सूर्योदय 6:04 सूर्यास्त 6:32

आज का तापमान

शिमला	15.5 न्यू	23.0 अधि
धर्मशाला	20.2 न्यू	29.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,781
निफ्टी	23,398

सोना 1,52,000 चांदी 2,29,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 28 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 139, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल में मिले पोर्न वीडियो

एजेंसी, बेंगलुरु। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच में कई पोर्न वीडियो मिलने की बात सामने आई है। शनिवार को हुई जांच के दौरान पेन ड्राइव में वेब सीरीज भी मिलने की जानकारी सामने आई। क्राइम ब्रांच ने 11 अगस्त को जेल में छापा मारकर रेवन्ना को कथित तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा था। इस दौरान मोबाइल, चार्जर, पेन ड्राइव और नोटबुक जब्त की गई थी। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। वह दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जेल नियमों के उल्लंघन पर उनकी सुविधाओं में कटौती, अलग सेल में रखने या नया मामला दर्ज किए जाने जैसी कार्रवाई हो सकती है।

डोडा में जंगल में संदिग्ध आतंकी का शव बरामद

एजेंसी, डोडा। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के पहाड़ी इलाकों से प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी का शव बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान डोडा की भद्रवाह घाटी को पड़ोसी उधमपुर और कठुआ जिलों से जोड़ने वाले सुदूर सियोजधार जंगल में शव मिला। उन्होंने बताया कि एसओजी डोडा, सेना की आरआर और सीआरपीएफ ने पहले एक संयुक्त अभियान में उसे मार गिराया था। शव के पास रात में मार करने योग्य एम 4 राइफल भी बरामद की गई है।

टीएमसी के बागी गुट से चुनाव आयोग ने मांगे और दस्तावेज

एजेंसी, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ऋजटीएमसी के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद जारी है। शनिवार को ऋतब्रत बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग के सामने मौखिक दलीलें दीं और सवालों के जवाब दिए। आयोग ने गुट से दिन खत्म होने से पहले अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को कहा। चुनाव आयोग की यह सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि यह 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले हो रही है, और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। बागी गुट उससे पहले सिंबल पर फैसला चाहता है। यदि 16 सितंबर तक चुनाव आयोग किसी एक गुट को मान्यता नहीं देता है, तो दोनों गुटों के उम्मीदवारों को 'इंडिपेंडेंट कैंडिडेट' के रूप में चुनाव लड़ना पड़ सकता है।

कनाडा में बीफ बनाने से रोकने पर भारतवंशी महिला गिरफ्तार

एजेंसी, ओटावा। कनाडा में बीफ बनाने से रोकने को लेकर भारतवंशी मकान मालकिन और किराएदार के बीच विवाद हो गया। किराएदार का आरोप है कि मकान मालकिन ने उसका खाना फेंक दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला उसकी इजाजत के बिना घर में घुसीं और ताले बदल दिए। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने भारतवंशी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। किराएदार के मुताबिक, वह अपने एक दोस्त के साथ गार्डन में बारबेक्यू पर खाना बना रहा था। इसी दौरान मकान मालकिन राज तिवान वहां पहुंचीं और उन्हें रोकने लगीं।

ब्रिक्स में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

चीन-रूस समेत सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत-ब्राजील की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन

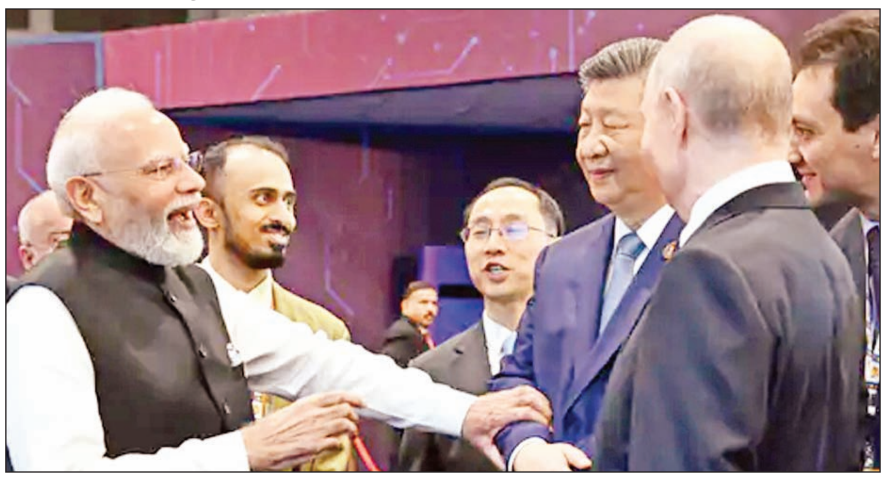

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शनिवार को 140 बिंदुओं वाला नई दिल्ली घोषणापत्र जारी किया गया। घोषणापत्र में वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने और मौजूदा आर्थिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप वैश्विक संस्थानों के पुनर्गठन पर जोर दिया गया। वीटो शक्ति रखने वाले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत भी बताई।

घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाए जाने वाले एकतरफा दंडात्मक आर्थिक उपायों और प्रतिबंधों की निंदा करते हुए इन्हें समाप्त करने की मांग की गई। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों का सबसे अधिक असर आम आबादी, गरीब और कमजोर वर्गों के मानवाधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास पर पड़ता है। व्यापार के क्षेत्र में गैर-टैरिफ बाधाओं और भेदभावपूर्ण कार्बन शुल्कों पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी वैश्विक व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

घोषणापत्र में वैश्विक विवादों के समाधान के लिए संवाद, मध्यस्थता और निवारक कूटनीति को महत्वपूर्ण साधन बताया गया। पश्चिम एशिया और गाजा की स्थिति पर चिंता जताते हुए युद्धविराम बनाए रखने, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई। फलस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र में उसकी पूर्ण सदस्यता के समर्थन को भी दोहराया गया।

आर्थिक क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने का स्वागत किया गया। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और नए विकास बैंक के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास के वित्तपोषण को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन, ग्लोबल साउथ की एआई तक समान पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला और अंतरिक्ष सहयोग को भी प्राथमिकता दी गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्वस्थ जीवनशैली के लिए ब्रिक्स मिशन (2026-2029)' शुरू करने तथा भारत के निमहांस के समन्वय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। चीन वर्ष 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

◆ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला पर बनी सहमति

ब्रिक्स ने की पहलगाम हमले की कड़ी निंदा

ब्रिक्स देशों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की विशेष रूप से निंदा की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंक के वित्तपोषण और उन्हें सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूह से नहीं जोड़ने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को खारिज करने की बात कही गई।

भारत में यूएई करेगा 1.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी आए हुए हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की।

इस बैठक का मुख्य फोकस भारत में यूएई की निवेश योजनाओं पर था। मोदी और शेख खालिद ने यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के ओडिशा में एक इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम प्रोजेक्ट में 11.5 अरब डॉलर का निवेश करने के ऐलान का स्वागत किया। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एल्युमीनियम निवेश होगा और ओडिशा को ग्लोबल एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करेगा।

सऊदी अरब ने हमले के बाद बंद की तेल पाइपलाइन

एजेंसी, रियाद। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के बाद अपनी ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। वीरवार को हुए ड्रोन हमले में पाइपलाइन से जुड़े पंपिंग स्टेशनों में आग लग गई और कुछ लोग घायल हुए थे। ईरान जंग के चलते होर्मुज बंद होने के बाद सऊदी इसी पाइपलाइन से रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल भेज रहा था। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाइपलाइन पर गुरुवार को कई हमले हुए थे। मंत्रालय की टीमें पाइपलाइन को सुरक्षित करने और नुकसान का पता लगाने में जुटी हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये हमले किसने किए। अब तक किसी भी देश या संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं हमले में पाइपलाइन के पास बने पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया गया। पंपिंग स्टेशन पाइपलाइन में तेल को आगे भेजने में मदद करते हैं। शुक्रवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में एक पंपिंग स्टेशन पर आग से काफी नुकसान दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन से काला धुआं निकलता दिखा।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर से जुड़े 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी

◆ कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला व सोपोर में की कार्रवाई

◆ सीमा पार आतंकी षड्यंत्र और स्थानीय मददगारों के नेटवर्क की जांच तेज

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सीमा पार आतंकी षड्यंत्र मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर में की गई। इस दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

एनआईए के अनुसार, छापेमारी का उद्देश्य लश्कर के संचालकों और उनके स्थानीय सहयोगियों के नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य जुटाना तथा घुसपैठ कर आए आतंकियों को ठिकाना, आवाजाही व रसद सहायता उपलब्ध कराने वालों की भूमिका का पता लगाना है। मामला श्रीनगर के जकूरा थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसे बाद में एनआईए ने अपने स्तर पर फिर दर्ज किया। जांच यूएपीए, शस्त्र अधिनियम व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चल रही है। एजेंसी के मुताबिक, जांच की शुरुआत 31 मार्च को एक स्थानीय सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी, जिसके कब्जे से हथगोला और कारतूस बरामद हुए थे। अब जांच में आतंकी नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन, संचार, हथियारों की आपूर्ति और स्थानीय मददगारों की भूमिका खंगाली जा रही है।

शराबबंदी करने का फैसला एकतरफा : बॉम्बे हाईकोर्ट

एजेंसी, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे प्रशासन को गणेश उत्सव के दौरान 10 दिन तक शराब पर रोक लगाने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति शराब का आदी है, उसे 10 दिनों तक शराब पीने को नहीं मिली, तो वे अस्पतालों में भीड़ लगा देंगे। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सिर्फ पुणे को चुनने के पीछे क्या तर्क है? हम ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। यह पुणे के निवासियों के लिए एक कलंक है।

उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर उत्साह में सड़कों पर निकलता है, तो सिर्फ इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगा। हालांकि, अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि शराब पी हो या नहीं, यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली स्थिति पैदा करता है तो उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना ही होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुणे प्रशासन ने गणेशोत्सव के दौरान 10 दिन की शराबबंदी घटाकर 2 दिन कर दी है। अब 14 सितंबर को शाम 4 बजे तक व 25 सितंबर को पूरे दिन शराब की बिक्री व सेवन पर रोक रहेगी।

नशा तस्करों की कमाई अब जनता की होगी : सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री ने नूरपुर में 3.27 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पर पुलिस को दी बधाई

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को अब अपनी आय का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नशा बेचकर आलीशान कोठियां, होटल और दुकानें बनाई गई हैं। जमीन और महंगी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह पैसा और सम्पत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे नशे के जाल में फंसाए गए हैं।

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगभग 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा।

उन्होंने कहा कि नशे की कमाई से बनाई गई संपत्ति वास्तव में उन परिवारों की कीमत पर अर्जित होती है, जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, भूमि, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशा माफिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है।

पुलिस जिला नूरपुर में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यह नशा माफिया के विरुद्ध प्रदेश सरकार की सख्त नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

नशे के पूरे नेटवर्क को करेंगे ध्वस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शेख सराय में बनेगी 151.81 करोड़ की फोरेंसिक लैब

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी, दो साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय में नया फोरेंसिक लैब बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए 151.81 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को परियोजना का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। शेख सराय में बनने वाली नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला लगभग 6,300 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाई जाएगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्गमीटर होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित यह भवन वैज्ञानिक जांच की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत फोरेंसिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।

नई आरएफएसएल रोहिणी स्थित मौजूदा एफएसएल की वैज्ञानिक सहायता को मजबूत करेगी। फोरेंसिक आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के साथ-साथ आपराधिक मुकदमों और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नई प्रयोगशाला से राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सहायता को भी मजबूती मिलेगी। इसका विशेष लाभ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को मिलेगा।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय एफएसएल के शुरू होने के बाद मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। नई सुविधा से साक्ष्य आधारित जांच को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, इससे आपराधिक मामलों को न्यायालयों में समय पर निपटाने में सहायता मिलेगी।

नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप आवश्यकता होगी पूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कारण आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच की मांग में काफी वृद्धि हुई है। नई क्षेत्रीय एफएसएल इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता करेगी। इससे आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर बनेंगे रिंग रोड: नायब सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों के बाहर रिंग रोड और नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। हिसार बाईपास, कुरुक्षेत्र बाईपास, नारनौल सिटी बाईपास, जींद बाईपास तथा सोहना-पलवल बाईपास के निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग से शहरी क्षेत्र में भीड़भाड कम करने के लिए शनिवार को मास्टर प्लान के तहत एडाप्शन आफ फाइनेंशियल माडल फार स्टेट कंट्रीब्यूशन को लेकर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिए गए। लोक निर्माण मंत्री रणबीर के साथ अधिकारियों की बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार बाईपास हिसार-राजगढ रोड एनएच 52 से हिसार देहली रोड तथा हिसार कैथल रोड से जोड़ने का कार्य करेगा। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र लाडवा बाईपास की भी डीपीआर तैयार कर ली गई है। जल्द ही इस परियोजना पर भी कार्य आरंभ किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत बाह्य रिंग रोड़ एवं नेशनल हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार के अनुसार पालिसी तैयार की जाएगी, ताकि शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक के दबाव कम करने के लिए बनाई जाने वाली सड़कों को अमलीजामा पहनाया जा सके। बैठक में केंद्र सरकार के लागत शेयर के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। नारनौल सिटी बाईपास बनाया जाएगा। लगभग 11 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को स्टेट हाईवे एनएच 148बी से जोड़ा जाएगा।

◆ हिसार, कुरुक्षेत्र, नारनौल, जींद बाईपास को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

चीन बोला-हम मतभेद सुलझाकर भारत के साथ काम करने को तैयार

एजेंसी, नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। गलवान झड़प के बाद यह जिनपिंग का यह पहला भारत दौरा है। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। जिनपिंग के भारत पहुंचने से पहले चीन ने स्टेटमेंट जारी कर कहा- हम भारत के साथ बातचीत बढ़ाकर और आपसी मतभेदों को सुलझाकर काम करने के लिए तैयार हैं।

जिनपिंग 11 अक्टूबर 2019 को भारत आए थे। 15 जून 2020 को गलवान झड़प हुई थी। इसके बाद भारत-चीन रिश्तों में तनाव बढ़ा, लेकिन कारोबार नहीं रुका। 2020-21 में चीन से भारत का आयात करीब 65 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 132 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। यानी गलवान झड़प के बाद चीन से आयात दोगुना हो गया है।

जिनपिंग के साथ चीन के दूसरे बड़े नेता भी पहुंचे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कै शी भी भारत आए हैं। वे चीन की सत्ता के दूसरे सबसे बड़े नेता में शामिल हैं। वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी सात सदस्यीय टीम (पॉलिटब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी) का हिस्सा हैं और पार्टी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर यानी सीधे तौर पर शी जिनपिंग के 'चीफ ऑफ स्टाफ' के रूप में काम करते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी चीन के पूरे प्रशासनिक सिस्टम, राष्ट्रीय सुरक्षा और पार्टी के प्रचार तंत्र (प्रोपोगैंडा और मीडिया) को कंट्रोल करने की है। इसके अलावा शी जिनपिंग की सुरक्षा, उनके दैनिक कामकाज और देश में पार्टी की विचारधारा को सख्ती से लागू करवाने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है।

कार्यक्रम 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध ज्ञान परंपरा का किया उल्लेख

हर युवा पढ़े 'एग्जाम वॉरियर्स', जीवन में उतारे इसके संदेश: योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' जरूर पढ़नी और उसके संदेशों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल स्कूली छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हर युवा और नागरिक के लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें गोमती पुस्तक महोत्सव-2026 का शुभारंभ करने के बाद युवाओं को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में पुस्तक महोत्सव की सफलता के बाद गोरखपुर में भी इसका आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पुस्तकों की बिक्री भी अधिक हुई। योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को लंबे समय तक संकुचित दायरे में सीमित करने के प्रयास हुए, जिसके दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र को भुगतने पड़े। उन्होंने नैमिषारण्य, काशी और मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश की समृद्ध ज्ञान परंपरा को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग ने गांव और शहर की दूरी कम की है। प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है और इनमें नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सरकारी स्कूलों में हुए बदलाव और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, महापुरुषों की आत्मकथाएं और वैज्ञानिकों के शोध से जुड़ी किताबें भी पढ़ें। साथ ही, हर युवा अपना 'बुक बैंक' बनाए और खाली समय में पढ़ने की आदत विकसित करे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारी, लेखक, प्रकाशक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

युवा किताब नहीं पढ़ता, यह कहना अन्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना कि युवा पुस्तकों से दूर हो गया या सोशल मीडिया पर अपना समय खराब कर रहा, पूरी तरह सही नहीं। ऐसा कहना युवा के साथ अन्याय होगा। जरूरत पुस्तकों को उसके पास पहुंचाने की व्यवस्था करने की है। जब पहली बार युवराज मलिक ने लखनऊ में पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, तब मैंने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से चर्चा की। इसे प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके बाद लखनऊ में पुस्तक महोत्सव शुरू हुआ। इसका जब अच्छा परिणाम मिला तो मैंने गोरखपुर में भी पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया। वहां लखनऊ से भी ज्यादा लोग पहुंचे और अधिक पुस्तकों की बिक्री हुई। इससे यह धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई कि आज का युवा पुस्तक नहीं पढ़ता।

बतीउड़ा बिशु मेले में ठोडा खेल और संस्कृति को मिली नई पहचान

ठोडा मुकाबले, लोक प्रस्तुतियां और बच्चों-महिला मंडलों की प्रतियोगिताओं से सजेगा दो दिवसीय मेला

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायत धमानदरी के बतीउड़ा में आयोजित दो दिवसीय पारंपरिक रिहाली (बिशु) मेले का शुभारंभ किया। पंचायत प्रतिनिधियों और मेला समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मेला मैदान पहुंचने पर मुख्य अतिथि का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

मेले के दौरान ठोडा दल तुहनाल बलसन और ठोडा दल छिब्बर के बीच पारंपरिक ठोडा खेल का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों, युवक मंडलों और महिला मंडलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे।

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पारंपरिक मेले केवल मनोरंजन के आयोजन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मेल-जोल बढ़ाने और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन स्थानीय लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने के साथ सामुदायिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने रिहाली (बिशु) मेले को क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा कि ठोडा खेल एक समय लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन क्षेत्रवासियों के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया गया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि पारंपरिक खेलों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है।

ठियोग-कसुम्पटी में विकास को गति : अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ठियोग और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्रों में समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से ग्रामीण सड़कों को पक्का करने, गांवों को सड़क और पेयजल सुविधा से जोड़ने तथा कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में अब तक 130 सड़कों की एफआरए सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। कई सड़कों का निर्माण जारी है, जबकि कुछ का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने भेखलटी-बतलाड संपर्क सड़क को जल्द चौड़ा और पक्का करने की बात कही।

मंत्री ने मुख्य मार्ग से बतीउड़ा संपर्क सड़क के सुधार के लिए ग्रामीणों से भूमि की गिफ्ट डीड शीघ्र उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने धमानदरी पंचायत भवन के अधूरे निर्माण को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि 31 मार्च 2027 से पहले भवन का शुभारंभ कर दिया जाएगा। महिला मंडल और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पांच-पांच हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

विधायक ने मेला मैदान के लिए दो लाख दिए : ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि परिसीमन के बाद धमानदरी पंचायत का कुछ क्षेत्र कसुम्पटी और कुछ ठियोग विधानसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में रिहाली-बिशु मेला दोनों क्षेत्रों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द पंचायतों का दौरा करने की बात कही।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर धमानदरी में को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा खोली गई है। विधायक ने मेला मैदान के विस्तार के लिए विधायक निधि से दो लाख रुपये तथा मेले के आयोजन के लिए मेला समिति को 25 हजार रुपये देने की घोषणा की।

शिमला में जाम से मुक्ति की तैयारी, सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने कार्ट रोड और सर्कुलर रोड के संकरे हिस्सों को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 20,444.10 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर यातायात को सुगम बनाना और संकरी सड़कों के कारण लगने वाले जाम से राहत दिलाना है। अधिसूचना के अनुसार, मुख्य जिला मार्ग-66 यानी कार्ट रोड पर टूटीकंडी से संजौली वाया छोटा शिमला और मुख्य जिला मार्ग-67 पर विक्ट्री टनल से ढली चौक वाया लक्कड़ बाजार के संकरे हिस्सों को चौड़ा किया जाएगा। छोटा शिमला स्थित तिब्बती स्कूल के पास नया फुटपाथ बनाने की योजना भी इसमें शामिल है।

इन क्षेत्रों में होगा भूमि अधिग्रहण : भूमि अधिग्रहण की जद में चौड़ा मैदान, कृष्णानगर, छोटा शिमला, बेमलोई, अप्पर कैथू, ताराहॉल, कालीबाड़ी, लक्कड़ बाजार, शांकली, संजौली चौक और यूएस क्लब समेत कई प्रमुख क्षेत्र आएंगे। विभाग ने खसरा नंबर के साथ प्रभावित दुकानों, मकानों, सीढ़ियों, रास्तों और खाली जमीनों का विवरण भी जारी किया है।

करीब 200 परिवार होंगे प्रभावित : परियोजना के कारण करीब 200 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) अध्ययन में भी इसका उल्लेख किया गया है। सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला को सौंपी है। विशेषज्ञ समूह ने परियोजना को तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा जनहित में आवश्यक माना है।

60 दिन में दर्ज करा सकेंगे आपत्ति : भूमि मालिकों और अन्य हितबद्ध लोगों को अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता (दक्षिण क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विंटरफील्ड, शिमला-3 के कार्यालय में आपत्ति दी जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

शिमला में सब्जियों के भाव चढ़े, प्याज ने पांच दिन से बढ़ाई रसोई की चिंता

अनीश सूद, भारतेंदु संवाददाता, शिमला । शिमला सब्जी मंडी में पिछले पांच दिनों से सब्जियों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी प्याज के लगातार महंगे बने रहने से है। मंडी में प्याज 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और पिछले पांच दिनों से इसके भाव में कोई कमी नहीं आई है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है।

प्याज के अलावा मटर और फूलगोभी भी महंगी सब्जियों में शामिल हैं। मटर का भाव 100 रुपये प्रति किलो और फूलगोभी 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। सब्जियों के लगातार ऊंचे दामों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

शिमला मंडी में शुक्रवार को टमाटर 40 रुपये, आलू 20 रुपये और भिंडी 40 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकी। तोरी, कद्दू, घिया, पत्ता गोभी और करेला के भाव भी 40 रुपये प्रति किलो रहे। गाजर 50 रुपये, फ्रास बीन 60 रुपये, शिमला मिर्च 60 रुपये और बैंगन 60 रुपये प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध रहे।

इसके अलावा अरबी 40 रुपये, लोबिया गट्ठी 20 रुपये, मूली 30 रुपये, खीरा 50 रुपये और चुकंदर 60 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिका। सब्जियों के इन भावों में प्याज, मटर और फूलगोभी की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक चिंता का कारण बनी हुई हैं।

> **प्याज** के दाम लगातार पांच दिनों से 70 रुपये प्रति किलो बने हुए हैं। उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि मंडी में आवक बढ़ने के साथ कीमतों में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्याज रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा होने के कारण इसके बढ़े भाव का असर सीधे घरेलू रसोई पर पड़ता है। मंडी में कई सब्जियों के दाम 40 से 60 रुपये प्रति किलो के बीच बने हुए हैं। वहीं मटर 100 रुपये और फूलगोभी 80 रुपये किलो बिकने से मौसमी सब्जियों की खरीद भी महंगी हो गई है।

विधायकों की गाड़ियों को मिलेगी नीली झंडी एक सप्ताह का इंतजार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विधायकों को अपने वाहनों पर विशिष्ट नीली झंडी लगाने के लिए अभी करीब एक सप्ताह और इंतजार करना होगा। विधानसभा की ओर से तैयार करवाई जा रही यह झंडी फिलहाल निर्माण प्रक्रिया में है। इसके तैयार होने के बाद सभी विधायकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तब तक विधायक अपने वाहनों पर एमएलए लिखवाकर काम चला सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मानसून सत्र के अंतिम दिन तीन सितंबर को सदन में विधायकों को विशिष्ट नीली झंडी उपलब्ध करवाने की जानकारी दी थी। लालबत्ती और फ्लैशर की व्यवस्था समाप्त होने के बाद विधायकों के वाहनों की अलग पहचान नहीं हो पा रही थी। ऐसे में विधायक लंबे समय से वाहनों के लिए अलग पहचान चिह्न की मांग कर रहे थे।

ब्यास ड्रेजिंग पर सुधीर शर्मा ने सरकार को घेरा

ड्रेजिंग कार्य में नियमों की अनदेखी और सरकारी राजस्व के नुकसान पर उठे गंभीर सवाल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कुल्लू में ब्यास नदी में ड्रेजिंग के नाम पर किए जा रहे कार्य को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन से जुड़े कार्य को खनन विभाग के बजाय वन विभाग के माध्यम से करवाए जाने से प्रदेश सरकार को राजस्व और रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि इस मामले में बेस वैल्यू प्राइस सरकार के पास जमा नहीं करवाए जाने और आवश्यक बैंक गारंटी नहीं लिए जाने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि यदि ये वित्तीय औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं तो कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति किस आधार पर दी गई और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था।

उन्होंने वन विभाग के माध्यम से माइनिंग कार्य करवाने के लिए कैबिनेट से कथित तौर पर जल्दबाजी में वाया सर्कुलेशन मंजूरी लिए जाने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकार को इस निर्णय से संबंधित पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि नियमित कैबिनेट बैठक के बजाय सर्कुलेशन के माध्यम से फैसला लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

भाजपा विधायक ने दावा किया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार वन विभाग माइनिंग करवाने के लिए अधिकृत एजेंसी नहीं है। उन्होंने सरकार से संबंधित वैधानिक प्रावधान, अनुमति और स्वीकृतियों को सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि किसी विशेष अनुमति के तहत यह कार्य किया गया है तो उसके दस्तावेज भी सामने आने चाहिए।

सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में कुल्लू के एक प्रभावशाली नेता की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि खनन विभाग से कार्य लेकर वन विभाग को सौंपने का निर्णय किसकी सिफारिश पर लिया गया।

उन्होंने एक कांग्रेस नेत्री को कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये दिए जाने की चर्चा का भी उल्लेख किया और कहा कि इस दावे की सच्चाई स्वतंत्र जांच से ही सामने आ सकती है। उन्होंने मांग की कि कथित लेन-देन से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। यदि आरोप गलत हैं तो जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ब्यास नदी से कितनी खनिज सामग्री निकाली गई, उसका बेस वैल्यू प्राइस कितना था, कितनी रॉयल्टी बनती थी, कितनी राशि जमा हुई और बैंक गारंटी क्यों नहीं ली गई।

नशा तस्करों की जमीनों पर पुलिस का शिकंजा, डिमार्केशन के बाद होगी जब्ती

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए शिमला पुलिस ने अब उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस नशा तस्करी से कमाई गई जमीनों की डिमार्केशन करवाकर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। इसके लिए खंडस्तरीय एनकॉर्ड बैठकों में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच रणनीति तैयार की गई है।

हाल ही में एसडीपीओ चौपाल की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय चौपाल में उपमंडल स्तरीय एनकॉर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम चौपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें नशा विरोधी अभियान, कानूनी जागरूकता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। एसडीपीओ रोहड़ू की ओर से भी एसडीएम कार्यालय रोहड़ू में एनकॉर्ड बैठक आयोजित की गई। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ नशा विरोधी अभियान तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा टिक्कर, रोहड़ू और चिड़गांव के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमांकन से जुड़े मामलों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

पांगी की शौर पंचायत का होगा कायाकल्प, खेल मैदान, लाइब्रेरी, जिम से हेलीपैड तक मिलेंगी सुविधाएं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ग्राम पंचायत शौर के समग्र विकास के लिए राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने पंचायत को गोद लेने की घोषणा की। शनिवार को आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने भाग लेकर सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और संतुलित विकास को गति देने का संकल्प लिया गया।

डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि पंचायत को गोद लेने का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार करना नहीं, बल्कि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए दीर्घकालिक और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पंचायत में खेल मैदान, जिम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल, सोलर लाइट, श्मशान घाट और हेलीपैड जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन मिल सके।

सांसद ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्थानीय जरूरतों और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

कार्यक्रम में पांगी-भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज भी मौजूद रहे। उन्होंने पंचायत को गोद लेने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार को गति मिलेगी। भाजपा प्रदेश सचिव एवं पांगी निवासी तिलक राज शर्मा ने भी पहल के लिए सांसद का आभार जताया।

27 साल बाद लॉटरी पर दांव कंपनियों ने दिखाई बेरुखी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारी कर्ज और आर्थिक चुनौतियों के बीच अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए हिमाचल सरकार की 27 साल बाद लॉटरी शुरू करने की योजना को शुरुआती झटका लगा है। राष्ट्रीय स्तर की लॉटरी वितरक कंपनियों ने पहली निविदा प्रक्रिया में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते राज्य लॉटरी विभाग ने निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है। सरकार को लॉटरी के माध्यम से सालाना करीब 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसी उद्देश्य से विभाग ने नामी लॉटरी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। विभाग को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में कंपनियां बोली लगाएंगी, लेकिन निर्धारित समयसीमा तक पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब कंपनियों को निविदा जमा करने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। विभाग को उम्मीद है कि बढ़ी हुई समयसीमा में कंपनियां प्रक्रिया में भाग लेंगी।

शिमला में घटेगा स्मार्ट पार्किंग शुल्क , वाहन चालकों को राहत

सड़क किनारे खड़े वाहनों पर लगेगा अंकुश, व्यवस्थित पार्किंग को मिलेगा बढ़ावा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग की समस्या कम करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तैयार की गई पार्किंग के शुल्क में कटौती की जाएगी। नगर निगम ने इन पार्किंग स्थलों की दरें कम करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय वाहन चालकों के साथ शिमला आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में चार प्रमुख पार्किंग तैयार की गई हैं। इनमें एसीपी परिसर कसुम्पटी में करीब 350 वाहनों, ऑकलैंड में 145, टूटीकंडी में 90 और संजौली में 105 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है। इन पार्किंग स्थलों में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में वाहन पार्क नहीं हो रहे थे।

अधिक शुल्क के कारण कम हो रहा था इस्तेमाल : स्मार्ट सिटी पार्किंग में निर्धारित शुल्क सामान्य पार्किंग की तुलना में अधिक होने के कारण वाहन चालक इनका कम इस्तेमाल कर रहे थे। लोग सड़क किनारे वाहन खड़ा करना अधिक सुविधाजनक और सस्ता समझ रहे थे।

इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी पैदा होती है।

पहले निर्धारित दरों के अनुसार कार को दो घंटे तक पार्क करने के लिए 50 रुपये, चार घंटे तक 75 रुपये, छह घंटे तक 100 रुपये, 12 घंटे तक 150 रुपये और 24 घंटे तक 200 रुपये शुल्क देना पड़ता था। बड़े वाहनों के लिए शुल्क इससे अधिक निर्धारित था। नगर निगम का उद्देश्य शुल्क को आम लोगों की पहुंच में लाकर स्मार्ट सिटी पार्किंग का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि शुल्क कम होने के बाद वाहन चालक सड़क किनारे पार्किंग करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करेंगे।

विरोध 15 सितंबर को होगा सचिवालय मार्च, समिति एक लाख हस्ताक्षर सरकार को सौंपेगी

केएनएच शिफ्टिंग के विरोध में महिला समिति का संघर्ष तेज

अनीश सूद, भारतेंदु संवाददाता, शिमला। कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) के गायनी विभाग को आईजीएमसी में शिफ्ट किए जाने के फैसले के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आंदोलन तेज करने का एलान किया है। समिति ने सरकार के निर्णय को महिलाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। समिति ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल महिलाओं के स्वास्थ्य और माता एवं शिशु चिकित्सा के लिए समर्पित प्रमुख संस्थान है। ऐसे में इसके विभागों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के बजाय यहां चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए।

शनिवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन की राज्य अध्यक्ष रंजना जरेट, राज्य महासचिव फालमा चौहान, राज्य कोषाध्यक्ष सुनिधि ठाकुर, शिमला जिला कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य सहसचिव रमा रावत तथा जिला कमेटी सदस्य पलक शांडिल ने इस मुद्दे पर संगठन का पक्ष रखा।

महिला समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने कमला नेहरू अस्पताल के गायनी विभाग को आईजीएमसी में शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिससे महिलाओं और अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के सामने कई समस्याएं पैदा

हो सकती हैं। समिति के अनुसार, केएनएच में ओबीजी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा, डिग्री और अध्यापकों की व्यवस्था भी इसी विभाग से जुड़ी हुई है। समिति ने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह विभाग को अलग करना उचित नहीं है।

समिति ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों और चिकित्सकों को दी गई विस्तारित सेवाओं के कथित प्रभाव में कमला नेहरू अस्पताल की गायनी ओपीडी को छुट्टी वाले दिन रातोंरात आईजीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया। समिति ने कहा कि सरकार इस निर्णय के पीछे रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाओं का तर्क दे रही है, लेकिन संगठन को इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर संदेह है।

केएनएच में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की मांग

महिला समिति ने मांग की कि केएनएच को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और गायनी ओपीडी को आईजीएमसी से वापस कमला नेहरू अस्पताल लाया जाए। इसके साथ ही अस्पताल में तीसरे फेज के भवन का निर्माण भी जल्द शुरू करने की मांग की गई है। समिति के अनुसार प्रस्तावित भवन में महिलाओं के लिए आईवीएफ सेंटर, रोबोटिक सर्जरी सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए अस्पताल को कमजोर करने के बजाय इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

डोरा ने निभाई पांच साल ड्यूटी अब अपनों के बीच कटेगी जिंदगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस में करीब पांच वर्षों तक सेवाएं देने वाली लैब्राडोर डोरा अब पुलिस ड्यूटी से सेवानिवृत्त होकर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगी। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन स्क्वाड का हिस्सा रही डोरा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर किया गया है। अब पुलिस विभाग उसके लिए ऐसे परिवार की तलाश में है, जहां उसे प्यार, देखभाल और सुरक्षित माहौल मिल सके।

◆ स्वास्थ्य कारणों से छोड़ी ड्यूटी

डोरा वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश पुलिस में शामिल हुई थी। सेवा के दौरान उसने कई महत्वपूर्ण सैनिटाइजेशन और सुरक्षा अभियानों में पुलिस टीम के साथ काम किया। महत्वपूर्ण आयोजनों और वीआईपी कार्यक्रमों में संभावित विस्फोटक खतरों की पहचान करने में भी उसने अहम भूमिका निभाई। पिछले कुछ समय से डोरा एक पुरानी बीमारी से जूझ रही है। इसका असर उसकी चलने-फिरने की क्षमता पर पड़ा है। पशु चिकित्सकों की सलाह के बाद पुलिस विभाग ने उसे नियमित ड्यूटी से हटाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण अब वह पहले की तरह लंबे समय तक चलने वाली और शारीरिक रूप से कठिन ड्यूटी करने में सक्षम नहीं है।

रोहड़ू में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी मोड पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पुलिस थाना रोहड़ू के अंतर्गत 10 सितंबर को अप्पर बाजार रोहड़ू में पारिवारिक अंतर्कलह के कारण पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया ।बाद में पति ने स्वयं को भी चाकू मार दिया और 11 सितंबर को सुबह आईजीएमसी में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि पत्नी का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। पुलिस ने धारा 109 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उक्त मामले की शिकायतकर्ता निर्मला जो पीड़ित रचना की बहन है आरोपित बीरबल की पत्नी है।

उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 10 सितंबर को दोपहर 1.20 बजे सीडीपीओ कार्यालय रोहड़ू से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।

घटनास्थल पर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को शौचालय के अंदर चाकू लगने से घायल अवस्था में पाया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते बीरबल द्वारा अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया गया और उसके बाद उसने स्वयं को भी चाकू से घायल किया।

पति पत्नी दोनों को घायल अवस्था में नागरिक

◆ चाकूबाजी में दोनों गंभीर घायल, आइजीएमसी में इलाज के दौरान पति ने तोड़ा दम

अस्पताल रोहड़ू से उपचार के लिए आइजीएमसी शिमला रेफर किया गया। 11 सितंबर को सुबह चाकू मारने वाले व्यक्ति बीरबल की उपचार के दौरान आइजीएमसी में मृत्यु हो गई है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं उसकी पत्नी का आइजीएमसी में उपचार चल रहा है जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस द्वारा उसकी गहन जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राजराजेश्वरी 2026 की बड़ीजात का हिस्सा नहीं

उदित नैनवाल, जिला चमोली। मां नंदा की लोकपरंपराओं और धार्मिक यात्राओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही सूचनाओं के बीच राजराजेश्वरी (बधाण की नंदा) को वर्ष 2026 की बड़ीजात/राजजात का हिस्सा बताए जाने पर आपत्ति जताई गई है। जारी संदेश में इसे भ्रामक बताते हुए लोगों से तथ्यहीन जानकारी का प्रचार-प्रसार न करने की अपील की गई है। संदेश में स्पष्ट किया गया कि राजराजेश्वरी वर्ष 2026 की बड़ीजात/राजजात का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए राजजात से जुड़ी जानकारी साझा करते समय प्रमाणित तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करना आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न फैले। मां नंदा से जुड़ी लोकपरंपराएं उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इनसे संबंधित सूचनाओं को बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से परंपराओं की वास्तविकता प्रभावित हो सकती है। लोगों से अपील की गई कि बड़ीजात/राजजात के संबंध में केवल प्रमाणित और तथ्यपूर्ण जानकारी ही साझा करें।

सेवा संकल्प अभियान मोदी के विकसित भारत-2047 का संकल्प : सतपाल महाराज

कहा- सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को व्यापक अभियान चलाएगा उत्तराखंड

अनिल थपलियाल

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में प्रस्तावित सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड में भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वृहद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की तैयारियों को लेकर प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को सुभाष रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, गैस वितरण केंद्रों, राशन की दुकानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और गंगा तटों पर जनभागीदारी से दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज।

इन कार्यक्रमों के फोटो एवं वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की यात्रा और सेवा-विकास के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ युवाओं को भी सेवा कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। महाराज ने अधिकारियों को रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और गरीब कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर 'सेवा सेतु', प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग में पंजीकृत दलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर मंचन और जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल जन्मदिन से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सेवा और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनमानस तक पहुंचाने का व्यापक प्रयास है। उन्होंने प्रत्येक जिले में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम प्रधानों, सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।

कई अधिकारी मौजूद रहे

बैठक में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, अपर निदेशक पूनम चंद, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडे, लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता बी.के. तिवारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश सिंह परमार, ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विभू रावत और संस्कृति विभाग के अपर निदेशक शेखर पटवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रुद्रप्रयाग में शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

सेवा कार्यों से जनभागीदारी बढ़ाएगी रुद्रप्रयाग भाजपा

अनिल थपलियाल

रुद्रप्रयाग। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सेवा, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हुए विकसित भारत-2047 के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है।

अभियान के तहत बूथ स्तर पर लाभार्थी परिवारों के घर दीप प्रज्वलित कर आभार जताया जाएगा। विद्यालयों में चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवा कार्यों की जानकारी दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम में नागरिक रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वास्थ्य जांच और नशामुक्ति सहित 25 सेवा गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

भानियावाला में खुलेगा पहाड़ी थीम वाला नया शोरूम

अनिल थपलियाल, देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक ज्वेलरी को आधुनिक डिजाइनों के साथ नई पहचान देने के उद्देश्य से अलंकार ज्वेलर्स 14 सितंबर को भानियावाला में अपना दूसरा शोरूम शुरू करेगा। ऋषिकेश में 14 वर्षों से अधिक समय से ग्राहकों का विश्वास जीतने के बाद कंपनी ने भानियावाला में विस्तार किया है। नए शोरूम को पूरी तरह पहाड़ी थीम पर तैयार किया गया है। यहां गढ़वाली और कुमाऊंनी पारंपरिक आभूषणों की विशेष रेंज उपलब्ध होगी। शुभारंभ से पहले 11 पंडितों ने पूजा-अर्चना और हवन कर शोरूम की समृद्धि की कामना की। 13 सितंबर को ग्रैंड प्रीव्यू आयोजित किया जाएगा, जबकि 14 सितंबर को भव्य उद्घाटन होगा। इसमें स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉ. विजय धस्माना मुख्य अतिथि होंगे। शोरूम में सोने, चांदी, हीरे और कुंदन के आभूषणों के साथ पहाड़ी नथ, पौंची और तिमनिया जैसे पारंपरिक डिजाइन भी उपलब्ध रहेंगे।

न्यूज ब्रीफ

ऊखीमठ में 14 बोतल अवैध शराब के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार

अनिल थपलियाल, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ। अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली ऊखीमठ पुलिस ने 12 सितंबर को चेकिंग के दौरान एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपी की पहचान दान बहादुर उर्फ प्रेम, उम्र 20 वर्ष, निवासी कालीकोट, नेपाल, हाल निवासी सीतापुर, सोनप्रयाग के रूप में हुई। पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए कुलदीप सिंह

अनिल थपलियाल, देहरादून। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के चुनाव में उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संरक्षक कुलदीप सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनके निर्वाचन से विश्वविद्यालय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण रौतेला और महामंत्री प्रशांत मेहता ने उन्हें बधाई दी। पदाधिकारियों ने कहा कि कुलदीप सिंह लंबे समय से कर्मचारियों के हितों, अधिकारों और सेवा संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय कर्मचारी संघों ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और नेतृत्व से राष्ट्रीय महासंघ को मजबूती मिलेगी। कुलदीप सिंह ने निर्वाचन पर सभी कर्मचारी प्रतिनिधियों और सहयोगियों का आभार जताते हुए कर्मचारियों के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने की बात कही।

16 साल बाद हरिद्वार स्थानांतरित हुए शिक्षक प्रकाश चंद्र सती

उदित नैनवाल

जिला चमोली, नारायणबगड़। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायणबगड़ में 16 वर्षों तक सेवाएं देने वाले सहायक अध्यापक प्रकाश चंद्र सती का हरिद्वार के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालियर में स्थानांतरण होने पर विद्यालय परिवार ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान शिक्षकों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए शुभकामनाएं दीं। प्रकाश चंद्र सती ने शिक्षण कार्य के साथ विद्यार्थियों को एनसीसी प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देशसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन से कई विद्यार्थियों को एनसीसी के माध्यम से करियर की दिशा तय करने में मदद मिली। प्रधानाचार्य डॉ. जीएस नेगी ने उनके योगदान की सराहना की। समारोह में उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

एसएसपी दून के नेतृत्व में पुलिस का एक और शानदार खुलासा

पूर्व प्रेमिका ने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए दी पांच लाख की सुपारी, गोलीकांड में तीन गिरफ्तार

विकास बलोनी

देहरादून। देहरादून में बैंककर्मी को गोली मारने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घायल युवक सत्यम कुमार की पूर्व प्रेमिका मालिया रहमान ने उसे रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी थी। मालिया ने अपने परिचित मोहित के माध्यम से अपराधी अंकित चौहान से संपर्क किया और सत्यम की हत्या के लिए पांच लाख रुपये देने की बात कही। उसने एक लाख 20 हजार रुपये अग्रिम भी दिए थे। आठ सितंबर को अंकित अपने साथी अंकुर के साथ बड़ोवाला क्षेत्र में पहुंचा और सत्यम की स्कूटी को रोककर उस पर गोली चला दी। हमले में सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 11 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान अंकित को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि अंकुर फरार हो गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता मालिया रहमान और उसके साथी मोहित को देर रात आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तमंचा, खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस फरार अंकुर की तलाश में दबिश दे रही है।

एसएसपी, देहरादून

सीताराम येचुरी की दूसरी पुण्यतिथि पर देहरादून में जुटे वामपंथी नेता और कार्यकर्ता

अनिल थपलियाल

देहरादून। नगर निगम टाउन हॉल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दिवंगत महासचिव एवं वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी की दूसरी पुण्यतिथि पर स्मृति सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और येचुरी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड राजेंद्र सिंह नेगी ने की, जबकि संचालन राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित ने किया। मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात ने सीताराम येचुरी के जीवन, संघर्ष और लोकतांत्रिक एवं सामाजिक आंदोलनों में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि येचुरी ने जीवनभर किसान-मजदूरों, वंचित वर्गों, दलितों, आदिवासियों और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संसद से सड़क तक उन्होंने जनता की आवाज उठाई और धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वृंदा करात ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बताया। उन्होंने जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों के नाम हटाए जाने के मुद्दे को भी उठाया। कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की बुनियादी ताकत है और मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है।

कांग्रेस ने धामी सरकार पर 7000 बीघा सरकारी जमीन कॉरपोरेट्स को देने का आरोप लगाया

अनिल थपलियाल, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार पर सरकारी जमीन को कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार करीब 7000 बीघा सरकारी भूमि को 90 वर्ष तक की लीज पर देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने व्यावसायिक उपयोग वाली जमीन का लीज किराया कृषि भूमि के सर्किल रेट के आधार पर तय करने पर सवाल उठाया और इसे सरकारी खजाने के नुकसान का कारण बताया।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की भूमि निजी संस्था को देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

चार्जशीट कमेटी सदस्य मनोज रावत ने अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन रद्द करने और संबंधित कंपनियों की पात्रता पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूरे मामले में पारदर्शिता और जांच की मांग की।

सामवेदी उपाकर्म 13 सितंबर को, सुबह से दोपहर तक रहेगा पुण्यकाल

अनिल थपलियाल, अल्मोड़ा। सामवेद के अनुयायियों के लिए इस वर्ष सामवेदी उपाकर्म विशेष और शुभ रहने वाला है। 13 सितंबर को हस्त नक्षत्र और हरतालिका तीज का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी के अनुसार, इस दिन सुबह 7:09 बजे तक द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि का प्रवेश होगा। हस्त नक्षत्र दोपहर 1:07 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में सुबह 7:30 बजे से मध्याह्न तक उपाकर्म और ऋषितर्पण के लिए सबसे उत्तम पुण्यकाल माना गया है। सामवेद के अनुयायी और विशेषकर तिवारी समुदाय के लोग हरतालिका तीज पर नूतन यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा निभाते हैं। श्रद्धालु नदियों, तालाबों और देवस्थानों पर एकत्र होकर वैदिक विधि से ऋषितर्पण करेंगे।

दून विश्वविद्यालय और सिनवेस्टाव के बीच एमओयू भारत-मेक्सिको शोध सहयोग को मिलेगी नई मजबूती

अनिल थपलियाल

देहरादून। दून विश्वविद्यालय और मेक्सिको के सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवांस्ड स्टडीज (सिनवेस्टाव) के बीच शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल एवं दून विश्वविद्यालय के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मौजूदगी में दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों ने समझौते को आगे बढ़ाया। वर्ष 1961 में स्थापित सिनवेस्टाव प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानविकी के क्षेत्र में उन्नत शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है।

◆ दून विश्वविद्यालय-सिनवेस्टाव समझौते से संयुक्त शोध और शैक्षणिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत और मेक्सिको के बीच बढ़ते शैक्षणिक और वैज्ञानिक संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने एमओयू के बाद जल्द ठोस कार्यक्रम शुरू करने और परिणाम आधारित सहयोग विकसित करने पर जोर दिया। दोनों संस्थानों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर संयुक्त परियोजनाएं तैयार करने के लिए कार्य समूह गठित करने की अपेक्षा जताई गई।

केदारनाथ पैदल मार्ग फिर बंद, चीरबासा हैलीपैड के पास आया मलबा-पत्थर

अनिल थपलियाल, रुद्रप्रयाग। गत रात्रि हुई वर्षा के कारण चीरबासा हैलीपैड के समीप श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुन: मलबा एवं पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सूचना प्राप्त होते ही डीडीओसी द्वारा तत्काल जेई, डीडीएमए गुप्तकाशी को अवगत कराया गया। वर्तमान में क्षेत्र में वर्षा जारी होने के कारण मार्ग से मलबा एवं पत्थर हटाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। मौसम सामान्य होने के उपरान्त मार्ग को सुचारु करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्री केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को फिलहाल सोनप्रयाग एवं गौरीकुण्ड में रोक दिया गया है।

◆ लगातार बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बढ़ी मुश्किल

बिजनौर में हॉलमार्किंग अनिवार्य बीआईएस ने दी अहम जानकारी

अनिल थपलियाल

बिजनौर अब अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों में शामिल हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से ऋद्धि रॉयल कैसल में ज्वैलर्स के लिए हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 80 ज्वैलर्स और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीआईएस अधिकारियों ने ज्वैलर्स को नवीन प्रावधानों, एचयूआईडी और उपभोक्ता हितों से जुड़ी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी संबंधित ज्वैलर्स को तत्काल बीआईएस ज्वैलर पंजीकरण कराना चाहिए। यह पंजीकरण निशुल्क है और इसकी वैधता आजीवन है।

ज्वैलर्स की सुविधा के लिए बिजनौर में विशेष पंजीकरण शिविर भी लगाया जाएगा। बीआईएस के निदेशक एवं प्रमुख हेमंत बी. आडे ने बताया कि बीआईएस केयर ऐप पर हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की फोटो और वजन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ता आभूषण की जानकारी सत्यापित कर सकेंगे। वहीं, हॉलमार्क चांदी के आभूषणों के लिए छह अंकों की एचयूआईडी व्यवस्था लागू है।

लोकसंस्कृति

महाराज ने गढ़वाली फिल्म 'बीरा' का ट्रेलर, म्यूजिक और पोस्टर किया लांच, कहा-

'बीरा' में दिखेगी पहाड़ की मिट्टी और रिश्तों की गर्माहट : सतपाल महाराज

अनिल थपलियाल

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को एक स्थानीय होटल में बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी गढ़वाली फीचर फिल्म 'बीरा' का ट्रेलर, म्यूजिक और पोस्टर लांच किया। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म निर्माता धीरज पप्पू सिंह, निर्देशक देबू रावत, मुख्य कलाकारों और फिल्म की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को देश-दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है।

सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता फिल्म निर्माताओं के लिए किसी प्राकृतिक स्टूडियो से कम नहीं है। प्रदेश में हिमालय की ऊंची चोटियां, घने और हरे-भरे जंगल, कल-कल करती नदियां, झीलें, खूबसूरत घाटियां और पहाड़ी गांव मौजूद हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराएं, लोकगीत, लोकनृत्य और विशिष्ट जीवनशैली भी फिल्मों के लिए मजबूत विषय उपलब्ध कराती हैं। राज्य सरकार प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक और सुविधाजनक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य दृश्य-श्रव्य परियोजनाओं की शूटिंग हो। इससे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही फिल्म निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय युवा, कलाकार, तकनीशियन, होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग और छोटे उद्यमी फिल्म निर्माण से जुड़कर अपनी आजीविका के नए साधन विकसित कर सकते हैं।

महाराज ने कहा कि गढ़वाली फिल्में उत्तराखंड की लोकभाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्थानीय भाषा में बनने वाली फिल्मों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और पहाड़ के सामाजिक जीवन से परिचित कराया जा सकता है।

'बीरा' में दिखी पहाड़ की जिंदगी

उन्होंने 'बीरा' फिल्म की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहाड़ के सरल जीवन और बदलते समय के बीच खड़े लोगों की भावनाओं को सामने लाती है। फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो अपने सपनों, रिश्तों और अपनी जड़ों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। बदलते सामाजिक परिवेश के बीच पहाड़ के लोगों की भावनाएं, संघर्ष और अपनी मिट्टी से जुड़ाव फिल्म की कहानी को विशेष बनाते हैं। उन्होंने कहा कि 'बीरा' पहाड़ की मिट्टी, रिश्तों की गर्माहट और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावना को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली सिनेमाई यात्रा है।

चंडीगढ़ के 29 स्केटर विश्व स्केट खेलों में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

परागवे की राजधानी असुनसियोन में दो से 18 अक्टूबर तक होने वाले पांचवें विश्व स्केट खेलों में चंडीगढ़ के 29 स्केटर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों में 15 बेटियां शामिल हैं। ये खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में रोलर हॉकी और इनलाइन हॉकी स्पर्धाओं में देश के लिए पदक की दावेदारी पेश करेंगे।

रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय टीम के चयन के लिए चंडीगढ़ में 30 और 31 अगस्त को ट्रायल आयोजित किए गए थे। ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए देशभर से 250 से अधिक स्केटर्स ने पंजीकरण कराया था। रोलर हॉकी और इनलाइन हॉकी के चयन ट्रायल सेक्टर-10 स्थित स्केटिंग रिंक में हुए, जबकि स्केटबोर्डिंग और फ्रीस्टाइल के ट्रायल सेक्टर-17 स्थित स्केट पार्क में आयोजित किए गए।

खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण की अधिकारी खुशबू सोनी को चयन ट्रायल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने ट्रायल के आयोजन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण वालिया ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने एक बार फिर रोलर और इनलाइन हॉकी में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर देश और शहर का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई।

एसोसिएशन के महासचिव एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हरप्रीत सिंह ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जल्द ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।

चंडीगढ़ में नशे के 58 हॉटस्पॉट पर पुलिस की सख्त निगरानी

प्रशासक ने तस्करों पर कार्रवाई तेज करने और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्ती के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब और सख्ती बरतेगी। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और शहर में नशे की सप्लाई तथा बिक्री रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में नशे की रोकथाम को लेकर हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जाए।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में नशे की बिक्री या इस्तेमाल से संबंधित शिकायतों वाले 58 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पहले नशे से जुड़े मामलों में पकड़े जा चुके आरोपितों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। कई चिह्नित तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है, जबकि कुछ आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

सप्लाई नेटवर्क तोड़ने पर जोर : प्रशासक ने पुलिस को नशे की सप्लाई करने वालों, पेडलरों और नशे की बिक्री या सेवन वाले स्थानों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को कहा। नशे की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ साइबर विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने की बात कही गई।

बीट सिस्टम होगा मजबूत : कटारिया ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस के बीट सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। ऐसे क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाने और अचानक निरीक्षण करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल स्टोरों पर भी निगरानी : नशे की रोकथाम के लिए मेडिकल स्टोरों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी दवाओं की बिक्री पर विशेष नजर रखने को कहा गया है, जिनमें नशे की लत लगाने वाले या नियंत्रित पदार्थ होते हैं। बिना उचित चिकित्सकीय पर्चे के ऐसी दवाओं की बिक्री रोकने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

जनता से सूचना देने की अपील : बैठक में नशे से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने के लिए गोपनीय और प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा हुई। डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि एनडीपीएस कानून के तहत ऐसा तंत्र तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग नशे की बिक्री या संदिग्ध तस्करों की सूचना पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। इसका उद्देश्य आम लोगों को पुलिस की आंख और कान के रूप में जोड़ना है।

पुनर्वास और सामाजिक भागीदारी जरूरी : प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ को नशामुक्त बनाने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। नशे की सप्लाई रोकने के साथ इसकी लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा। परिवार, समाज और संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी से ही नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए।

न्यूज ब्रीफ

आपराधिक मामला छिपाकर नौकरी पाने वाला क्लर्क सेवा से बर्खास्त

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सरकारी नौकरी के समय अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना सहकारी सभाओं के आडिट विभाग के क्लर्क करमजीत सिंह को भारी पड़ गया। वर्ष 2019 में नियुक्त हुए करमजीत सिंह ने घोषणा पत्र में अपने खिलाफ किसी आपराधिक मामले के लंबित नहीं होने की जानकारी दी थी, जबकि उसके खिलाफ वर्ष 2015 से मामला अदालत में विचाराधीन था।नौकरी मिलने के बाद होशियारपुर की अदालत ने 21 अक्टूबर 2021 को उसे मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। इसके बावजूद उसने विभाग को अपनी सजा की जानकारी नहीं दी और सरकारी सेवा में बना रहा।मामले की जानकारी विभाग को अप्रैल 2022 में शिकायत मिलने के बाद हुई। इसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई और कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच में सामने आया कि आपराधिक मामला उसी से संबंधित था। कर्मचारी ने स्वीकार किया कि मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है।इसके बाद मामला पंजाब के एडवोकेट जनरल के पास कानूनी राय के लिए भेजा गया। कानूनी राय में माना गया कि नियुक्ति के समय आपराधिक मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के कारण कर्मचारी पर सरकारी सेवा में भरोसा करना उचित नहीं है।

तरनतारन के गांव चाहल में खेतों से 12 किलो हेरोइन बरामद, तस्करों की तलाश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, तरनतारन । थाना सराय अमानत खां पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर सीमावर्ती क्षेत्र से 12 किलो 70 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार, नशे की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में पहुंचाई गई थी। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि थाना सराय अमानत खां पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव चाहल में मनजिंदर सिंह के खेतों में बड़ी संख्या में संदिग्ध पैकेट पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बीएसएफ की 115वीं बटालियन के जवानों ने संयुक्त रूप से खेतों और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान खेतों से कुल 24 संदिग्ध पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने पैकेटों की जांच की तो उनमें हेरोइन बरामद हुई। सभी पैकेटों का वजन करने पर कुल 12 किलो 70 ग्राम हेरोइन मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने ड्रोन के जरिये सीमा पार से यह खेप भारतीय क्षेत्र में गिराई थी। पुलिस अब खेप मंगवाने और उसे लेने वाले तस्करों की पहचान में जुटी है। मामले में आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग भी खंगाले जा रहे हैं।

फिरोजपुर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी

भारतेन्दु संवाददाता, फिरोजपुर । फिरोजपुर जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। शरारती तत्वों ने ई-मेल के माध्यम से कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। टीमों ने पूरे कोर्ट परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया।धमकी को गंभीरता से लेते हुए दोपहर 12 बजे तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदालती कामकाज बंद रखा गया। वकीलों, क्लर्कों और आम लोगों को भी सुरक्षा कारणों से इस अवधि में परिसर में प्रवेश नहीं करने की सलाह दी गई। वहीं, शुक्रवार को होने वाली लोक अदालत की कार्यवाही भी धमकी के चलते निर्धारित समय से देरी से शुरू हुई।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डॉग स्क्वायड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट परिसर के प्रत्येक हिस्से की बारीकी से जांच की। तलाशी अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली।पुलिस अब ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। धमकी भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस गुप्त सूत्रों की मदद से भी मामले की जानकारी जुटा रही है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार के 133 पीड़ितों को 42 साल बाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

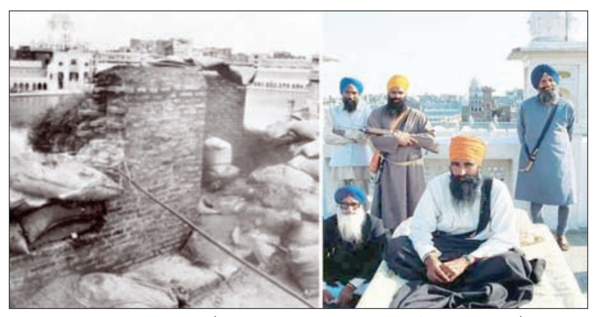

ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर में दुकानें और कारोबार उजड़ने के करीब 42 साल बाद 133 प्रभावित लोगों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्षों से पुनर्वास और वैकल्पिक जगह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे पीड़ितों के लिए अब अमृतसर की मालमंडी में जगह मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को वर्ष 1988 में गलियारा परियोजना के तहत निर्धारित दर के आधार पर वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए। उस समय जमीन की कीमत 1000 रुपये प्रति गज तय की गई थी। अदालत ने बाद में सरकार की ओर से बढ़ाई गई जमीन की दर को स्वीकार नहीं किया और पुराने निर्धारित रेट के आधार पर ही राहत देने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रभावित लोग लंबे समय से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था। पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता सौरव खुराना और अन्य वकीलों ने दलील दी कि इतने लंबे समय से विस्थापित लोगों पर लगातार बढ़ती जमीन की कीमतों का आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।

पीड़ितों के अनुसार, उनके पुनर्वास का मामला कई वर्षों तक अलग-अलग स्तरों पर चलता रहा। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों को 10 हजार रुपये प्रति गज के आधार पर राशि जमा करवाने का निर्देश दिया था और मामला हाईकोर्ट को वापस भेजा था। इसके बाद जनवरी 2020 में 14,450 रुपये प्रति गज की दर से आवंटन का निर्णय लिया गया।

हालांकि जुलाई 2022 में पंजाब सरकार ने जमीन की दर बढ़ाकर 38,400 रुपये प्रति गज कर दी। इससे 133 प्रभावित लोगों के सामने दोबारा बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बढ़ी हुई दर को चुनौती दी और पुराने आधार पर वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की।

निलंबित कैब एप से बुकिंग जारी चालान पर चालकों ने उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में ओला, उबर, इंड्राइव और रैपिडो के लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद मोबाइल एप के माध्यम से शहर में कैब की बुकिंग और सवारियों को उठाने की शिकायतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्राइसिटी कैब चालक कल्याण संघ ने इस मामले में जिम्मेदारी तय करने और तकनीकी स्तर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संघ ने शुक्रवार को राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन की प्रतियां वित्त-सह-परिवहन सचिव, मुख्य सचिव चंडीगढ़, प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक और सेमीट के प्रमुख को भी भेजी गई हैं।

संघ का कहना है कि जब चारों सवारी सेवा कंपनियों के लाइसेंस चंडीगढ़ में निलंबित हैं, तो उनके मोबाइल एप शहर की सीमा के भीतर सवारी बुक करने और चालक को सवारी उठाने की सुविधा कैसे दे रहे हैं। संघ ने सवाल उठाया कि यदि निलंबन के बावजूद एप पर सवारी उपलब्ध कराई जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

कंपनी की गलती का खामियाजा चालक क्यों भुगतें : संघ ने मांग की है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सेमीट के तकनीकी सहयोग से भू-घेराबंदी और स्थान-निर्धारण तकनीक लागू की जाए। इससे निलंबित कंपनियों के एप चंडीगढ़ सीमा में सवारी स्वीकार करने और चालक को सवारी उठाने के लिए भेजने में सक्षम नहीं रहेंगे। संघ के मुताबिक एप पर बुकिंग मिलने के कारण चालक सवारी लेने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इसके बाद यातायात और परिवहन विभाग की ओर से उनके चालान किए जा रहे हैं। संघ के अध्यक्ष वरदीप सिंह ने कहा कि प्रशासन ने कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए हैं, लेकिन उनके एप से अब भी चंडीगढ़ में सवारी बुक हो रही है।

चंडीगढ़ में वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर चुनावी रणनीति पर करेंगे विचार-विमर्श

सचिन पायलट के पहले पंजाब दौरे से कांग्रेस संगठन को एकजुट करने की कवायद तेज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट के पंजाब दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद पायलट का यह पहला पंजाब दौरा होगा। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद वह कभी भी पंजाब पहुंच सकते हैं। उनका दौरा दो से तीन दिन का हो सकता है। अगले एक-दो दिनों में उनके कार्यक्रम का विस्तृत कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।

पायलट के दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को दूर कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगी। दौरे के दौरान वह प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला प्रभारियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी की जमीनी स्थिति की जानकारी ले सकते हैं।

पंजाब दौरे से पहले सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इन बैठकों में प्रदेश में संगठन की स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। पायलट ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना होगा।

राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस को सक्रिय करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में पायलट का पंजाब दौरा संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पायलट के दौरे की शुरुआत अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने से होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी उनका अंतिम कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। अमृतसर के बाद वह चंडीगढ़ पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।

दौरे के दौरान जिला स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पायलट जिला प्रभारियों से संगठन की सक्रियता, नेताओं के बीच तालमेल और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी ले सकते हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है।

प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से अलग-अलग नेताओं के बीच खींचतान पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पायलट के सामने सभी गुटों को साथ लेकर चलने और संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पर सभी कमियों को दूर किया जाए।

सेक्टर-26 मंडी पार्किंग टेंडर पर हाईकोर्ट ने 28 सितंबर तक लगाई तत्काल रोक

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी में नई पार्किंग के टेंडर की प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने यूटी चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया जाए।

◆ टेंडर की शर्तों पर याचिकाकर्ताओं ने जताई आपत्ति, पिक-एंड-ड्रॉप वाहनों से शुल्क की आशंका

याचिकाकर्ता मोहित सूद और अन्य ने टेंडर की शर्तों को चुनौती देते हुए कहा कि मंडी के प्रवेश द्वार पर सभी वाहनों को पार्किंग पर्ची देने और निकासी के समय शुल्क वसूलने की व्यवस्था प्रस्तावित है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि इससे केवल सवारी को छोड़ने या लेने के लिए मंडी आने वाले पिक-एंड-ड्रॉप वाहनों से भी पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, छूट प्राप्त क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वालों को भी शुल्क देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने इसे लोगों के लिए अनावश्यक आर्थिक बोझ बताते हुए टेंडर की शर्तों पर आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तीन फरवरी 2022 को हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश का हवाला दिया, जिसमें इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया गया था।

यूटी प्रशासन की ओर से अधिवक्ता कुणाल मुलवानी अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि टेंडर की बोलियां उसी दिन खोली जानी थीं और जवाब दाखिल करने के लिए कम समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले को 28 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी। अब प्रशासन को टेंडर की शर्तों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर अपना पक्ष रखना होगा।

पंजाब चुनाव में कांग्रेस-आप आमने-सामने, नशा और विकास होंगे मुद्दे

नशे पर सरकार को घेरने की तैयारी, युवाओं के रोजगार और विकास पर रहेगा कांग्रेस का जोर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करना, विकास को गति देना और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना पार्टी के प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। पायलट ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम भी इस दिशा में संकेत दे चुके हैं।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं पर पायलट ने कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी हाईकमान से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसलिए वह इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की वापसी को लेकर फैसला पार्टी नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा।

पंजाब दौरे से पहले तैयारियों में जुटे पायलट ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी बात की। उन्होंने नशे को पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। पायलट ने आरोप लगाया कि प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। उनका कहना था कि नशे की समस्या ने पंजाब के युवाओं और उनके भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

केंद्र पर भी नशे की आपूर्ति रोकने में विफल रहने का आरोप : पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी पंजाब में बाहर से आने वाले नशे की आपूर्ति रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर नशे के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करेगी और युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब के विकास के अपने पुराने रिकार्ड और युवाओं के बेहतर भविष्य के संकल्प को लेकर जनता के बीच जाएगी।

भाजपा के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया की ओर से अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर की गई टिप्पणी पर पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि जिन लोगों को भाजपा पहले निशाना बनाती थी और जिन्हें उसने राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया था, आज उसी के साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

प्रकाश सिंह बादल के बाद बदल गया अकाली दल : अकाली दल को लेकर पायलट ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल के समय वाला अकाली दल अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई बार टूट हुई है और अलग-अलग राजनीतिक दल अस्तित्व में आए हैं। उनके अनुसार अकाली दल और भाजपा दोनों पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए एक-दूसरे का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि जब दोनों दल पहले गठबंधन में थे, तब भी उन्हें पंजाब में हार का सामना करना पड़ा था।

आप के बिखरने का दावा : आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पायलट ने दावा किया कि पार्टी के भीतर बिखराव की स्थिति है और उसके राज्यसभा के कई सांसद भाजपा के साथ चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास विपक्षी दलों को तोड़ने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं है। पायलट ने कहा कि सांसदों को अपने साथ जोड़कर किसी तरह परिसीमन से जुड़े कानून को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

पायलट ने कहा कि पंजाब के लोग राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हैं। कांग्रेस संगठन को प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस मजबूत संगठन और स्पष्ट मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी तथा आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी।

पंजाब पुलिस के 70 इंस्पेक्टर बने डीएसपी एक साल के लिए प्रभावी रहेगी पदोन्नति

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 70 इंस्पेक्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मामलों एवं न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिला कैडर और आर्म्ड कैडर के कुल 70 इंस्पेक्टरों को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया गया है। सरकार के इस फैसले से पुलिस विभाग में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

पदोन्नत अधिकारियों को पंजाब पुलिस सेवा के वेतन स्तर-18 में स्थान दिया गया है। इस स्तर के तहत 56,100 से 1,77,500 रुपये का वेतनमान निर्धारित है। पदोन्नति विभागीय तरक्की कमेटी की 23 मई 2025 को हुई सिफारिशों के आधार पर की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकारियों को वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति और निर्धारित नियमों के अनुसार डीएसपी पद पर पदोन्नति दी गई है।

जिला कैडर के 50 और आर्म्ड कैडर के 20 इंस्पेक्टर : पदोन्नति पाने वाले 70 अधिकारियों में जिला कैडर के 50 इंस्पेक्टर और आर्म्ड कैडर के 20 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इनमें कई अधिकारी लंबे समय से इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं दे रहे थे। पदोन्नति के बाद उन्हें डीएसपी स्तर की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलेगा। इससे उनके पद और वेतनमान में भी बढ़ोतरी होगी।

एक साल के लिए प्रभावी रहेगी पदोन्नति : अधिसूचना में पदोन्नति की अवधि को लेकर भी शर्त निर्धारित की गई है। इसके अनुसार संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, लेकिन यह एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। इस दौरान सेवा संबंधी नियमों और अन्य निर्धारित शर्तों के अनुसार पदोन्नति की स्थिति पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठता सूची में बदलाव, किसी आपत्ति या न्यायिक मामले की स्थिति में पदोन्नति पर नियमानुसार दोबारा विचार किया जा सकता है।

डीएसपी स्तर पर बढ़ेगी अधिकारियों की उपलब्धता : पंजाब पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की जांच और पुलिस प्रशासन में अहम भूमिका होती है। ऐसे में 70 इंस्पेक्टरों की पदोन्नति से जिला पुलिस और आर्म्ड पुलिस में अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

कश्मीरी हिंदुओं की कॉलोनियों को आतंकियों की खुली धमकी

आतंकी संगठन की धमकी से विस्थापित कर्मचारियों की सुरक्षा और पुनर्वास प्रक्रिया पर बढ़ी चिंता

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आतंकी संगठनों की ओर से अब ट्रांजिट आवासीय कॉलोनियों को निशाना बनाने की धमकी सामने आई है। लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन के तौर पर बताए जाने वाले यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (यूएलसी) ने इन कॉलोनियों को लेकर आपत्तिजनक दावे करते हुए संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

यूएलसी ने ट्रांजिट कॉलोनियों को कथित तौर पर 'इजरायली शैली की बस्तियां' बताते हुए आरोप लगाया है कि इनके जरिए कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। आतंकी संगठन ने इन कॉलोनियों में रहने वाले कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी है।

पीएम पैकेज के तहत छह हजार लोगों को नौकरी : कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज लागू किया गया है। इसके तहत घाटी के विभिन्न हिस्सों में करीब छह हजार विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन कर्मचारियों के रहने के लिए अलग-अलग जिलों में ट्रांजिट आवासीय कॉलोनियां भी बनाई गई हैं।

कई कर्मचारी इन कॉलोनियों में रह रहे हैं। आतंकी संगठन ने अब इन्हीं कॉलोनियों और वहां रहने वाले लोगों को धमकी दी है। संगठन की ओर से धमकी के साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जुड़े दो दस्तावेज भी जारी किए गए हैं। इनमें एक दस्तावेज ट्रांजिट आवास के निर्माण और इंजीनियरिंग कार्यों से संबंधित बताया गया है, जबकि दूसरे में प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कर्मचारियों के आवास से जुड़े विवरण और अधिकारियों के बीच पत्राचार का उल्लेख है।

कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक करने का दावा : यूएलसी ने इससे पहले भी इंटरनेट मीडिया के जरिए विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और अन्य लोगों की कथित जानकारी साझा कर उन्हें धमकाने का प्रयास किया है। इस बार संगठन ने दावा किया है कि उसके पास संबंधित कर्मचारियों का विवरण मौजूद है और आने वाले समय में उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा।

धमकी में कर्मचारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सरकार के एजेंडे का हिस्सा बताया गया है। संगठन ने उन्हें चेतावनी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही है। इस तरह की धमकियों ने ट्रांजिट कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सरकारी दस्तावेज आतंकियों तक पहुंचने पर सवाल : पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डा. अजय चरंगू ने कर्मचारियों की जानकारी और सरकारी दस्तावेज आतंकियों तक पहुंचने को गंभीर विषय बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि संवेदनशील सरकारी सूचनाएं आतंकी संगठनों तक कैसे पहुंच रही हैं और इसके पीछे कौन लोग या तंत्र सक्रिय हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक कर धमकियां देना कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है। उनके अनुसार, इससे यह भी पता चलता है कि आतंकी और कट्टरपंथी तत्व अभी भी अपने नेटवर्क के जरिए गतिविधियां चला रहे हैं।

पहले भी हुआ है कॉलोनियों का विरोध : कश्मीर मामलों के जानकारों के अनुसार, विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए बनाई जा रही ट्रांजिट कॉलोनियों का विरोध पहले भी अलगाववादी और कुछ राजनीतिक संगठनों की ओर से किया जाता रहा है। हालांकि, मौजूदा धमकियां केवल आवासीय कॉलोनियों के विरोध तक सीमित नहीं माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की धमकियां कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी और पुनर्वास की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास हो सकती हैं। साथ ही, 'इजरायली मॉडल' जैसे आरोपों के जरिए स्थानीय समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव पैदा करने की कोशिश भी की जा सकती है।

'वंदे मातरम' विवाद में सुरिंदर चौधरी की एंट्री, बोले- राष्ट्रीय गीत पर है गर्व

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के पूरे छंद के गायन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जारी विवाद के बीच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को 'वंदे मातरम' पर गर्व जताते हुए इसे स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की भावनाओं से जुड़ा गीत बताया।

चौधरी ने कहा कि 'वंदे मातरम' आजादी की लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण गीतों में से एक रहा है। उस दौर में देश के अलग-अलग समुदायों और धर्मों के लोग इसे गाते थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे शहीदों की विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का प्रतीक है।

उपमुख्यमंत्री से जब राष्ट्रीय गीत के पूरे गायन के दौरान खड़े रहने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस की टिप्पणी की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 'वंदे मातरम' देश का राष्ट्रीय गीत है और उन्हें इस पर गर्व है।

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में 'वंदे मातरम' के पूरे गायन को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय गीत गाना कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उमर ने यह भी कहा था कि पूरे गीत के दौरान खड़े नहीं होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उनके इस बयान पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे वास्तविक परिस्थितियों से दूर बताया।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति में लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के शुरुआती दो पद गाए जाने के बावजूद किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया।

वहीं, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था कि क्या कांग्रेस चाहती है कि और कश्मीरी जेल जाएं। उनके इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं।

'वंदे मातरम' को लेकर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का बयान ऐसे समय आया है, जब जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय गीत को लेकर दोनों दलों के नेताओं के अलग-अलग रुख ने गठबंधन के भीतर वैचारिक मतभेद को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। चौधरी ने अपने बयान में गीत के सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन से इसके ऐतिहासिक जुड़ाव पर जोर दिया। अब देखना होगा कि 'वंदे मातरम' को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आगे जम्मू-कश्मीर की सियासत में कितना असर डालता है।

महानपुर हाई सिक्योरिटी जेल तैयार होने से 600 खूंखार कैदियों और आतंकियों की होगी निगरानी

वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के महानपुर में बन रही हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जेल को जल्द संचालित करने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य और वहां उपलब्ध कराई जा रही सुरक्षा सुविधाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजीपी एस.जे.एम. जिलानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं और निगरानी प्रणाली का जायजा लिया। निर्माण से जुड़े अधिकारियों को बचे हुए काम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि जेल को समय पर संचालित किया जा सके।

600 कैदियों को रखने की होगी व्यवस्था : महानपुर में तैयार की जा रही इस हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 600 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। जेल को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश की जेलों में बंद बेहद संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले कैदियों को सुरक्षित तरीके से रखने की व्यवस्था करना है।

खूंखार आतंकियों और बड़े अपराधियों के लिए विशेष व्यवस्था: जानकारी के अनुसार, इस जेल में जम्मू-कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद खूंखार आतंकियों और बड़े अपराधियों को रखा जा सकता है। हाई सिक्योरिटी व्यवस्था के कारण ऐसे कैदियों की निगरानी और सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, जेल का निर्माण पूरा होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से संचालन में लाया जाएगा।

जेल का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अगले करीब एक महीने में इसे पूरी तरह तैयार किए जाने की उम्मीद जताई गई है।

श्रीनगर की हवा हुई बेदम, स्वच्छ वायु रैंकिंग में बड़ी गिरावट

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। बर्फ से ढके पहाड़ों, डल झील और साफ-सुथरी आबोहवा के लिए पहचाने जाने वाले श्रीनगर के लिए स्वच्छ वायु के मोर्चे पर चिंताजनक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में श्रीनगर 26वें स्थान पर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 में श्रीनगर इसी श्रेणी में चौथे स्थान पर था। महज तीन वर्षों में शहर की रैंकिंग में 22 पायदान की गिरावट दर्ज हुई है। ताजा सर्वेक्षण में श्रीनगर को 162.6 अंक मिले हैं। रैंकिंग में राजधानी दिल्ली ने भी श्रीनगर को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली को 172 अंकों के साथ 21वां स्थान मिला है। वहीं मुंबई 28वें और बेंगलुरु 32वें स्थान पर रहे। सर्वेक्षण में लखनऊ 198 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि इंदौर और जबलपुर ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। श्रीनगर की रैंकिंग में आई गिरावट ने शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं। सर्दियों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य, सड़क की धूल और अन्य प्रदूषण स्रोत शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

हाफिज सईद पर दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी

कश्मीर में आतंकियों तक हथियार और धन पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपित लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ जम्मू की एनआइए अदालत ने दूसरा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। करीब दो महीने के भीतर उसके खिलाफ यह दूसरी बड़ी कानूनी कार्रवाई है। एनआइए ने अदालत में कहा कि यूएपीए के तहत नामित आतंकी पाकिस्तान से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को हथियार और धन उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए निर्देश दे रहा है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित फरार है और जांच एजेंसी सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसके बाद सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान निवासी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वारंट की तामील के लिए इसे एनआइए जम्मू के डीआइजी को भेजा गया है।

कश्मीर में हथियार और धन पहुंचाने का आरोप : एनआइए के अनुसार, हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों को हथियार, धन और आतंकी गतिविधियों के संचालन संबंधी निर्देश उपलब्ध करा रहा है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि हाफिज पाकिस्तान में रहकर जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।

इससे पहले जुलाई में भी उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। उस मामले में एनआइए ने उसे पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। अब आतंकियों तक हथियार और धन पहुंचाने के कथित नेटवर्क में भूमिका को लेकर अदालत ने उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की है।

नाका जांच में पकड़ा गया संदिग्ध : यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस की नाका जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी से भी जुड़ा है। पांडच जकूरा क्षेत्र में पुलिस ने श्रीनगर निवासी मोहम्मद नकीब बट को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक चीनी ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।

थाना जकूरा में एफआइआर नंबर 24/2026 दर्ज की गई है। आरोपित के खिलाफ यूएपीए की धारा 23, आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही एनआइए : एनआइए अब मामले में आतंकी नेटवर्क की कड़ियों की जांच कर रही है। एजेंसी संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर हथियार और धन पहुंचाने वाले नेटवर्क तथा हाफिज सईद की कथित भूमिका का पता लगाने में जुटी है। जांच एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के मददगारों और कश्मीर में सक्रिय नेटवर्क के बीच संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।

सतवारी फ्लाईओवर से जम्मू एयरपोर्ट की राह होगी आसान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। बहुप्रतीक्षित कुंजवानी-सतवारी चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को अगले कुछ दिनों में अस्थायी रूप से वाहनों के लिए खोलने की तैयारी है। करीब चार किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के शुरू होने से सतवारी चौक पर रोजाना लगने वाले भारी जाम से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के तहत बन रहे इस फ्लाईओवर की अनुमानित लागत करीब 240 करोड़ रुपये है। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू शहर और जम्मू हवाई अड्डे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे सड़क निर्माण का काम पूरा करने के लिए इसे अस्थायी तौर पर खोला जा रहा है। वहीं सतवारी और एयरपोर्ट की ओर उतरने वाले दो रैंप का निर्माण अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार दोनों रैंप पर एक-एक पिलर का काम बाकी है और इन्हें अगले दो से तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।

एयरपोर्ट की ओर बनने वाले रैंप के तैयार होने के बाद कुंजवानी से आने वाले यात्री सतवारी चौक के जाम से बचते हुए सीधे जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे। इससे एयरपोर्ट मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा। फ्लाईओवर शुरू होने से बेलीचराना, रायपुर सतवारी और आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है।

कुलगाम से अनंतनाग तक जांच, तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई से मचा हड़कंप

आतंकवाद और नशे के नेटवर्क पर एजेंसियों का बड़ा प्रहार, कई ठिकानों पर की छापेमारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और नशा तस्करी के खिलाफ जांच एजेंसियों ने शनिवार को कई जिलों में व्यापक कार्रवाई की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर के कुलगाम, बांदीपोरा और बारामुला के सोपोर इलाके में कई आवासीय परिसरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी साजिश के मामले में चल रही जांच का हिस्सा बताई गई है।

सोपोर के गुंड ब्राठ इलाके में एनआईए टीम ने गुलाम मोहम्मद तंतरी के आवास की तलाशी ली। इसके अलावा अरामपोरा के तेलियां मोहल्ले में शबनम के गौसिया आबाद स्थित आवास पर भी जांच की गई। कुलगाम और बांदीपोरा में भी कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने एनआईए टीमों को सुरक्षा मुहैया कराई।

इसी दौरान राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने जम्मू संभाग के पुंछ और उधमपुर में तीन स्थानों पर तलाशी ली। पुंछ के मंडी और सुरनकोट तथा उधमपुर के रामनगर में जांच की गई। मंडी के चीला डांगरी इलाके में मुन्नबर हुसैन के आवासीय परिसर की भी तलाशी ली गई।

आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक मामले में एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है। एजेंसी के अनुसार वह कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को धन, हथियार और निर्देश उपलब्ध कराने में शामिल है।

डोडा के जंगल में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी का शव बरामद

भारतेंदु संवाददाता, डोडा । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों को संयुक्त अभियान के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी का शव बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, यह बरामदगी जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सियोजधार जंगल में हुई। सियोजधार जंगल भद्रवाह घाटी को पड़ोसी उधमपुर और कठुआ जिलों से जोड़ने वाले पहाड़ी इलाके में स्थित है। सुरक्षा बलों ने यहां आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर अभियान चलाया था। इसी दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराने के बाद उसका शव बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान में डोडा पुलिस की विशेष अभियान समूह (एसओजी), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीम शामिल थी।

स्मार्टफोन ने बदली सेब बिक्री की तस्वीर, किसानों का बढ़ा मुनाफा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर के सेब किसानों ने अब पारंपरिक मंडी व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल माध्यमों से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनानी शुरू कर दी है। शोपियां और बडगाम के कई युवा किसान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए देशभर में अपने बागों का सेब बेच रहे हैं। इससे उन्हें बिचौलियों और कमीशन की लंबी श्रृंखला से राहत मिल रही है।

शोपियां में बड़ी संख्या में परिवार सेब की खेती पर निर्भर हैं, जबकि सोपोर की मंडी देश की प्रमुख फल मंडियों में शामिल है। पारंपरिक व्यवस्था में किसान की फसल कई हाथों से गुजरती है और हर स्तर पर कमीशन कटता है। सीधे बिक्री शुरू होने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है, वहीं ग्राहकों को भी बाजार कीमत की तुलना में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक सस्ता और ताजा सेब उपलब्ध हो रहा है।

शोपियां के युवा किसान इरशाद डार ने कोरोना काल में 'कश्मीरी एपल' नाम से सोशल मीडिया पेज शुरू किया था। शुरुआत में सीमित ऑर्डर मिले, लेकिन धीरे-धीरे मांग बढ़ती गई। अब वह सीजन में हजारों पेटियां सीधे देश के विभिन्न शहरों में भेजते हैं। बडगाम के किसान भी इसी मॉडल को अपनाकर सेब के साथ बादाम और अखरोट बेच रहे हैं।

कृषि विशेषज्ञ इस बदलाव को 'फार्म-टू-फोन' मॉडल बता रहे हैं। स्मार्टफोन के जरिए किसान अब उत्पादक के साथ-साथ मार्केटिंग और बिक्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। इससे कश्मीर के सेब को स्थानीय मंडियों से आगे राष्ट्रीय बाजार में सीधे पहचान बनाने का अवसर मिल रहा है।

जेकेरेरा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं की निगरानी और शिकायत के लिए शुरू कीं डिजिटल सुविधाएं

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में घर, जमीन या अन्य संपत्ति खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं की वैधता और पंजीकरण स्थिति की जांच अब पहले से आसान हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (जेकेरेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से अपने आधिकारिक पोर्टल पर दो नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं।

इन सुविधाओं में 'जीआइएस प्रोजेक्ट ट्रैकर' और 'रिपोर्ट अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट' शामिल हैं। इनके माध्यम से नागरिक न केवल अपने आसपास मौजूद रियल एस्टेट परियोजनाओं की स्थिति डिजिटल नक्शे पर देख सकेंगे, बल्कि बिना पंजीकरण संचालित हो रही परियोजनाओं की शिकायत भी सीधे जेकेरेरा तक पहुंचा सकेंगे।

जेकेरेरा की जीआइएस आधारित सुविधा के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं को इंटरैक्टिव डिजिटल नक्शे पर देखा जा सकेगा। इसमें पंजीकृत परियोजनाओं के साथ-साथ उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी उपलब्ध होगी, जिनके पंजीकरण आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

खरीदार जेकेरेरा पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध 'व्यू आन द मैप' विकल्प के जरिए संबंधित परियोजना की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे संपत्ति खरीदने से पहले किसी प्रोजेक्ट की स्थिति और पंजीकरण संबंधी जानकारी जांचना अधिक सुविधाजनक होगा।

जेकेरेरा ने बिना पंजीकरण संचालित हो रही रियल एस्टेट परियोजनाओं पर निगरानी मजबूत करने के लिए 'रिपोर्ट अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट' सुविधा भी शुरू की है। इसके जरिए कोई भी नागरिक अपने आसपास चल रही ऐसी परियोजना की शिकायत कर सकता है, जो जेकेरेरा के साथ पंजीकृत नहीं है।

शिकायत दर्ज करते समय परियोजना से संबंधित आवश्यक विवरण के साथ मौके की तस्वीरें भी साक्ष्य के तौर पर अपलोड की जा सकेंगी। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राधिकरण मामले की जांच कर आवश्यक नियामकीय कार्रवाई कर सकता है।

जेकेरेरा ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई रियल एस्टेट में लगाने से पहले परियोजना की पंजीकरण स्थिति और प्रामाणिकता की जांच जरूर करें।

असंतोष | स्थानीय अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को लेकर सितंबर में पदयात्रा पर टिकीं निगाहें

लद्दाख की मांगों पर नहीं बनी बात, वांगचुक ने आंदोलन का फूंका बिगुल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख के राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के साथ हुई हालिया बैठक के बाद पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने निराशा जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर बैठक के नतीजे पर सवाल उठाए और केंद्र से ठोस आश्वासन की मांग की। वांगचुक ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो लद्दाख में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।

वांगचुक ने वीडियो में कहा कि वह लद्दाख के मुद्दों को लेकर गृह मंत्रालय के साथ बैठक के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन बैठक से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें केवल चाय अच्छी थी और अगली बैठक अगले महीने होने की बात कही गई है।

लोकतांत्रिक ढांचे और विधानसभा की मांग : सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोगों की प्रमुख मांगों में क्षेत्र के लिए मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा और विधानसभा का गठन शामिल है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में अधिक अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने भूमि, पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों से जुड़े मामलों में भी लद्दाख के लोगों की भागीदारी की जरूरत बताई। वांगचुक ने कहा कि जब तक लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होती, तब तक प्रशासन को ऐसे बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, जिनसे क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और स्वरूप में व्यापक बदलाव हो।

19 से 24 सितंबर तक पदयात्रा का एलान : केंद्र से आश्वासन नहीं मिलने पर वांगचुक ने 19 से 24 सितंबर के बीच लद्दाख में पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। वांगचुक के अनुसार, यदि इस अवधि में केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो पदयात्रा को लद्दाख के शहीदों की स्मृति को समर्पित किया जाएगा। वहीं, प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों में हुई बैठक: बुधवार को केंद्र सरकार और लद्दाख के स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में केंद्र ने फिलहाल लद्दाख को राज्य का दर्जा देने या विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की मांग स्वीकार नहीं की।

गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं से अनुच्छेद 371 से संबंधित प्रस्तावित राजनीतिक ढांचे पर चर्चा से पहले आठ से दस प्रमुख मुद्दों पर विचार कर सहमति बनाने को कहा है। बैठक में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों ने एक ऐसे विशेष मॉडल पर काम करने पर सहमति जताई, जिसमें निर्वाचित निकाय को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां देने की व्यवस्था हो सकती है। वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के लोगों को अपने भविष्य और क्षेत्र से जुड़े फैसलों में प्रभावी लोकतांत्रिक अधिकार मिलना जरूरी है।

बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता से समाज में बदलाव की नई उम्मीद

शिवालिक अवस्थी
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र।

वैसे तो हमारा देश-हमारा प्रदेश, आधुनिकता के इस दौर में, हमेशा से उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है और भविष्य में भी अग्रसर रहेगा। किंतु, आधुनिकीकरण के बावजूद, आज भी हमारे समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए समय-समय पर सरकार को कई प्रमुख कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का संचालन विशेष तौर से करना पड़ रहा है। ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का संचालन करने का एक मात्र उद्देश्य; हमारे समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने से जोड़ा गया है। समाज प्रेरित होकर, नई और आशावादी दिशा की ओर बढ़ता रहे, इसी सोच को धरातल तक पहुंचाने के लिए समय-समय पर कई प्रेरक योजनाओं की शुरुआत की जा चुकी है। इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एक ऐसी योजना-एक ऐसा अभियान, जिसके माध्यम से, समाज के हर वर्ग को बेटियों की सुरक्षा एवं उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है।

बेटियों की सुरक्षा एवं उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। भारत में बढ़ती जनसंख्या के बावजूद लड़कियों के गिरते लिंगानुपात में सुधार लाने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर संचालित किया जा रहा है जिसमें देश में विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर समाज के कोने-कोने तक इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसान भाषा में कहें; तो इस योजना के माध्यम से हम सभी को - बच्चियों की 'सुरक्षा' एवं उनकी 'शिक्षा' में रचनात्मक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मुख्यत: इसके नाम से ही साफ हो जाता है। 'बेटी बचाओ' - हमारे समाज की बेटियों को बचाने की पहल और 'बेटी पढ़ाओ' - हमारे समाज की बेटियों को पढ़ाने की पहल।

पहले भाग पर प्रकाश डालें तो पता चलता है कि आज भी हमारे समाज के किसी कोने को रूढ़िवादी विचारों ने अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। जिसके कारण बेटियों का अस्तित्व असुरक्षित या खतरे से घिरा हुआ प्रतीत होता है। आज भी समाज के कई परिवारों का झुकाव बेटियों की तुलना में बेटों पर अधिक आंका गया है, जिससे असमानता वाले भाव हमारे समाज में हावी होते दिख रहे हैं। हालांकि, यह भी सत्य है कि सरकार, प्रशासन, विभाग एवं आम जन के सहयोग से, चलाई जा रही कई मुहिमों के चलते अब पक्षपाती विचार हमारे दिलो-दिमाग से बाहर जरूर निकलने लगे हैं। परंतु, समाज के वह हिस्से, जहां बेटियों के प्रति आज भी संकीर्ण सोच अपनाई जाती है, ऐसी विचारधाराओं के आधार को समाप्त करके उन्हें आशावादी बनाकर, बालिकाओं का अस्तित्व आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि जहां सोच बदलती है, वहीं से हमारा समाज बदलता है।

इसी कड़ी में, इस योजना के दूसरे भाग पर प्रकाश डालें, तो यह हमें, हमारा उत्तरदायित्व बेटियों की शिक्षा के प्रति हमें प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करता है। न केवल प्रारंभिक अथवा स्कूली शिक्षा, बल्कि समाज की हर बेटी, उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ-साथ अन्य प्रेरक गतिविधियों में भी उचित स्थान प्राप्त करे और समाज का नाम रोशन करे, ऐसे सफल प्रयासों के प्रति हमें अवगत करवाता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में वह महत्वपूर्ण आधार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों और अवसरों को समझने में सक्षम बनता है। इसलिए बेटियों की शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित रखने के बजाय उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपने कौशल को विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी समाज को सकारात्मक प्रयास करने होंगे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

गोमूत्र बनेगा ग्रामीण आय का नया आधार या सरकारी खर्च का एक और मॉडल?

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ (उ. प्र.)

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से गोमूत्र खरीद का जो पायलट मॉडल सामने आया है, उसे केवल गाय, गांव और संस्कृति की कहानी मानना आसान है, लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या सरकार गोमूत्र को सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया उत्पाद बनाना चाहती है, या फिर ऐसी घोषणा कर रही है जिसकी चमक कुछ समय बाद सरकारी कागजों तक सिमट जाएगी। 15 गांवों से रोज करीब 500 लीटर गोमूत्र एकत्र करने का लक्ष्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसी आंकड़े में योजना की ताकत और कमजोरी दोनों छिपी हैं। 500 लीटर प्रतिदिन का मतलब साल भर में करीब 1.82 लाख लीटर है। दस रुपये लीटर की दर से केवल खरीद पर सालाना लगभग 18.25 लाख रुपये खर्च होंगे। दर बीस रुपये हुई तो यही खर्च 36.5 लाख रुपये पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इस कच्चे माल से तैयार उत्पादों की बिक्री कितनी होगी और सरकारी खरीद के मुकाबले बाजार से कितनी आमदनी आएगी।

बुलंदशहर में यह प्रयोग बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुआ है। नरसेना क्षेत्र में पिछले वर्षों से महिला समूह गोमूत्र संग्रह कर रहे हैं। 2023 में वहां किसानों से 10 से 15 रुपये लीटर तक खरीद और जैविक खाद तथा कीटनाशक तैयार करने का दावा सामने आया था। उस समय एक साल में 10 हजार लीटर खरीद के बाद अगले चरण में 50 हजार लीटर का लक्ष्य बताया गया था। 2024 की रिपोर्टों में दर्जन से अधिक गांवों में महिला समूहों के संग्रह केंद्र और 20 हजार लीटर से अधिक संचयन का उल्लेख मिला। इसका मतलब साफ है कि सरकार के सामने कोई काल्पनिक प्रयोग नहीं, बल्कि पहले से चल रही स्थानीय गतिविधि को बड़े ढांचे में बदलने का अवसर है। यही कारण है कि नई योजना की असली परीक्षा घोषणा नहीं, पुराने अनुभव से सीख लेने में होगी।

छत्तीसगढ़ का उदाहरण इस बहस को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 में वहां गोधन न्याय योजना के विस्तार के रूप में चार रुपये लीटर की दर से गोमूत्र खरीद शुरू हुई। उद्देश्य था उससे जैविक कीटनाशक और कृषि इनपुट तैयार करना। उस समय राज्य में हजारों गौठानों का ढांचा भी बताया गया था। फिर भी किसी योजना की सफलता केवल खरीद केंद्रों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। यदि संग्रहित सामग्री का नियमित प्रसंस्करण, पैकेजिंग, प्रमाणन और बिक्री नहीं होती, तो खरीद अपने आप में टिकाऊ कारोबार नहीं बनती। यही वह बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश को उत्साह से ज्यादा व्यवस्था दिखानी होगी।

गुजरात का हालिया मॉडल इस बहस को एक और दिशा देता है। बनास डेयरी ने 2025 में देशी कांकरेज गाय पालने वाले पशुपालकों से पांच रुपये लीटर की दर पर गोमूत्र खरीदने का पायलट शुरू किया। इसे मृदा कंडीशनर और पौध वृद्धि से जुड़े उत्पादों में बदलने की व्यवस्था की गई। यहां महत्वपूर्ण बात खरीद की कीमत नहीं, बल्कि खरीद से पहले प्रसंस्करण और बिक्री का ढांचा है। संग्रह, परिवहन, संयंत्र, ब्रांड और बाजार की क्षमता किसी भी ऐसे मॉडल की सफलता के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश को भी इसी सवाल का जवाब देना होगा कि बुलंदशहर से निकलने वाला 500 लीटर प्रतिदिन आखिर किस संयंत्र में जाएगा, कितने समय में पहुंचेगा, किस गुणवत्ता मानक पर रखा जाएगा और तैयार उत्पाद कौन खरीदेगा।

गोमूत्र के कृषि उपयोग को पूरी तरह खारिज करना भी उतना ही गलत होगा जितना उसे हर बीमारी की दवा मान लेना। वैज्ञानिक साहित्य में गोबर और गोमूत्र आधारित जैविक मिश्रणों पर खेत परीक्षण हुए हैं और कुछ परिस्थितियों में इनके पोषक तथा सूक्ष्मजीवी प्रभाव दर्ज किए गए हैं। लेकिन खेत में किसी जैविक घोल का उपयोग और मानव औषधि के रूप में उसका सेवन दो अलग बातें हैं। इसलिए सरकार यदि गोमूत्र से दवाएं बनाने की बात करती है तो उसे औषधि नियमों, परीक्षण, बैच गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों से गुजरना होगा। परंपरा बाजार की शुरुआत कर सकती है, प्रमाणन ही उसे विश्वसनीय बाजार बनाता है।

सबसे बड़ी चुनौती संग्रहण है। ताजा गोमूत्र कोई दूध नहीं है जिसे सामान्य दुग्ध श्रृंखला की तरह तुरंत उठाकर हर जगह पहुंचा दिया जाए। गांव में स्वच्छ संग्रह पात्र, ढक्कनयुक्त टैंक, छनाई, बैच पहचान, परिवहन और प्रसंस्करण की समयसीमा तय करनी होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

हिंसा के सामने कानून कमजोर न पड़े

नोएडा हिंसा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यकर्ता आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को निरस्त करने का निर्णय कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठाए तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई को उचित नहीं माना। न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार का इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना स्वाभाविक रूप से इस पूरे मामले को व्यापक संवैधानिक बहस के केंद्र में ले आया है। प्रश्न यह है कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन किस प्रकार कायम किया जाए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना और प्रशासन से जवाब मांगना नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक भीड़ में स्पष्ट अंतर है। जब कोई आंदोलन पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमले अथवा आम नागरिकों में भय पैदा करने में बदल जाता है तो वह केवल विरोध का माध्यम नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है।

नोएडा की घटना के संदर्भ में सामने आए आरोपों में बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान पहुंचाने, औद्योगिक इकाइयों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं शामिल हैं। यदि किसी आंदोलन के दौरान इस स्तर की हिंसा होती है तो पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। उनका प्राथमिक दायित्व मानव जीवन की रक्षा करना, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा को फैलने से रोकना है। किसी आंदोलन की मूल मांग जायज होने मात्र से उसके दौरान की गई हिंसा जायज नहीं हो जाती।

हालांकि दूसरी ओर राज्य की शक्तियां भी असीमित नहीं हो सकतीं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी निरोधात्मक कार्रवाई असाधारण प्रकृति की होती है। इसका इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, आंदोलन में शामिल है अथवा प्रशासन से असहमति रखता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा भड़काने, हिंसक गतिविधियों को संगठित करने या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के आरोप लगाए जाते हैं तो राज्य को उन आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। न्यायालय की जिम्मेदारी भी यही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो।

यदि उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर खामियां पाईं और गिरफ्तारी को कानून की कसौटी पर उचित नहीं माना तो उसका न्यायिक परीक्षण आवश्यक था। प्रशासन की ओर से किसी कार्रवाई में प्रक्रिया संबंधी कमी रह जाना संभव है और यदि किसी अधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन किसी कार्रवाई को न्यायिक कसौटी पर गलत पाए जाने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उस समय कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चिंता ही निराधार थी।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसमें सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल हिंसा के लिए ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता। पुलिस पर हमला, वाहनों में आगजनी, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ या आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना किसी भी विचारधारा या आंदोलन का वैध हिस्सा नहीं हो सकता। इसी प्रकार पुलिस को भीड़ नियंत्रण के नाम पर कानून की सीमाओं से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों के लिए कानून की सीमा समान होनी चाहिए।

यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि किसी हिंसक घटना की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और वैज्ञानिक है। यदि किसी व्यक्ति पर हिंसा भड़काने या उसके पीछे साजिश रचने का आरोप है तो केवल आरोप पर्याप्त नहीं होने चाहिए। जांच एजेंसियों को घटनाओं, बयानों, डिजिटल सामग्री और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति की वास्तविक भूमिका स्थापित करनी चाहिए। जो वास्तव में हिंसा में शामिल रहे हैं, उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए और जो निर्दोष हैं, उन्हें केवल संदेह या राजनीतिक आरोपों के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य की शक्ति का उद्देश्य नागरिकों को डराना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं न्यायिक संरक्षण का उद्देश्य अराजकता को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि कानून के शासन को मजबूत करना है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को केवल सरकार बनाम कार्यकर्ता या पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी के रूप में देखने के बजाय संवैधानिक संतुलन के प्रश्न के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

-शिवांश धाकड़

कविता

शुल्क लगे तो फिर नकदी लौटेगी

संजय एम तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक)

यूं डिजिटल युग में कदम बढ़े थे,
नकदी से हमने ही नाता तोड़ा था।
हमको यूपीआई ने ही राह दिखाई,
हर भुगतान को सरल बनाया था।
मगर अब शुल्क की आहट हैं आई,
तब तो सोच में पड़ गया हैं बाजार।
ये छोटा-सा चार्ज भी बन सकता है,
नकदी नोट की वापसी का आधार।
हाँ, कभी जेब में सिक्के खनकते थे,
नोटों से होता था सबका कारोबार।
फिर मोबाइल ने यहाँ जगह बना ली,
डिजिटल पेमेंट हुआ हरेक व्यवहार।
कागज के नोटों से मुक्ति का सपना,
ये सुविधा ने सच करके दिखलाया।
लेकिन शुल्क की छोटी-सी दीवार ने,
फिर से नकदी का रास्ता हैं सुझाया।
व्यापारी बोलते हैं लेन-देन सस्ता हो,
ग्राहक बोले-भुगतान सभी सरल हो।
हमेशा तकनीक वो अच्छी कहलाए,
जिसमें हर वर्ग का हित नज़र आए।
आज यूपीआई भारत की पहचान है,
क्या कहें यहीं सुविधा बेमिसाल रहें।
न शुल्क का बोझ बढ़े जनता पे भार,
न नकद की मजबूरी फिर बहाल रहें।
डिजिटल भारत तब सफल कहलाए,
जब सुविधा सभी के द्वार तक जाए।
अब नकदी हो या डिजिटल भुगतान,
जन-जन की जेब पर बोझ ना आए।

नशे की गिरफ्त में फंसती युवा पीढ़ी देश के भविष्य के लिए बढ़ती गंभीर चिंता का विषय

केशव शर्मा
स्वतन्त्र लेखक
गांव-कोटला, घुमारवीं।

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार और सकारात्मक सोच ही देश के विकास की आधारशिला होती है। लेकिन जब यही युवा नशे की गिरफ्त में आने लगें तो यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज, परिवार और राष्ट्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। आज युवाओं में नशे का बढ़ता क्रेज सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसे संकट का रूप ले चुका है, जिस पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

वर्तमान समय में शराब, चरस, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली गोलियां, इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कई युवाओं के बीच एक खतरनाक फैशन या दिखावे का माध्यम बनता जा रहा है। कुछ युवा इसे आधुनिकता, तनाव से मुक्ति या दोस्तों के बीच अपनी पहचान बनाने का साधन समझ बैठते हैं। सोशल मीडिया, फिल्मों और कुछ डिजिटल माध्यमों में नशे को आकर्षक जीवनशैली के रूप में प्रस्तुत किए जाने का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि नशा किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक विनाश की ओर ले जाता है।

युवाओं के नशे की ओर आकर्षित होने के पीछे कई कारण हैं। बेरोजगारी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, परीक्षा और करियर का दबाव, पारिवारिक कलह, अकेलापन, गलत मित्र मंडली, मानसिक तनाव, जिज्ञासा और आसानी से नशीले पदार्थों की उपलब्धता प्रमुख कारणों में शामिल हैं। कई बार युवा केवल प्रयोग के तौर पर नशा शुरू करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इसकी लत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसके बाद उससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नशे की शुरुआत को रोकना, नशे की लत लगने के बाद उपचार करने की तुलना में अधिक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।

नशे का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मादक पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। नशे का आदी युवा पढ़ाई, रोजगार और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होने लगता है। उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और धीरे-धीरे वह अवसाद, चिंता तथा अन्य मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। कई मामलों में नशे की लत व्यक्ति को अपराध, हिंसा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की ओर भी धकेल देती है। इस प्रकार नशा व्यक्ति के वर्तमान के साथ-साथ उसके भविष्य को भी प्रभावित करता है।

नशे की समस्या का सबसे अधिक दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ता है। माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो पूरा परिवार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से गुजरता है। परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है और रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है। कई परिवार अपने बच्चे को नशे से बाहर निकालने के लिए लंबे समय तक उपचार और पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसलिए युवाओं को नशे से बचाना परिवार की जिम्मेदारी के साथ-साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह समस्या केवल परिवार तक सीमित नहीं रहती। नशे के कारण समाज में अपराध, सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

क्रिकेट और राजनीति में शुक्ला

राजीव शुक्ला
जन्म : 13 सितंबर 1959

राजीव शुक्ला भारतीय राजनीति और क्रिकेट प्रशासन की दुनिया में एक चर्चित नाम हैं। उनका जन्म 13 सितंबर 1959 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। उन्होंने कानपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई भी की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। वे हिंदी दैनिक जनसत्ता में रिपोर्टर रहे और बाद में रविवार पत्रिका में विशेष संवाददाता तथा वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2000 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उनका राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा। वर्ष 2003 में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया। वर्ष 2006 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और बाद में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए भी निर्विरोध चुने गए।

राजीव शुक्ला का क्रिकेट प्रशासन में भी लंबा अनुभव रहा है।

वर्ष 1989 में उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से अपने प्रशासनिक सफर की शुरुआत की और बाद में इसके सचिव बने। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने के अलावा वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में विभिन्न समितियों से भी जुड़े। वर्ष 2011 से 2013 तक वे इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2015 में उन्हें दोबारा आईपीएल अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने 2018 तक यह जिम्मेदारी निभाई। दिसंबर 2020 में वे निर्विरोध बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चुने गए और 2022 में दोबारा इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वर्ष 2025 में उन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा जुलाई 2025 से वे अंतरिम बीसीसीआई अध्यक्ष की भूमिका में भी रहे। हालांकि उनका क्रिकेट प्रशासनिक सफर विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। वर्ष 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण के दौरान उन पर दबाव बढ़ा और उन्होंने आईपीएल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वर्ष 2018 में उनके निजी सहायक से जुड़े चयन में कथित रिश्वत मांगने के मामले ने भी सवाल खड़े किए।

जन शिकायतों के प्रभावी समाधान से मजबूत होता है नागरिकों का शासन पर विश्वास

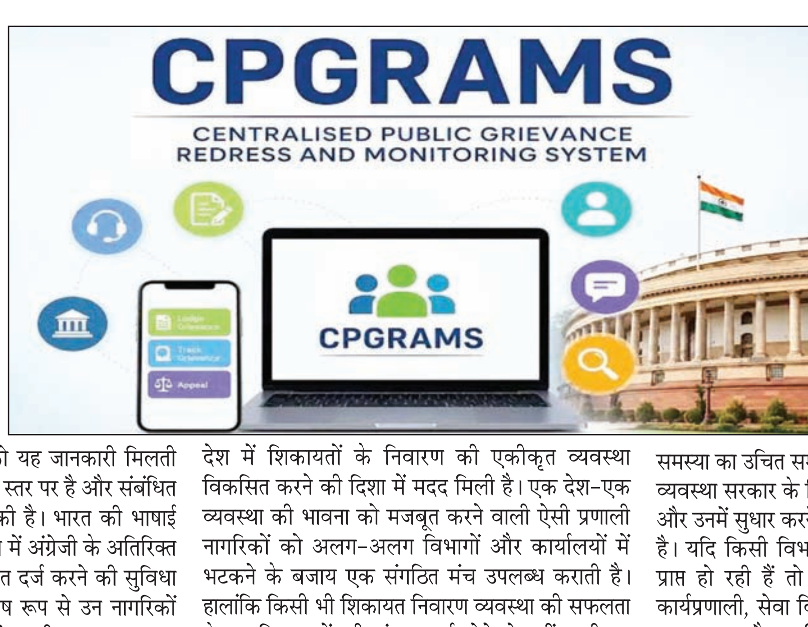

विशाल कल्याण
सहायक प्रोफेसर
महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी सोलन

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी सरकार की सफलता केवल इस आधार पर तय नहीं की जा सकती कि उसने कितनी नीतियां बनाईं या कितनी योजनाएं शुरू कीं। असली कसौटी यह है कि आम नागरिक को इन नीतियों और योजनाओं का लाभ कितना मिला तथा उसकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान कितनी प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया। लोकतंत्र में नागरिक सरकार के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं। इसलिए उनकी बात सुनना, उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेना और उचित समाधान उपलब्ध कराना सुशासन की मूल भावना है। नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी निवारण प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास भी पैदा करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली यानी सीपीग्राम्स की स्थापना की है। पिछले एक दशक में यह देश के प्रमुख डिजिटल लोक शिकायत निवारण मंच के रूप में उभरा है और नागरिकों तथा प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता को उसकी समस्या के समाधान की पूरी प्रक्रिया से जोड़ना भी है।

सीपीग्राम्स के माध्यम से नागरिक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी समस्या लेकर बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है और घर बैठे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलता है। डिजिटल व्यवस्था के कारण शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ हुई है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकता है। यह सुविधा शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ प्रशासनिक तंत्र को जवाबदेह बनाने में भी मदद करती है।

शिकायत दर्ज होने के बाद नागरिक को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह आगे की कार्रवाई और शिकायत की स्थिति देख सकता है। इससे नागरिक को यह जानकारी मिलती रहती है कि उसकी शिकायत किस स्तर पर है और संबंधित विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की है। भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए सीपीग्राम्स में अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 अनुसूचित भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंग्रेजी में अपनी समस्या सहजता से व्यक्त नहीं कर पाते। प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच में भाषा बाधा नहीं बननी चाहिए और स्थानीय तथा भारतीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रकार डिजिटल शिकायत निवारण व्यवस्था केवल तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि प्रशासनिक समावेशन का भी माध्यम बन रही है। सीपीग्राम्स को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की शिकायत निवारण व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। इससे देश में शिकायतों के निवारण की एकीकृत व्यवस्था विकसित करने की दिशा में मदद मिली है। एक देश-एक व्यवस्था की भावना को मजबूत करने वाली ऐसी प्रणाली नागरिकों को अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में भटकने के बजाय एक संगठित मंच उपलब्ध कराती है। हालांकि किसी भी शिकायत निवारण व्यवस्था की सफलता केवल शिकायतों की संख्या दर्ज होने से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता तब होगी जब शिकायतों का समाधान वास्तविक, संतोषजनक और समस्या की मूल वजह को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

सीपीग्राम्स के तहत शिकायतों का यथाशीघ्र निवारण करने का प्रयास किया जाता है और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अधिकतम 21 दिनों के भीतर शिकायतों के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। समयबद्ध निवारण प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करता है और नागरिकों को लंबे समय तक अपनी समस्या के समाधान की प्रतीक्षा करने से बचाता है। लेकिन समय सीमा के साथ समाधान की गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। केवल शिकायत को निस्तारित दिखा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का उचित समाधान होना चाहिए। शिकायत निवारण व्यवस्था सरकार के लिए प्रशासनिक कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बन सकती है। यदि किसी विभाग से बार-बार एक जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो यह संकेत है कि उस विभाग की कार्यप्रणाली, सेवा वितरण या संबंधित नीति में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए शिकायतों को केवल प्रशासन के सामने आने वाली समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। शिकायतों के स्वरूप और उनके कारणों का विश्लेषण करके सरकार उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहां नागरिकों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे नीतियों में आवश्यक बदलाव, सेवाओं में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने में मदद मिल सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

योगी सरकार ने चाइल्ड ट्रैकिंग का बजट बढ़ाया

परिषदीय स्कूलों में एमआईएस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन के लिए 6.55 करोड़ मंजूर

एजेंसी, लखनऊ

हर बच्चे की शैक्षिक जानकारी व्यवस्थित करने के लिए अपार आईडी को चाइल्ड ट्रैकिंग से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस, यू-डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के साथ विद्यार्थियों के नामांकन, शैक्षिक स्थिति और प्रगति की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से विद्यालयी व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं का समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सकेगा।

निर्धारित कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि में एमआईएस यानी यू-डायस प्लस के लिए 262 लाख रुपये और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 393.01 लाख रुपये रखे गए हैं। यह धनराशि विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से निर्धारित गतिविधियों पर खर्च की जाएगी। इसके लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मद में पारदर्शी तरीके से उपयोग हो और उसकी नियमित निगरानी की जाए।

इस व्यवस्था में यू-डायस प्लस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके माध्यम से विद्यालयों और विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन तथा उनके उपयोग को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। वहीं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। एक की विशेष प्राथमिकता विद्यार्थियों की विशिष्ट अपार आईडी को चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने की है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की पहचान और उससे संबंधित शैक्षिक जानकारी को एक व्यवस्थित डिजिटल व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकेगा। इसके माध्यम से बच्चों के नामांकन और उनकी शैक्षिक स्थिति की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक निगरानी की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रबंध समितियों के स्तर पर हुए खर्च की प्रगति की समीक्षा करने तथा निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल व्यवस्था में बढ़ेगी जवाबदेही: सीएम योगी

इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बजट का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के अनुसार सरकार विद्यालयी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर रखना चाहती है। एमआईएस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बेहतर उपयोग से बच्चों से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करने में नई मजबूती मिलेगी।

बांदा की 11 बेटियों का राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिता में चयन

बरेली में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी खेल प्रतिभा

एजेंसी, बांदा

मिनी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम।

बांदा की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन किया है। केजीबीवी यूनिट टीम में बड़ोखर खुर्द की आठ और महुआ केजीबीवी की तीन समेत कुल 11 बालिकाओं का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 12 से 22 सितंबर तक आयोजित यूनिट कैंप के विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी। इसके बाद 23 से 26 सितंबर तक बरेली में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। टीम के कोच प्रदीप वर्मा तथा मैनेजर सुमन सिंह और अर्चना वर्मा के मार्गदर्शन में बालिकाएं प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटेंगी।

इन खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित बांदा मिनी ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय टीम में चयन को जिले की बालिका खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बालिकाओं के चयन की जानकारी मिलते ही केजीबीवी परिवार, अभिभावकों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी सहित जिला ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों, कोच और मैनेजर को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेंद्र शर्मा, महासचिव डॉ. इंद्रवीर सिंह, मीडिया प्रभारी सुनील सक्सेना, लेखाकार रामविलास राजपूत, प्रभारी वार्डन कविता गुप्ता और जिला समन्वयक बालिका शिक्षा प्रभात शुक्ला ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उम्मीद जताई कि बांदा की ये प्रतिभाशाली बेटियां राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगी।

68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य का आवास

एजेंसी, लखनऊ

◆ ओबीसी आरक्षण के आधार पर की संशोधित परिणाम की मांग

लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण संबंधी मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने मांग की कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का पालन करते हुए ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाए और पूर्णांक 150 में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर संशोधित परिणाम जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने माना था कि ओबीसी वर्ग को पांच प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए थी। उनका कहना है कि भर्ती विज्ञापन और प्रक्रिया के दौरान इसका पालन नहीं किया गया। अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के करीब सात वर्ष बाद इस मामले में उच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है।

बैठक में अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुपालन और संशोधित परिणाम जारी करने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता करने का आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से ईको गार्डन भेज दिया।

पश्चिमी यूपी में 15-16 सितंबर को बढ़ेगा बारिश का दायरा

एजेंसी, लखनऊ

◆ बारिश के साथ बिजली चमकने का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों के मौसम को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर तथा 18 सितंबर को कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 15 से 17 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद 15 और 16 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़ सकता है और कई स्थानों पर बौछारें पड़ने की संभावना है।

17 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 18 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को गरज-चमक तथा बिजली गिरने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को फसलों को जलभराव से बचाने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

13 सितंबर को शिवमहापुराण कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल

रायबरेली कथा में मुख्यमंत्री योगी समेत कई विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे

एजेंसी, रायबरेली

रायबरेली में पंडित प्रदीप मिश्र की श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ चल रहा है। कथा के पहले और दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथा में जहां देश-प्रदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं विशिष्ट अतिथियों और वीआईपी के आने का सिलसिला भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को कथा में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की है।

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। ऊंचाहार के इटौरा टोल प्लाजा स्थित आयोजन स्थल पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है और भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। आयोजन स्थल पर कई जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है तथा अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है। आयोजक एवं प्रदेश सरकार के खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडे के अनुसार 14 सितंबर को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, 15 सितंबर को तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल और 16 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कथा में शामिल होने के कार्यक्रम तय हैं।

ब्रिक्स डायलॉग 2026 में यूपी की आवाज बनी बलिया की बेटी स्मृति सिंह

एजेंसी, बलिया

◆ ब्रिक्स डायलॉग में स्मृति सिंह ने उठाए महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के मुद्दे

दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स डायलॉग 2026 में उत्तर प्रदेश की युवा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधान स्मृति सिंह ने सहभागिता कर जिले का मान बढ़ाया है। वह शनिवार को उत्तर प्रदेश से इस संवाद में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुईं और ब्रिक्स देशों से आए विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर भारत तथा ग्रामीण भारत का पक्ष रखने का अवसर प्राप्त किया।

संवाद के दौरान स्मृति सिंह ने महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा विकास, स्वच्छता एवं सामाजिक विकास जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने ग्रामीण भारत में महिलाओं और युवाओं को बढ़ती भागीदारी तथा जमीनी स्तर पर हो रहे सकारात्मक बदलावों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष साझा किया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली स्मृति सिंह महिला सशक्तिकरण और मेंसट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें विलेज पैड गर्ल के नाम से पहचान मिली है।

स्मृति सिंह ने कहा कि 'ब्रिक्स डायलॉग जैसे अंतराष्ट्रीय मंच पर भारत की बात रखने और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज, महिलाओं एवं युवाओं की आवाज को वैश्विक प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर मेरे लिए गौरव का विषय है।' उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच महिला नेतृत्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा सहभागिता के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।

लड़की से मिलवाने के बहाने युवक से 17 .98 लाख ठगे

◆ पहले लड़की से मिलवाने का झांसा, फिर वीआईपी सदस्यता और क्रेडिट स्कोर के नाम पर ठगी

एजेंसी, नोएडा। नोएडा में साइबर अपराधियों ने फ्लर्टीफाई क्लब के माध्यम से लड़की से मिलवाने का झांसा देकर लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे से 17.98 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित निखिल कुमार रस्तोगी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, निखिल शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। 27 अगस्त को टेलीग्राम एप पर फ्लर्टीफाई क्लब के जरिए उनकी एक लड़की से बातचीत हुई। आरोप है कि लड़की ने उन्हें क्लब की वीआईपी सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए कुछ कार्य पूरे करने को कहा।

पीड़ित ने बताया कि कार्य पूरे करने के बाद अलग-अलग खातों में करीब 17.98 लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद आरोपितों ने उन्हें बताया कि उनका क्रेडिट स्कोर कम है और इसे बढ़ाने के लिए सात लाख 16 हजार रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे। ठगों ने दावा किया कि उनके वॉलेट में 17.98 लाख 348 रुपये लंबित हैं और राशि प्राप्त करने के लिए और भुगतान जरूरी है। संदेह होने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।

इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों द्वारा इस्तेमाल किए गए खातों, टेलीग्राम संपर्क और लेन-देन की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन दोस्ती, वीआईपी सदस्यता और क्रेडिट स्कोर सुधारने जैसे झांसे में आकर किसी अनजान व्यक्ति को धनराशि नहीं भेजनी चाहिए। इंटरनेट पर संबंध बनाने या मिलने-जुलने के नाम पर होने वाली गतिविधियों में सावधानी बरतना जरूरी है।

पीएम यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरी को मिलेगा नया बाजार

एजेंसी, लखनऊ

◆ आगरा में 128 करोड़, वाराणसी में 154 करोड़ से बन रहे यूनिटी मॉल, लखनऊ में भी काम तेज

स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरी को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगरा, वाराणसी और लखनऊ में आधुनिक पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इन मॉल का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित और विपणन करने के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है, जिससे कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को बड़े बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी और जीआई-टैग उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ रहे परंपरागत उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार की ओर से बढ़ाया गया यह कदम न सिर्फ शिल्पकारों की आजीविका को मजबूत कर रहा है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को 'स्वदेशी की नई ताकत' के रूप में स्थापित भी कर रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएम यूनिटी मॉल राज्यों में स्थानीय उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और ब्रांडिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है।

आगरा के शिल्पग्राम क्षेत्र में लगभग 11.53 एकड़ भूमि पर करीब 128.85 करोड़ रुपये की लागत से पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। बेसमेंट की खुदाई, फाउंडेशन की पीसीसी, आरसीसी, बेसमेंट फ्लोर के कॉलम एवं रिटेनिंग बाल की आरसीसी का कार्य 100 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। यहां ब्रज क्षेत्र, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों के हस्तशिल्प व पारंपरिक उत्पादों को ब्रांडिंग के साथ देश-विदेश के बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। 06 फ्लोर के मॉल में कुल 135 दुकानें होंगी। यह मॉल नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

वाराणसी के गंगानगर कॉलोनी में करीब 154.71 करोड़ रुपये की लागत से 1.46 एकड़ क्षेत्र में यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। डी-वाल और छत की स्लैब की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि बेसमेंट 03 में फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है।

हरदोई रोडवेज के 328 आउटसोर्स कर्मचारी बनेंगे संविदाकर्मी

30 सितंबर तक संविदा व्यवस्था में शामिल होंगे रोडवेज के कर्मचारी

एजेंसी, हरदोई

कर्मचारियों की बढ़ेगी आय, यात्रा पास और पीएफ का भी लाभ।

हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 328 आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। निगम की ओर से 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निर्णय से लंबे समय से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक इन कर्मचारियों की सेवाएं परिवहन निगम के विभिन्न डिपो और कार्यालयों में एजेंसियों के माध्यम से ली जा रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को सीधे निगम के संविदा कर्मियों के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा के अनुसार वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों को 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। संविदा व्यवस्था में शामिल होने के बाद यह भुगतान बढ़कर 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगा। इस बदलाव से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा। इसके साथ ही संविदा व्यवस्था के तहत उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की भी उम्मीद है। इनमें कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए यात्रा पास तथा भविष्य निधि यानी पीएफ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ के साथ ही सेवा से जुड़ी सुविधाओं का भी फायदा मिल सकेगा।

निगम में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कर्मचारी लंबे समय से अलग-अलग डिपो और कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को काम पर लगाए जाने की व्यवस्था में उन्हें निगम के सीधे संविदा कर्मियों के समान सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब संविदा व्यवस्था में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। निगम की तैयारी के अनुसार 30 सितंबर तक मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा व्यवस्था में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

नई व्यवस्था से कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के साथ उनकी सेवा संबंधी स्थिति भी बेहतर होने की संभावना है। वर्तमान भुगतान दर और प्रस्तावित संविदा भुगतान दर में अंतर होने के कारण कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी। परिवार के लिए यात्रा पास और पीएफ जैसी सुविधाएं मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकती है। लंबे समय से निगम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चेतावनी गंगा के बढ़ते जलस्तर से कानपुर में अलर्ट, बैराज पर लगातार बढ़ रहा पानी

कानपुर में गंगा का जलस्तर चार सेंटीमीटर बढ़ा

एजेंसी, कानपुर

कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने नदी किनारे बसे बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। शनिवार को कानपुर बैराज के अपस्ट्रीम में गंगा का जलस्तर 114.750 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी बिंदु से 75 सेंटीमीटर ऊपर और खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे है। शुक्रवार की तुलना में जलस्तर में चार सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गंगा के जलस्तर के साथ-साथ विभिन्न बैराजों से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा की भी लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कानपुर बैराज पर शुक्रवार को अपस्ट्रीम में गंगा का जलस्तर 114.710 मीटर दर्ज किया गया था, जो शनिवार को बढ़कर 114.750 मीटर पहुंच गया। इसी तरह डाउनस्ट्रीम में भी जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई।

बैराज पर जलस्तर 114.750 मीटर पहुंचा

शुक्रवार को डाउनस्ट्रीम जलस्तर 114.350 मीटर था, जबकि शनिवार को यह बढ़कर 114.380 मीटर हो गया। बैराज से पानी के डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को जहां चार लाख 17 हजार 201 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था, वहीं शनिवार को यह बढ़कर चार लाख 21 हजार 854 क्यूसेक पहुंच गया। इससे नदी में पानी की बढ़ती मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर, शुक्लागंज में भी गंगा का जलस्तर चार सेंटीमीटर बढ़ा है। शनिवार को यहां जलस्तर 113.100 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। शुक्रवार को शुक्लागंज में जलस्तर 113.060 मीटर था।

गंगा के जलस्तर में इस बढ़ोतरी से नदी किनारे रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ सकती है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के साथ स्थानीय अधिकारियों को स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार और नरोरा बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हरिद्वार बैराज से 89 हजार 197 क्यूसेक और नरोरा बैराज से 77 हजार 819 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इन बैराजों से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा को देखते हुए कानपुर में गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखना आवश्यक है।

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट

जिला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जलस्तर में होने वाले बदलावों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने तथा प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव से संबंधित व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जलस्तर में अचानक वृद्धि होने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। प्रशासन जलस्तर, बैराजों से पानी के डिस्चार्ज और संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर लगातार जानकारी जुटा रहा है।

हाइराइज इमारतें बढ़ीं, फायर सुरक्षा इंतजाम अब भी नाकाफी

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

ग्रेटर फरीदाबाद में 30 से 35 मंजिला हाइराइज सोसाइटियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इनके मुकाबले अग्निशमन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। क्षेत्र में एक भी हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ऊंची मंजिलों पर आग लगने की स्थिति में हजारों लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि मौजूदा दमकल उपकरण करीब 10वीं मंजिल तक ही प्रभावी रूप से पहुंच पाते हैं। वहीं ग्रेटर फरीदाबाद से फायर स्टेशन की दूरी आठ से 10 किलोमीटर है। दमकल वाहनों को मौके पर पहुंचने में 25 से 30 मिनट तक लग जाते हैं। आग की स्थिति में यह देरी बड़ा नुकसान कर सकती है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कई सोसाइटियों में फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर खराब पड़े हैं और फायर अलार्म भी काम नहीं करते। नवंबर 2021 में सेक्टर-70

स्थित रायल हेरिटेज सोसायटी में आग लगने के दौरान फायर सिस्टम के नाकाम रहने पर स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने में मदद की थी।

ग्रेटर फरीदाबाद में 50 से अधिक सोसायटियां और तीन लाख से ज्यादा परिवार हैं। यहां 33 से 35 मंजिल तक के टावर हैं। जिले में छह अग्निशमन केंद्र, 24 दमकल वाहन, 12 बाइक और 115 कर्मचारी हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि बढ़ती आबादी और ऊंची इमारतों को देखते हुए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के साथ दमकल संसाधनों में भी बढ़ोतरी जरूरी है। लोगों ने प्रशासन से किसी बड़े हादसे से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

राफेल तस्वीरें पाकिस्तान भेजने के आरोपी को हाईकोर्ट से कोई जमानत नहीं

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात राफेल लड़ाकू विमानों की कथित तौर पर तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान की एक महिला को भेजने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए इस स्तर पर आरोपी को राहत देना उचित नहीं माना।

आरोप है कि याची ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से संबंधित संवेदनशील तस्वीरें खींचीं और उन्हें पाकिस्तान की एक महिला के साथ साझा किया। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन तस्वीरों में राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित जानकारी दिखाई देती थी। सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़ी तस्वीरों के कथित तौर पर पड़ोसी देश में साझा किए जाने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीर माना है।

आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर राहत की मांग की गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच से जुड़े पहलुओं का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत के समक्ष मामला केवल तस्वीरें खींचने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान की महिला तक पहुंचाने का आरोप भी था। अदालत के इस फैसले से आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिली है और मामले की जांच जारी रहेगी।

चरखी दादरी में 4.51 करोड़ से बनेंगी 11.6 किमी सड़कें, 12 हजार वाहन चालकों को मिलेगी राहत

टेंडर प्रक्रिया शुरू, ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण से आवागमन होगा सुगम और सुरक्षित

भारतेन्दु संवाददाता, चरखी दादरी

चरखी दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली तीन महत्वपूर्ण सड़कों की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने घसोला-भैरवी, चिड़िया-पोता और रामनगर-घसोला संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण व नवनिर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 11.6 किलोमीटर लंबी इन तीनों सड़कों के निर्माण पर 4.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिदिन आवागमन करने वाले 12 हजार से अधिक वाहन चालकों और आसपास के ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

इन संपर्क मार्गों की हालत पिछले काफी समय से खराब थी। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार वाहनों में

तकनीकी खराबी आने के साथ हादसों का खतरा भी बना रहता था। ग्रामीण लंबे समय से इन सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों की ओर से भी मामला विभाग और सरकार के समक्ष उठाया गया था।

लोगों की मांग और यातायात के दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण का एस्टिमेट तैयार कर सरकार को भेजा। मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द धरातल पर काम शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।

तीनों सड़कों की बदलेगी सूरत : घसोला-भैरवी मार्ग करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा।

चिड़िया-पोता मार्ग करीब पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण होने से कृषि आधारित गतिविधियों और भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। रामनगर-घसोला मार्ग करीब 2.11 किलोमीटर लंबे इस संपर्क मार्ग से आसपास की ढाणियों और मुख्य मार्ग के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

12 हजार से अधिक वाहन चालकों को फायदा : इन सड़कों के निर्माण से रोजाना गुजरने वाले 12 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों को सुगम और सुरक्षित आवागमन मिलेगा। जर्जर सड़कों के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च करना पड़ता है। सड़कें बेहतर होने से सफर का समय घटने के साथ वाहनों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होने की उम्मीद है।

आईआईटी की तकनीक से गुरुग्राम में जलभराव का होगा स्थायी समाधान

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

गुरुग्राम में मानसून के दौरान होने वाले जलभराव से निपटने के लिए अब बरसाती पानी को शहर से बाहर निकालने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर रोककर भूजल रिचार्ज करने की योजना बनाई जा रही है। आईआईटी गांधीनगर की रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।

योजना के तहत इंजेक्शन वेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, भूमिगत वाटर टैंक, नए तालाब और जलाशय विकसित किए जाएंगे। आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञों ने 50 लीटर प्रति सेकंड क्षमता वाले इंजेक्शन वेल का डिजाइन तैयार किया है। पालम विहार में इसकी तकनीक की टेस्टिंग भी की जा चुकी है।

जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने बताया कि आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पांच रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। सेक्टर-31 की ग्रीन बेल्ट में बने एक स्ट्रक्चर से एक बारिश में करीब 13 लाख लीटर पानी जमीन में रिचार्ज होने की पुष्टि हुई है।

मानेसर निगम क्षेत्र के 15 गांवों में बड़े जलाशयों के लिए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। वहीं, अरावली के प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश का पानी रोकने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। जापानी कंपनी निपोनकोई अगले महीने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी।

हिसार में ऑटो-ई-रिक्शा चालकों की पहचान होगी आसान, ग्रे वर्दी अनिवार्य

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

शहर में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के चालकों को निर्धारित ग्रे रंग की वर्दी पहननी होगी। इसके साथ ही शर्ट के बाईं ओर निर्धारित बैज लगाना भी जरूरी होगा।

यातायात पुलिस का मानना है कि एक जैसी वर्दी और बैज होने से यात्रियों को चालक की पहचान आसानी से हो सकेगी। किसी अप्रिय घटना या शिकायत की स्थिति में भी चालक की पहचान करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित वर्दी और बैज संबंधी नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी व्यवस्था को लेकर

यातायात थाना पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ जागरूकता बैठक की। बैठक में यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने चालकों को नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और नियमों का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय चालक सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। यात्रियों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही बैठाया और उतारा जाए। क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने से बचें, क्योंकि ओवरलोडिंग से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने चालकों को मनमर्जी से सड़क पर कहीं भी सवारी बैठाने या उतारने से भी बचने की हिदायत दी।

पुलिस ने चालकों के व्यवहार को भी यातायात व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार किया जाए और सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूरी तरह पालन हो। चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई। बैठक में मौजूद चालकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।

रेवाड़ी में अवैध पेट्रोल-डीजल सप्लाई का भंडाफोड़, सात ड्रम जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार रात गांव गुजरीवास में छापेमारी कर अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल के भंडारण और सप्लाई का भंडाफोड़ किया। टीम ने खेत के अंदर बने एक प्लाट से एक हजार लीटर से अधिक पेट्रोल-डीजल बरामद किया। मौके से पेट्रोल-डीजल से भरे सात ड्रम और एक पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गुजरीवास गांव में खेत के अंदर बने प्लाट में अवैध तरीके से पेट्रोल-डीजल जमा किया जा रहा है। यहां से आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई किए जाने की भी जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने बताए गए स्थान पर कार्रवाई की। प्लाट की तलाशी के दौरान सात ड्रम मिले, जिनमें बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल भरा हुआ था। इसके अलावा वहां एक पिकअप गाड़ी भी खड़ी मिली। पुलिस ने वाहन और बरामद पेट्रोल-डीजल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा में लंपी का खतरा बढ़ा पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

दो वर्ष पहले पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला लंपी वायरस एक बार फिर हरियाणा की चौखट तक पहुंच गया है। सात राज्यों में संक्रमण मिलने तथा भिवानी, नारनौल और कुरुक्षेत्र में मामले सामने आने के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है।

विभाग ने पशुओं के अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और गोशालाओं में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हिसार में अभी लंपी वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संक्रमण की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं।

जिलों को जारी एडवाइजरी में गोशालाओं में नए पशुओं के

प्रवेश और निकास पर नियंत्रण रखने तथा नए पशुओं को कम से कम 15 दिन अलग रखने को कहा गया है। संक्रमित या संदिग्ध पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग ने बीमारी फैलाने वाले मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों की रोकथाम के लिए फागिंग, शेड और नालियों की नियमित सफाई कराने पर जोर दिया है। पशुपालकों से किसी भी पशु में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल पशु चिकित्सक को सूचना देने की अपील की गई है।

फरीदाबाद में डेंगू-मलेरिया के साथ स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

बदलते मौसम और बारिश के बाद फरीदाबाद में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 13, मलेरिया के तीन और स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आ चुके हैं। एक साथ कई बीमारियों के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है।

बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की करीब 40 टीमें जिले के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर मच्छरों के लार्वा की जांच और सैंपलिंग कर रही हैं। टीमें घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने वाले स्थानों की भी जांच कर रही हैं। विशेष रूप से कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, खाली बर्तनों और अन्य कंटेनरों में जमा पानी की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन स्थानों पर पानी जमा रहने से डेंगू और

मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पनप सकता है।

जांच के दौरान जहां भी मच्छरों का लार्वा पाया जा रहा है, वहां लोगों को पानी जमा न होने देने की हिदायत दी जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को जरूरत के अनुसार नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 1,660 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि विभाग बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रहा है। डेंगू और मलेरिया के साथ स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आने के बाद इसकी भी निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और रात में मच्छरदानी या अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करें। विभाग ने लोगों से बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज न करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है।

अमृता देवी के बलिदान से प्रेरणा हरियाली के लिए रोपे 150 पौधे

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणास्रोत शहीद मां अमृता देवी और उनकी तीन बेटियों सहित 363 पर्यावरण प्रेमियों की शहादत को नमन करते हुए शहीद मां अमृता देवी पर्यावरण ट्रस्ट की ओर से सेक्टर-33 में पौधारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के करीब 150 पौधे लगाए गए।

कार्यक्रम में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. नरसी बिश्नोई और मेयर प्रवीण पोपली मुख्य अतिथि रहे। सेक्टरवासियों ने दोनों अतिथियों का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया।

ट्रस्ट के संस्थापक राजपाल नैन ने बताया कि ट्रस्ट के गठन के बाद सेक्टर-33 में यह पहला पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में मोलसरी, बेलपत्र, अशोक, खेजड़ी और कचनार समेत कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि मां अमृता देवी ने पेड़ों और प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण को जन-अभियान बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

ट्रस्ट प्रधान जगदीश गोदारा ने बताया कि सेक्टरवासियों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सहयोग से नवंबर तक सेक्टर-33 के सभी पार्कों में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतनमान पर समिति की मुहर

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में शुक्रवार को वेतनमान विसंगतियों को लेकर गठित रजिस्ट्रार समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया।

बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक एवं एमडीयू के रजिस्ट्रार प्रो. संदीप बंसल ने की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों, वेतनमान और वर्तमान में लागू व्यवस्थाओं की तुलनात्मक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित आंकड़े और तथ्य बैठक में प्रस्तुत किए। इस दौरान उन पदों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जहां समान प्रकृति का कार्य करने वाले गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर पाया गया है। सदस्यों ने इन विसंगतियों के संभावित कारणों का भी अध्ययन किया।

बैठक में उपलब्ध रिकॉर्ड और आंकड़ों का दोबारा परीक्षण किया गया। समिति ने यह समझने का प्रयास किया कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों में समान पदों के लिए वेतनमान में अंतर किन कारणों से उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही विसंगतियों को दूर करने के लिए संभावित विकल्पों और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

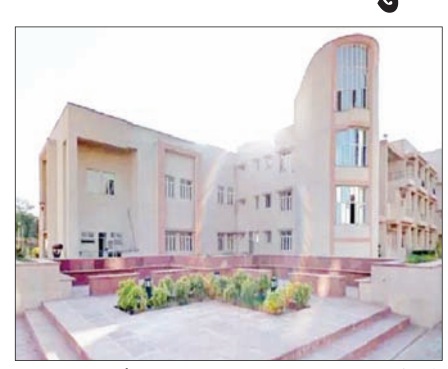

समिति के समक्ष विश्वविद्यालयवार रिकॉर्ड रखे जाने के बाद सदस्यों ने सामूहिक रूप से सभी तथ्यों की समीक्षा की। चर्चा के दौरान पदों की समानता, कार्य की प्रकृति, मौजूदा वेतनमान और विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्थाओं को प्रमुख आधार बनाया गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया। अब इन सिफारिशों पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इससे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समान प्रकृति के पदों पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे होने वाली कार्रवाई से कर्मचारियों को वेतनमान में समानता और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम निर्णय और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया संबंधित स्तर पर आगे तय की जाएगी।

फतेहाबाद में 58 लाख की कोकीन के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

सीआईए टोहाना की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भूना रोड फ्लाईओवर के पास एक कार से 114.19 ग्राम कोकीन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की अनुमानित कीमत करीब 58 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके से दो युवकों और एक महिला को गिरफ्तार करने के साथ तस्करी में इस्तेमाल हुंडई औरा कार को भी कब्जे में लिया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भिवानी के गांव खानक निवासी सोनू कुमार, हिसार के नलवा निवासी रविन्द्र शर्मा और नई दिल्ली के मोतीनगर निवासी निशा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सोनू फिलहाल मॉडल टाउन, हिसार और निशा आईटीआई चौक के नजदीक, हिसार में रह रही थी।

सहायक पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला ने शनिवार को

पत्रकारों को बताया कि सीआईए टोहाना प्रभारी उपनिरीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में एएसआई जतिन्द्र सिंह की टीम 11 सितंबर को नया बस अड्डा फतेहाबाद क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक हुंडई औरा कार में दो युवक और एक महिला भारी मात्रा में कोकीन लेकर भूना रोड फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर खड़े हैं और ग्राहकों को नशीला पदार्थ बेचने की तैयारी में हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही कार चालक ने वाहन को तेजी से भगाने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया। नियमानुसार तलाशी लेने पर आरोपियों और कार से 114.19 ग्राम कोकीन बरामद हुई।

इस मामले में थाना शहर फतेहाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि कोकीन की खेप कहां से लाई गई थी, इसका मुख्य सप्लायर कौन है और इसे जिले में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई केवल नशीला पदार्थ जब्त करने तक सीमित नहीं रहेगी।

डबवाली में छह-छह माह की प्रधानगी तय, यमुनानगर में 558 मतों से मिली बड़ी जीत, फतेहाबाद में त्रिकोणीय मुकाबले में सुभाष जांगू विजयी

बार चुनावों में कहीं टाई, कहीं पांच मतों से जीत, रोहतक में अटका परिणाम

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

पानीपत जिला बार एसोसिएशनों के चुनाव में शुक्रवार को प्रधान पद के नतीजों ने मुकाबलों की नजदीकी से लेकर बड़े मतांतर तक कई रंग दिखाए। डबवाली में दो प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने के बाद छह-छह माह की प्रधानगी पर सहमति बनी। वहीं पलवल में महज पांच मतों के अंतर से जीत-हार का फैसला हुआ। यमुनानगर में 558 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की गई। दूसरी ओर रोहतक में ईवीएम से मतगणना कराने को लेकर विवाद के चलते परिणाम अटक गया।

डबवाली में बराबर मत, छह-छह माह की प्रधानगी : डबवाली बार एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव में राजपाल सिधू और काली देवी आमने-सामने थे। दोनों प्रत्याशियों को 126-126 मत मिले। बराबर मत आने के कारण किसी एक को विजेता घोषित करना संभव नहीं हुआ। इसके बाद दोनों को छह-छह माह के लिए प्रधान बनाए जाने पर सहमति बनी। तय व्यवस्था के अनुसार राजपाल सिधू पहले छह माह प्रधान रहेंगे, जबकि इसके बाद काली देवी जिम्मेदारी संभालेंगी।

पलवल में पांच मत बने जीत-हार का अंतर : पलवल में प्रधान पद का मुकाबला बेहद करीबी रहा। दीपक चौहान ने 858 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि नेत्रपाल चौहान को 853 मत मिले। इस तरह दीपक चौहान केवल पांच मतों के अंतर से विजयी रहे। तीसरे प्रत्याशी वेद प्रकाश गौड़ को आठ मत मिले। कुल 1893 मतदाताओं में से 1719 ने मतदान किया।

यमुनानगर में 558 मतों से बड़ी जीत : यमुनानगर में दिनेश चौहान ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 1100 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी प्रदीप राठौर को 542 मत हासिल हुए। दोनों के बीच 558 मतों का अंतर रहा। यह चुनाव के प्रमुख बड़े मतांतरों में शामिल रहा।

फतेहाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला : फतेहाबाद में प्रधान पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। सुभाष जांगू ने 307 मत लेकर जीत हासिल की। विनय शर्मा को 160 और विकास कड़वासरा को 152 मत मिले। जांगू ने दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को 147 मतों से हराया। वहीं दूसरे और तीसरे प्रत्याशी के बीच महज आठ मतों का अंतर रहा।

टोहाना में प्रगट सिंह मान ने 240 मत हासिल कर 181 मतों से जीत दर्ज की।

छोटी बार एसोसिएशनों में भी कांटे की

◆ **कैथल में पूर्व विधायक के बेटे को 101 मतों से मिली हार**

टक्कर : सफीदों में पुरुषोतम राणा ने हरिश वशिष्ठ को 11 मतों से हराया। सिवानी में विजय खिचड़ ने राजीव श्योराण को 13 मतों से पराजित किया। नारनौंद में प्रदीप लोहान सात मतों के अंतर से विजयी रहे। नारायणगढ़ में सुरेश कालूवा ने अमर सैनी को 78 मतों से हराया, जबकि पटौदी में मुनीष कुमार चौहान ने 86 मतों से अध्यक्ष पद हासिल किया।

सोहना में एकतरफा रहा मुकाबला : सोहना में अमित यादव ने प्रधान पद का चुनाव 371 मतों के बड़े अंतर से जीता। उन्हें 558 मत मिले, जबकि महावीर प्रसाद को 187 और सुनील कुमार विकल को 83 मत प्राप्त हुए। चुनाव ईवीएम से कराया गया था और कुल 883 मतदाता थे।

रोहतक में मतगणना को लेकर विवाद : रोहतक जिला बार एसोसिएशन में चुनाव के बाद मतगणना शुरू नहीं हो सकी। ईवीएम को बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा ले जाकर मतगणना कराने की बात सामने आने के बाद पूर्व प्रधान लोकेंद्र फोगाट समेत अन्य अधिवक्ताओं ने धरना शुरू कर दिया।

ब्रिक्स मेहमानों के लिए स्मारकों पर एएसआई अलर्ट

कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किले पर नोडल अधिकारी तैनात, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के संभावित ऐतिहासिक स्मारक भ्रमण को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला समेत तीन विश्व धरोहर स्मारकों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, फिलहाल इन स्मारकों में आम पर्यटकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पर्यटक सामान्य दिनों की तरह इन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। लेकिन यदि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या विशिष्ट अतिथि का दौरा तय होता है तो सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए आम पर्यटकों की आवाजाही को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है।

तीन विश्व धरोहर स्मारकों पर विशेष निगरानी : विदेशी मेहमानों के संभावित भ्रमण को ध्यान में रखते हुए एएसआई की ओर से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किले में व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। स्मारकों पर तैनात नोडल अधिकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क में रहेंगे और किसी भी संभावित दौरे को लेकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करेंगे।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल कौन-कौन से विदेशी नेता इन स्मारकों का दौरा करेंगे। हालांकि, संभावित भ्रमण को देखते हुए एएसआई को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरत के अनुसार स्मारकों की गतिविधियों को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है।

आधिकारिक कार्यक्रम में स्मारक भ्रमण का उल्लेख नहीं

12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के आधिकारिक कार्यक्रम में नेताओं की बैठक, भारत नवाचार प्रदर्शनी, पौधरोपण और रात्रिभोज समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। उपलब्ध आधिकारिक कार्यक्रम में कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या लाल किले के दौरे का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद संभावित भ्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने एएसआई को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इन तीन विश्व धरोहर स्मारकों को संभावित दौरे के लिए तैयार रखा गया है। विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम में अंतिम समय पर बदलाव होने की स्थिति में भी सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल लागू किया जा सकेगा। एएसआई के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्मारकों में पर्यटकों की सामान्य आवाजाही जारी रहेगी। किसी विदेशी मेहमान के दौरे की पुष्टि होने पर सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश के अनुसार कुछ समय के लिए प्रवेश और आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है।

आम पर्यटकों का प्रवेश फिलहाल जारी : कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किले में आम पर्यटकों के लिए प्रवेश फिलहाल जारी है। किसी स्मारक को पूरी तरह बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। यदि किसी विदेशी मेहमान का कार्यक्रम अचानक तय होता है तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत संबंधित स्मारक में पर्यटकों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है। एएसआई को ऐसे संभावित दौरे की सूचना पहले दिए जाने की बात कही गई है, ताकि सुरक्षा और पर्यटकों की व्यवस्था को उसी के अनुसार नियंत्रित किया जा सके।

सोहना की स्ट्रीट लाइट में बड़ा घोटाला, 80 लाख की चपत; 11 पर एसीबी का शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली

नगर परिषद सोहना में करीब एक दशक पहले हुए स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला फिर सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वर्ष 2014-15 में करीब 4.87 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए इस प्रोजेक्ट की प्राथमिक जांच के बाद तत्कालीन चीफ इंजीनियर, एसडीओ, नगर परिषद के दो तत्कालीन सचिवों और तीन ठेकेदारों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से नियमों को दरकिनार किया गया और सरकारी खजाने को 80 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय क्षति पहुंची। एसीबी की जांच में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट सामग्री की खरीद पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि बाजार में उपलब्ध दरों की तुलना में करीब 20 से 25 प्रतिशत अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी गई।

अब जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि सामग्री की दरें किस आधार पर तय की गईं और खरीद प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका रही।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि प्रोजेक्ट की खरीद और कार्य आवंटन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि कुछ ठेकेदारों को उनकी निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक राशि के कार्य आवंटित किए गए। नियमानुसार सरकारी निर्माण एवं विकास कार्यों में ठेकेदारों को उनकी श्रेणी और लाइसेंस क्षमता के आधार पर ही काम दिया जाना चाहिए। एसीबी अब यह जांच करेगी कि संबंधित अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी किस आधार पर की और इससे किसी ठेकेदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिला या नहीं।

आईजीआई एयरपोर्ट पर 4.9 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली । दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर कस्टम विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। आरोपित बैंकाक से दिल्ली पहुंचा था और अपने ट्रॉली बैग में करीब 4.969 किलो गांजा छिपाकर ला रहा था। कस्टम अधिकारियों ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यात्री को ग्रीन चैनल पार करते समय रोक लिया। कस्टम विभाग के अनुसार, बैंकाक से आई उड़ान संख्या एकेजे-230 से पहुंचे यात्री की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर प्रोफाइलिंग की गई थी।

दिल्ली में गणेश उत्सव की तैयारी तेज मिट्टी में उतर रहे गणपति के नए रूप

एजेंसी, नई दिल्ली

गणेश उत्सव नजदीक आते ही दिल्ली में गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेज हो गया है। करोल बाग और राजेंद्र नगर के बीच झंडेवालान मंदिर के पास फुटपाथ पर सजे बाजार में राजस्थान, महाराष्ट्र और कोलकाता से आए कारीगर दिन-रात प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हैं। पारंपरिक प्रतिमाओं के साथ इस बार बाल गणेश, सिंहासन पर विराजमान गणपति, कार पर सवार गणपति और अलग-अलग मुद्राओं वाली प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। कारीगर करीब 15 दिन से एक माह की मेहनत के बाद प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। चेहरे की भाव-भंगिमा, आंखों की बनावट, हाथ-पैर की मुद्रा, रंग और आभूषणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छह से आठ फीट तक की प्रतिमाएं करीब 25 से 30 हजार रुपये में उपलब्ध हैं। राजस्थान से आए श्रवण कुमार पिछले 25 वर्षों से प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह काम उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है।

पुलिस की कार्रवाई से कारीगरों की चिंता बढ़ी, बिक्री प्रभावित होने का डर

कारीगरों के सामने अब प्रतिमाओं की बिक्री को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है। जिन स्थानों पर उन्होंने अस्थायी दुकानें और बिक्री स्थल बनाए हैं, उन्हें पुलिस की ओर से हटाने के लिए कहा गया है। इससे दूसरे राज्यों से आकर कई दिनों से मेहनत कर रहे कारीगर परेशान हैं। उनका कहना है कि दुकानें हटने पर तैयार प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने और बेचने में दिक्कत आएगी, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। कारीगरों के अनुसार, मौसम की परवाह किए बिना वे सुबह से देर रात तक प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं, ताकि उत्सव से पहले ग्राहकों की मांग पूरी हो सके। इस बार प्रतिमाओं में परंपरा के साथ आधुनिकता की झलक भी दिखाई दे रही है। बच्चों के बीच बाल गणेश के अलग-अलग रूप लोकप्रिय हैं, जबकि बड़े आकार की प्रतिमाओं में नए डिजाइन और आकर्षक मुद्राएं देखने को मिल रही हैं।

निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज

उपराज्यपाल की मंजूरी से 2.7 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना लागू होने के बाद राजधानी में पंजीकृत 2.7 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को इलाज के बढ़ते खर्च से आर्थिक सुरक्षा देना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए निर्धारित सीमा तक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्रमिक को दो लाख, परिवार के लिए 10 लाख तक का कवर

योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक वर्ष में दो लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं, एक परिवार के लिए सालाना स्वास्थ्य कवर की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी परिवार के अलग-अलग सदस्यों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्धारित समग्र सीमा 10 लाख रुपये तक होगी। कैशलेस व्यवस्था लागू होने से लाभार्थियों को इलाज के समय तत्काल भुगतान की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ दिल्ली में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलेगा। निर्माण श्रमिकों के लिए यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि काम की प्रकृति के कारण उन्हें दुर्घटना और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उपचार के लिए आर्थिक सहायता और कैशलेस सुविधा परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल ने दी स्वीकृति

दिल्ली बिल्डिंग वर्कर्स हेल्थ स्कीम को उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने से पहले मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब योजना को लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। सरकार का लक्ष्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। योजना के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य कवर की अलग-अलग सीमा तय की गई है, जिससे जरूरत के अनुसार श्रमिक और उनके परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से अस्पताल में उपचार के दौरान भुगतान संबंधी औपचारिकताओं का बोझ कम होगा। 2.7 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों तक योजना का लाभ पहुंचने से निर्माण क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। सरकार की इस पहल को श्रमिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कृष्णानगर में 30 लाख की लूट, आठ घंटे में पुलिस ने दबोचे चार लुटेरे

पूर्वी दिल्ली । कृष्णानगर में कारोबारी से करीब 30 लाख रुपये की लूट के मामले में शाहदरा जिला पुलिस ने आठ घंटे के भीतर दो नाबालिग समेत चार आरोपितों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की रकम में से 19.05 लाख रुपये, वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी, एक देशी पिस्तौल और लूट के पैसों से खरीदे गए तीन नए आईफोन बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, विवेक विहार फेज-2 निवासी कारोबारी संजय जैन करीब 30 लाख रुपये लाल बैग में लेकर गांधी नगर स्थित अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान जा रहे थे। कृष्णानगर के ई-ब्लॉक में पीछे से स्कूटी पर आए चार बदमाश बैग छीनकर विजय चौक की ओर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि एक बदमाश के हाथ पर पट्टी बंधी थी।

वारदात के बाद पुलिस ने इलाके और संभावित भागने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर दीपक, उमंग उर्फ मंगू उर्फ अमन और दो 17 वर्षीय नाबालिगों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, दीपक ने लूट की साजिश रची और नकदी की जानकारी साथियों को दी थी। उमंग के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है।

करावल नगर में 44 वर्षीय पेंटर की पीट-पीटकर हत्या

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अंकुर एन्क्लेव निवासी राजकुमार (44) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करते थे। स्वजन का आरोप है कि बृहस्पतिवार रात तीन-चार लोगों ने राजकुमार के साथ मारपीट की, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई।

परिजनों के मुताबिक, घटना के बाद राजकुमार को गंभीर हालत में पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें राजीव गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्वजन रात में ही शव लेकर घर लौट आए थे। शुक्रवार सुबह परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

◆ **पिटाई करने वालों की तलाश जारी**

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक महिला ने राजकुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी आरोप के बाद कुछ लोगों ने उनकी कथित तौर पर पिटाई की। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह और मारपीट का पूरा क्रम अभी स्पष्ट नहीं है। राजकुमार के परिवार में पत्नी और एक बेटा है। उनके भाई गिरीश कुमार ने भी घटना के संबंध में जानकारी दी है।

गाजियाबाद में बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा ईंधन

गाजियाबाद के 26,384 वाहनों पर संकट, पीयूसीसी बिना ईंधन होगा बंद

एजेंसी, नई दिल्ली

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत जिले में एक अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आपूर्ति पर रोक लगाने की तैयारी है। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी अधूरी दिखाई दे रही हैं। जिले में कुल 26,384 वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है। इनमें 20,193 दोपहिया वाहन और 6,070 कारें शामिल हैं। इसके अलावा 108 ट्रैक्टर, एक एंबुलेंस, एक गुड्स कैरियर और नौ बसों के पास भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है।

जिले में वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कुल 135 पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप हैं। नई व्यवस्था के तहत बिना पीयूसीसी वाले वाहनों की पहचान के लिए सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जाने हैं। लेकिन 10 सितंबर की समयसीमा बीतने के बावजूद अभी तक किसी भी पेट्रोल पंप पर एएनपीआर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में एक अक्टूबर से लागू होने वाली नीति को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जिला पेट्रोल एवं डीजल वितरक एसोसिएशन ने मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर गाजियाबाद में भी एएनपीआर कैमरे परिवहन विभाग की ओर से लगाए जाएं।

एसोसिएशन का कहना है कि कैमरों की व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रिया स्पष्ट होने पर ही नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। प्रशासन के सामने अब कम समय में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कराने की चुनौती है।

नो पीयूसीसी-नो फ्यूल लागू, 26 हजार वाहन निशाने पर।

2.5 लाख में आठ दिन के नवजात का सौदा, पुलिस ने जींद से बचाया मासूम

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तम नगर के हस्तसाल स्थित जेजे कॉलोनी में आठ दिन के नवजात बच्चे को कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है। पड़ोसी महिला की सूचना के बाद उत्तम नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी निगरानी के आधार पर बच्चे को हरियाणा के जींद से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे के पिता जयराम और उसे खरीदने वाली पंजाब के फगवाड़ा निवासी महिला ममता को पकड़ लिया है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

उपायुक्त कुशल पाल सिंह के अनुसार, आठ सितंबर की रात करीब 9:41 बजे बिना देवी नामक महिला ने पीसीआर को सूचना दी कि उसके पड़ोसी के घर जन्मे बच्चे को बेच दिया गया है। सूचना मिलते ही उत्तम नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जयराम दर्जी का काम करता है और उसकी पत्नी गृहिणी है। दंपती के पहले से पांच बच्चे हैं। 28 अगस्त को डाबड़ी मोड़ स्थित दादा देव अस्पताल में उनके छठे बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ था।

◆ **पिता जयराम और खरीदार महिला ममता पुलिस की गिरफ्त में।**

◆ **दाई के जरिए हुई थी नवजात के सौदे की कथित व्यवस्था।**

पूछताछ में जयराम ने पुलिस को बताया कि वह पड़ोस में रहने वाली 72 वर्षीय अनीता को जानता है, जो दाई का काम करती है। आरोप है कि अनीता ने उसे बताया कि नवजात को रखने के इच्छुक व्यक्ति की व्यवस्था की जा सकती है। अनीता पहले पंजाब में रह चुकी थी और फगवाड़ा निवासी ममता को जानती थी। पुलिस के मुताबिक ममता अपने किसी रिश्तेदार के लिए बच्चे की तलाश कर रही थी।

पांच सितंबर को ममता दो अन्य महिलाओं के साथ अनीता के घर पहुंची। वहां जयराम को भी बुलाया गया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान जयराम ने 2.50 लाख रुपये लेकर अपने नवजात बेटे को ममता को सौंप दिया।

जुलाई में भी सामने आया था ऐसा मामला

गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली पुलिस ने नवजात और शिशुओं को निःसंतान दंपतियों को कथित तौर पर अवैध तरीके से बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उस मामले में बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई थी। हालांकि, उत्तम नगर के इस मामले में पुलिस ने अभी किसी संगठित गिरोह से संबंध होने की पुष्टि नहीं की है।

ग्रेटर नोएडा में सजेगा यूपी ट्रेड शो कला से उद्योग तक दिखेगा दमखम

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और औद्योगिक क्षमता की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों के साथ आधुनिक तकनीक और नए उद्योगों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ आम दर्शकों के लिए भी यह आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेगा।

ट्रेड शो में 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना के तहत तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा उद्यमियों और नए स्टार्टअप को भी अपने उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने और उद्यमियों को नए कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

क्यूआर कोड से होगा पंजीकरण

ट्रेड शो में प्रवेश निश्शुल्क रहेगा। दर्शकों को प्रवेश के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। कारोबार से जुड़े आगंतुकों के लिए प्रवेश का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा, जबकि आम दर्शक दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे। आयोजन स्थल पर निश्शुल्क पार्किंग, खुदरा बिक्री और लकी ड्रॉ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिले के उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेड शो प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश की संभावनाओं, नवाचार और उद्यमिता को देश-विदेश के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच है।

आयोजन में रक्षा एवं एयरोस्पेस, वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन, नागरिक विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी विशेष जोर रहेगा। औद्योगिक अवस्थापना परियोजनाओं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, खुदरा कारोबार, ई-कॉमर्स, परिवहन और भंडारण से जुड़े क्षेत्र भी ट्रेड शो का हिस्सा होंगे। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को भी मंच मिलेगा। मत्स्य पालन एवं पशुपालन, औषधि और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों से जुड़े उत्पाद और तकनीक भी यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। हस्तकरघा, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर, खेल सामग्री, खिलौने, शिशु देखभाल से जुड़े उत्पाद, चमड़े के सामान और जूते-चप्पल भी दर्शकों को देखने को मिलेंगे।

तैयारी विदेशी मेहमानों के आगमन से दिल्ली के होटल हुए व्यस्त, तीन हजार कमरे बुक

ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल्ली के होटल हुए फुल

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर विदेशी मेहमानों और वीवीआईपी प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में शामिल होने आ रहे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ प्रतिनिधियों और राजनयिकों के लिए दिल्ली के प्रमुख फाइव-स्टार होटलों में तीन हजार से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। विदेशी मेहमानों के आगमन से शहर के प्रमुख होटलों में रौनक बढ़ गई है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ठहरने के लिए आईटीसी मौर्या को चुना गया है।

सम्मेलन के दौरान होटल में कमरों की भारी मांग के चलते एक रात के कमरे का किराया दो लाख रुपये से अधिक पहुंच गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस में ठहरे हैं। इन होटलों के आसपास सुरक्षा एजेंसियों की विशेष तैनाती की गई है और आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। द ओबेरॉय होटल में ब्राजील, कजाखस्तान, इथियोपिया और इंडोनेशिया के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति के ठहरने की व्यवस्था की गई है।

इसके चलते यहां भी कमरों की उपलब्धता बेहद सीमित हो गई है। ताज महल होटल में उरुग्वे, फिलीपींस, क्यूबा और वियतनाम के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ठहरे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक भी इसी होटल में मौजूद हैं। ले मेरिडियन होटल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के ठहरने की व्यवस्था की गई है।

वीवीआईपी मेहमानों से भरे प्रमुख फाइव-स्टार होटल।

◆ **ब्रिक्स सम्मेलन में वीवीआईपी मेहमानों का होगा जमावड़ा**

अफ्रीकी नेताओं से बढ़ी होटल मांग

वहीं कनॉट प्लेस के समीप स्थित द ललित न्यू दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी सहित कई अफ्रीकी देशों के वरिष्ठ राजनयिक रुके हुए हैं। अशोक रोड स्थित शांगरी-ला इरोस में पश्चिम एशियाई प्रतिनिधिमंडलों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाले शीर्ष नेताओं और सैकड़ों राजनयिकों के आगमन के कारण दिल्ली के इन प्रमुख होटलों में कमरों की मांग काफी बढ़ गई है। सीमित उपलब्धता के बीच होटल कमरों के किराये में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां होटल परिसरों, आसपास के क्षेत्रों और प्रतिनिधिमंडलों के आवागमन वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रख रही हैं।

बारिश ने फिर बढ़ाई हिमाचल की मुश्किलें

भूस्खलन से 67 सड़कें बंद, 142 ट्रांसफार्मर ठप, धर्मशाला में 87.2 मिमी बारिश, मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से धीमे पड़े मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में सबसे अधिक 87.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में भी रात को तेज बारिश हुई और शनिवार सुबह शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 67 सड़कें बंद हैं, जबकि 142 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार धर्मशाला के अलावा कांगड़ा में 68.8, कुफरी में 64.6, शिलारू में 54.6 और जोगिंदरनगर में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। पालमपुर में 40, मलरांव में 45, सराहन में 27.3 और नैना देवी में 22.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कांगड़ा, सुंदरनगर, शिमला, भुंतर, जुब्बड़हट्टी, कुफरी, जोत और मुरारी देवी में गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी सामने आईं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिला बारिश से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 36 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 11, कांगड़ा में 10, जबकि शिमला, सिरमौर और ऊना में तीन-तीन तथा लाहौल-स्पीति में एक सड़क अवरुद्ध है। बिजली आपूर्ति की बात करें तो मंडी के गोहर, जोगिंदरनगर और करसोग में 92 ट्रांसफार्मर, शिमला के रामपुर और कुमारसेन में 34 तथा कुल्लू के निरमंड में 16 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं।

शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 15/20 क्षेत्र में फांचा कंडे के नीचे जंगल का एक हिस्सा धंसने से कई दर्जन देवदार के पेड़ गिर गए। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वहीं, सिरमौर में जलस्तर बढ़ने के बाद गिरि जटोंन डैम से पानी छोड़ा गया और मैदानी क्षेत्रों के लोगों को सतर्क किया गया। मौसम विभाग ने 12 से 18 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश हुई है।

राज्य आपातकालीन केंद्र के अनुसार मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 296 लोगों की मौत और 520 लोग घायल हुए हैं। चार लोग अभी लापता हैं। प्रदेश में 129 घर, 17 दुकानें और 470 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं, जबकि 499 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मानसून से प्रदेश को अब तक 1,661 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

शिक्षकों के लिए तबादला नीति और निश्चित कार्यकाल तय करना जरूरी : रोहित ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना जरूरी है। जब तक शिक्षक का कार्यकाल तय नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाना कठिन होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता अच्छे तथा प्रतिबद्ध शिक्षकों पर निर्भर करती है।

रोहित ठाकुर ने शनिवार को कहा कि चाहे सीबीएसई हो, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हो या अटल और राजीव गांधी आदर्श विद्यालय, हर व्यवस्था में शिक्षकों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होने के साथ उनकी तैनाती और तबादलों में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य शिक्षक लंबे समय तक एक ही स्थान पर सेवाएं दे सकें। इससे छात्रों की पढ़ाई बार-बार शिक्षक बदलने से प्रभावित नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि हर साल नई भर्ती से शिक्षा विभाग में नया और योग्य मानव संसाधन आएगा। उन्होंने हाल में सीबीएसई के माध्यम से की गई शिक्षकों की नियुक्ति को सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना था कि शिक्षकों की भर्ती, तैनाती व कार्यकाल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी।

15 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्र घटे

रोहित ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में लगभग चार लाख की कमी आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें समय के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव न होना भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों को लोगों की बदलती जरूरतों और रोजगार की मांग के अनुसार तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि आने वाले समय में उद्योगों में किन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होंगे। इसके बाद उसी जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन पर हो रहा मंथन

प्राथमिक शिक्षक संघ के आंदोलन को लेकर रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों और सुझावों पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस विषय में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ओर से आने वाले सकारात्मक सुझावों का सरकार स्वागत करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षक का पद समाप्त नहीं किया जाएगा और शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर भी खत्म नहीं होंगे। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार कर रही है।

शिमला में जनता के पैसे से सज रहा शाही दरबार : राजेंद्र राणा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय के खर्च और विभिन्न टेंडरों को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमीर होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि 12.96 करोड़ रुपये का मूल टेंडर बढ़कर 20 करोड़ से अधिक हो चुका है और करीब 40 करोड़ तक पहुंच गया है।

राणा ने सवाल उठाया कि एक ही काम को अलग-अलग टेंडरों में क्यों बांटा जा रहा है। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रिक टेंडर और रिसेप्शन तोड़कर पार्किंग बनाने के लिए दो करोड़ रुपये के अलग टेंडर का भी उल्लेख किया। उन्होंने 15-15 लाख

◆ 12.96 करोड़ का टेंडर 40 करोड़ तक पहुंचने का लगाया आरोप

रुपये की टेबल, पांच-पांच लाख के झूमर और महंगे पर्दों सहित अन्य खर्चों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर एक लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जबकि शिमला में करीब 10 हजार वर्गफुट का आलीशान मुख्यमंत्री कार्यालय तैयार किया जा रहा है। राणा ने इसे सरकार का 'शीशमहल मॉडल' करार देते हुए कहा कि जनता के टैक्स का पैसा फिजूलखर्ची में नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से टेंडरों और भुगतान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।

हिमालय बचाने को जन आंदोलन की जरूरत : राज्यपाल

धर्मशाला में संगोष्ठी में कविंद्र गुप्ता बोले-हिमालय हमारी पहचान, विरासत और जिम्मेदारी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और प्राकृतिक जीवन-व्यवस्था का आधार है। हिमालय हमारी पहचान, विरासत और जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण को केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा, तभी हिमालय संरक्षण के साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल शनिवार को धर्मशाला में हिमालय परिवार, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'हिमालय संरक्षण से राष्ट्र निर्माण की ओर' विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी तथा पुस्तक विमोचन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां देश के विशाल भू-भाग को जीवन प्रदान करती हैं। यहां की जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, लोक संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन

अमूल्य धरोहर हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, जलस्रोतों का संकट, वनाग्नि, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाएं हिमालय की संवेदनशीलता की गंभीर चेतावनी दे रही हैं। ऐसे में विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष के बजाय दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना समय की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने हाल ही में नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हुए वैज्ञानिक अध्ययन, समयबद्ध पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन की तैयारी तथा स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील विकास की दिशा में सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारत का विकास तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण भी सुनिश्चित हो।

राज्यपाल ने हिमालय परिवार की ओर से प्रस्तुत धर्मशाला घोषणा-2026 का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी घोषणा की सफलता केवल उसके दस्तावेज तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से होती है। उन्होंने कहा कि हिमालय संरक्षण की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, विद्यालय, गांव और आसपास के पर्यावरण से कर सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पेड़ों की रक्षा करना, स्थानीय जैव विविधता को समझना, आपदा के समय स्वयंसेवा करना तथा लोक संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ाना ऐसे कदम हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इनमें अशोक बेरी की 'समरस समाज- विकसित भारत का आधार' तथा प्रेम कैथ की 'हैंडबुक ऑन हिमाचल प्रदेश एक्साईज लॉ' प्रमुख हैं। राज्यपाल ने लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि पुस्तकों के माध्यम से समाज में समरसता, राष्ट्र निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा मिलता है।

झंडूता और शाहतलाई भाजपा ने शुरू की 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर झंडूता और शाहतलाई मंडल भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को झंडूता में दोनों मंडलों के अध्यक्ष रसम सिंह चंदेल और डॉ. रामप्रकाश शर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई। विधायक जीतराम कटवाल मुख्य वक्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

बैठक में अभियान की रूपरेखा तैयार करने के साथ मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा का जरिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी सक्रियता से जुटने का आह्वान किया।

विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण संरक्षण और केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा।

17.68 ग्राम हेरोइन मामले में बड़ी कार्रवाई सप्लाई चेन के दो और आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ऊना ने 17.68 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पंजाब से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में दोनों आरोपी अम्ब क्षेत्र में नशे की सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार हाल ही में पुलिस थाना अम्ब के तहत एक घर की तलाशी के दौरान 17.68 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की आगामी जांच के दौरान पुलिस ने बैकवर्ड लिंक खंगालते हुए नशे की सप्लाई के नेटवर्क तक पहुंच बनाई। पुलिस थाना अम्ब की टीम ने 11 सितंबर को पंजाब के होशियारपुर जिले के बरोटी-चोहाल क्षेत्र से नीलम रानी पत्नी तथा स्माइल नाग दोनों निवासी होशियारपुर (पंजाब) को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों आरोपी जिला ऊना, विशेषकर अम्ब क्षेत्र में नशे की सप्लाई के मुख्य स्रोतों से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

पुलिस कप्तान सचिन हीरेमठ ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल नशीले पदार्थ की बरामदगी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे

◆ अंब पुलिस ने होशियारपुर से की गिरफ्तारी, अब तक 5 गिरफ्तार; जांच जारी

के स्रोत, सप्लायर, नेटवर्क और उससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच कर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

बस्सी चौक पर कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा का धरना

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भोरंज की संगठनात्मक बैठक भोरंज बस्सी में दोनों मंडलों के अध्यक्ष अशोक ठाकुर और अभयवीर लवली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की ओर से आगामी दिनों में चलाए जाने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने तथा आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने को लेकर विचार-विमर्श किया।

बैठक में भाजपा जिला सह प्रभारी प्रियव्रत शर्मा, पूर्व विधायक अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष विपिन अग्निहोत्री, चमन कुमार, राज कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता शर्मा और प्रदेश आईटी सह संयोजक जग सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को

◆ भोरंज में संगठनात्मक बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर हुआ मंथन

◆ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने व समस्याएं उठाने पर दिया जोर

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आम जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया गया।

संगठनात्मक बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस्सी चौक पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी समय में भी जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी।

3 .7 किलो चूरा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार

गनोह-राजा का तालाब क्षेत्र में पुलिस को मिली सफलता, मामला दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सी.आई.ए. नूरपुर की टीम ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित रंगे हाथ दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस दौरान आरोपी से 3 किलो 700 ग्राम चूरा पोस्त बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की गई है।

एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि नूरपुर की टीम गश्त एवं नशा विरोधी चेकिंग के दौरान गनोह बाजार व राजा का तालाब क्षेत्र में मौजूद थी। गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी मारुति कार में भारी मात्रा में चूरा पोस्त लेकर राजा का तालाब क्षेत्र में बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने स्वतंत्र साक्षियों

की उपस्थिति में संदिग्ध मारुति 800 कार नम्बर एचपी54ए0157 को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट से पारदर्शी पॉलीथीन बैगों में छिपाकर रखा गया कुल 3 किलो 700 ग्राम चूरा पोस्त (डोडा छिलका/भुक्की) बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान जरनैल सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव ज्योर, डाकघर हरनोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा बरामद मादक पदार्थ एवं अपराध में प्रयुक्त मारुति 800 कार को जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस संदर्भ में आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना रैहन में मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 15 एवं 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में नशे के बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजेस सप्लाई चेन की गहनता से जांच की जा रही है।

एचआरटीसी की बसों के लिए चिन्हित ढाबों में लंच-डिनर के नाम पर लूट

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर से चंडीगढ़-दिल्ली रूट पर चलने वाली एचआरटीसी बसों के यात्रियों को लूटने का खेल बेरोकटोक जारी है। निगम द्वारा चिन्हित किए गए ढाबों पर यात्रियों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। 100 रुपये की थाली 150 से 180 रुपए में बेची जा रही है। शिकायतें लगातार हो रही हैं, लेकिन शिमला से लेकर निचले स्तर तक अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

ताजा मामला घनौली का है। चंडीगढ़ से हमीरपुर आ रही नॉन-स्टॉप बस को दोपहर के समय वहां रोका गया। यात्रियों का आरोप है कि साधारण खाने के भी 180 रुपए वसूल किए गए। विरोध करने पर कुछ यात्रियों को बिल थमा दिया गया, लेकिन उसमें भी हेराफेरी की गई। बिल पर दाल के बदले पनीर की आइटम दर्ज कर दी गई। सबसे गंभीर बात यह है कि ढाबे पर कहीं भी रेट लिस्ट नहीं लगी है।

एचआरटीसी द्वारा तय किए गए दामों की सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई है। न सीसीटीवी है, न ही कोई पारदर्शी व्यवस्था, ताकि यात्री सबूत जुटा सकें। रोजाना यही हाल है, लेकिन कभी भी अधिकारियों ने औचक निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा। यात्री सवाल उठा रहे हैं कि जब बस चंडीगढ़ से हमीरपुर के लिए नॉन-स्टॉप है और कुल सफर 4 घंटे से भी कम है, तो उसे एक घंटे बाद ही आधे घंटे के लिए क्यों रोका जा रहा है?

नेता के दबदबे से खामोश हैं अधिकारी

सूत्रों के मुताबिक जिस ढाबे पर रोजाना यात्रियों से अवैध वसूली हो रही है, वह हिमाचल के एक प्रभावशाली नेता का बताया जा रहा है। इसी राजनीतिक रसूख के चलते बड़े अधिकारी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं।

लिखित शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

हमीरपुर के डिवीजनल मैनेजर राजकुमार पाठक का कहना है कि जिन यात्रियों के साथ ऐसी घटना हुई है, उन्हें लिखित में शिकायत करनी चाहिए। लिखित शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं शिमला हेड ऑफिस में इस मामले को देखने वाले अधिकारी पंकज सिंघल ने बताया कि वह इस बाबत हमीरपुर डीएम से बात करेंगे। इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो ढाबे की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

◆ घनौली में फिर लूटे जा रहे यात्री, 180 रुपए में मिल रही 100 की थाली

660 मेगावाट की इकाई-II ने हासिल किया वाणिज्यिक प्रचालन, परियोजना की कुल क्षमता हुई 1320 मेगावाट

एसजेवीएन की बक्सर पावर प्रोजेक्ट की दूसरी इकाई भी शुरू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। एसजेवीएन की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की इकाई-II (660 मेगावाट) ने 12 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक वाणिज्यिक प्रचालन हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ परियोजना की दोनों इकाइयां अब वाणिज्यिक रूप से संचालित हो गई हैं और कुल 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्रचालन में आ गई है। यह एसजेवीएन की पहली ताप विद्युत परियोजना है, जो पूर्ण रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में आई है।

एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने इस उपलब्धि पर केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युत मंत्रालय तथा अन्य प्रमुख मंत्रालयों और विभागों द्वारा निरंतर प्रदान किए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में योगदान देने वाले एसजेवीएन के कर्मचारियों और सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता, समर्पण एवं दृढ़ता की सराहना की। इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा, निदेशक (वित्त) पार्थजीत डे तथा निदेशक

(परियोजनाएं) राजेश कुमार चंदेल ने भी कर्मचारियों एवं संबंधित हितधारकों को बधाई दी।

बिहार के बक्सर जिले के चौसा में स्थित 1320 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किया था। इसके बाद इकाई-द्ब ने 14 नवंबर 2025 को वाणिज्यिक प्रचालन हासिल किया था। अब दूसरी इकाई के संचालन में आने से परियोजना पूरी तरह कार्यशील हो गई है।

बक्सर ताप विद्युत परियोजना अत्याधुनिक सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है और उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों से सुसज्जित है। परियोजना को जून 2025 के मूल्य स्तर पर संशोधित ₹13,756.56 करोड़ के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर परियोजना से प्रतिवर्ष 9,828.72 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। कुल उत्पादित बिजली में से 85 प्रतिशत बिहार को दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के तहत आवंटित की गई है।

◆ 13,756 करोड़ की परियोजना से बिहार और पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति होगी मजबूतः भूपेंद्र गुप्ता

परियोजना से बिहार और पूर्वी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी तथा पीक आवर्स के दौरान बिजली की कमी कम करने में मदद मिलेगी। निर्माण चरण के दौरान करीब 65,000 श्रमिकों को रोजगार मिला। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी कई पहलें की गईं। परियोजना का पूर्ण संचालन ऊर्जा सुरक्षा के साथ रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगा।

न्यूज ब्रीफ

अंडर-14 बॉक्सिंग में अर्की स्कूल ने जीते 9 पदक

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। बरोटीवाला में आयोजित अंडर-14 जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पीएम श्री एससीवीटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यालय के चार खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और पांच कांस्य पदक हासिल किए। इस प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हेम राज गौड़ ने पदक विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों की सफलता के लिए बॉक्सिंग कोच रमेश पंवार और भारत भूषण के प्रयासों एवं मार्गदर्शन की सराहना की। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन से विद्यालय के खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत कर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

मारपीट और सड़क हादसे के दो मामले दर्ज

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना घुमारवीं के तहत मारपीट और सड़क हादसे के दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में दडयाणा निवासी प्रमिला देवी ने शिकायत दी कि मनीष कुमार, नीजू और सोनू ने उनके परिवार के साथ गाली-गलौज व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरे मामले में पनोह के पास तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पलटकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में चालक अनिल कुमार और सवार रणजीत घायल हुए हैं। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सरवन के परिजनों को मिली 2 लाख की बीमा राशि

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कुटबांगड़ निवासी सरवन कुमार के पीड़ित परिवार को 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाहतलाई शाखा ने औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यह राशि मृतक की पत्नी को सौंपी। कुटबांगड़ निवासी सरवन कुमार पुत्र सुखराम की कुछ समय पूर्व एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। मृतक ने बैंक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपना बीमा करवाया हुआ था। हादसे के बाद परिजनों ने शाखा में जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर क्लेम की प्रक्रिया शुरू की थी। सभी कानूनी व कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लाख रुपये की सहायता राशि जारी कर दी। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक अमन वशिष्ठ ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना की अप्रत्याशित स्थिति में गरीब व जरूरतमंद परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल प्रदान करती है। उन्होंने आमजन से नाममात्र के प्रीमियम वाली इस सरकारी बीमा योजना से जुड़ने की अपील की। इस दौरान बैंक शाखा के अन्य कर्मचारी व स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

पुराने मीटरों की जगह लग रहे स्मार्ट मीटर, अब तक 5118 उपभोक्ता लाभान्वित: रविंद्र

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। विद्युत उपमंडल-2 बिलासपुर के तहत पुराने विद्युत मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य डियारा, रौड़ा, ऋषिकेश तथा चंगर विद्युत अनुभागों में जारी है। सहायक अभियंता विद्युत रविंद्र चौधरी ने बताया कि अब तक उपमंडल में 5118 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बिजली की प्रति यूनिट दर, सब्सिडी और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा कंज्यूमर आईडी भी पूर्ववत रहेगी। मीटर की तेज रीडिंग पर उपभोक्ता बिना शुल्क चेक मीटर लगवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और विभाग को सहयोग देने की अपील की।

मोंगरा ने मटौर में अंडर-19 कांगड़ा जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटौर में तीन दिवसीय अंडर-19 छात्र कांगड़ा जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ एपीएमसी के जिला, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र निशू मोंगरा ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतियोगिता में 33 विद्यालयों के करीब 345 छात्र विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने मुख्य अतिथि, खेल अधिकारियों, शारीरिक शिक्षकों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मोंगरा ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए 21 हजार रुपये तथा स्टेज पर टाइलिंग के लिए 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

ओटीपी न आने पर भड़का उपभोक्ता, सहकारी सभा के विक्रेता पर किया डंडे से हमला

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। दी ख्याह सहकारी सभा समिति के डिपो में शुक्रवार को ओटीपी न आने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि उपभोक्ता नरेंद्र ने विक्रेता संजय शर्मा पर डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान सहकारी सभा के काउंटर और विभागीय वेइंग मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया। विक्रेता ने विभागीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई पॉश मशीनों में सर्वर की समस्या के कारण उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा था। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि शिकायत होने पर विभागीय अधिकारियों या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें और डिपो संचालकों से अभद्र व्यवहार न करें।

हिमाचल के युवाओं और पर्यटन को जापान से जोड़ने की पहल

टोक्यो में मंत्री राजेश धर्माणी ने शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार के नए अवसरों पर किया मंथन

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। तकनीकी, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख आर. मधु सूदन से भेंट की। बैठक में हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों, विशेष रूप से प्रदेश के विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए जापान में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा वैश्विक अवसरों की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। जापान में भारत के उप मिशन प्रमुख आर. मधु सूदन ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों के संदर्भ में भारतीय दूतावास की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। इससे प्रदेश के विद्यार्थियों एवं युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को जापान में बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और शांत वातावरण के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा जी की उपस्थिति ने हिमाचल प्रदेश को वैश्विक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जापान में हिमाचल प्रदेश की पर्यटन क्षमता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर अधिक से अधिक जापानी पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने पर बल दिया। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध एवं आध्यात्मिक विरासत, साहसिक पर्यटन तथा समृद्ध हिमाचली संस्कृति जापानी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन सकती है। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हिमाचल के युवाओं, शिक्षा, कौशल और पर्यटन की संभावनाओं को वैश्विक मंच से जोड़ना है, ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण एवं विकास के नए अवसर सृजित हों और हिमाचल की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत हो सके।

मटौर-टांडा रूट पर 'राइड विद प्राइड' टैक्सी में ओवरलोडिंग से यात्रियों में रोष

आशीष दामीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। मटौर से टांडा अस्पताल की ओर चलने वाली एचआरटीसी की 'राइड विद प्राइड' टैक्सी सेवा में कथित ओवरलोडिंग को लेकर यात्रियों में रोष है। यात्रियों का आरोप है कि वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं और उनसे पूरा किराया वसूला जा रहा है। इसके बावजूद कई यात्रियों को बैठने की सुविधा नहीं मिल रही।

यात्रियों के अनुसार टांडा अस्पताल सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए इस रूट पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। छोटी वैन में अधिक सवारियां भरने से उन्हें असुविधा के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता रहती है। आरोप है कि कुछ यात्रियों ने जब चालक से ओवरलोडिंग को लेकर सवाल किया तो उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई।

◆ **यात्रियों ने क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने का लगाया आरोप**

ओवरलोडिंग पर जल्द होगी कार्रवाई : अजय

एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि ओवरलोडिंग और यात्रियों से बदसलूकी की शिकायत गंभीर है। जांच करवाकर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों ने प्रबंधन से ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

विद्यार्थियों को बैनट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने सिखाई आधुनिक तकनीकें

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। प्रताप वर्ल्ड स्कूल (पीडब्ल्यूएस) पठानकोट में बैनट यूनिवर्सिटी के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए एडवांस्ड एनीमेशन एवं विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका संचालन बैनट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश नारायण अय्यर ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को एनीमेशन, विजुअल स्टोरीटेलिंग और डिजिटल मीडिया में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी।

कार्यशाला में डिजिटल विजुअलाइजेशन, एनीमेशन तकनीक, वीएफएक्स वर्कफ्लो तथा फिल्मों, विज्ञापनों, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट में इनके उपयोग के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञ से सवाल पूछकर विषय की व्यावहारिक जानकारी हासिल की। साथ ही एनीमेशन, वीएफएक्स और तकनीक आधारित क्षेत्रों में बढ़ते करियर अवसरों पर भी चर्चा हुई। स्कूल की प्रिंसिपल सुभ्रा रानी ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं विद्यार्थियों में रचनात्मकता और तकनीकी जागरूकता बढ़ाती हैं। डायरेक्टर सनी महाजन ने कहा कि स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों और भविष्य के कौशल से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

◆ **प्रताप वर्ल्ड स्कूल में एडवांस्ड एनीमेशन एवं वीएफएक्स लगी कार्यशाला**

वॉलीबॉल में प्रताप वर्ल्ड स्कूल ने लहराया परचम

39 स्कूलों के बीच हासिल किया दूसरा स्थान, 3 खिलाड़ी जिला स्तर के लिए चयनित

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा (कांगड़ा)। प्रताप वर्ल्ड स्कूल इंदौरा चनौर के विद्यार्थियों ने घोरन में आयोजित इंदौरा जोनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के 39 विद्यालयों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन, टीम भावना और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में प्रताप वर्ल्ड स्कूल की वॉलीबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, आत्मविश्वास और खेल भावना का परिचय देते हुए कड़े मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि यह रही कि तीन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। विद्यार्थियों के जिला स्तर के लिए चयनित होने से विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है। आयोजित सम्मान समारोह में घोरन विद्यालय की प्रधानाचार्या सुमन लता एवं एसडीएम सुरिंदर ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। विद्यालय की प्रधानाचार्या रेनू परमार एवं एमडी डॉ. ऋचा महाजन ने वॉलीबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों, जिला स्तर के लिए चयनित तीन विद्यार्थियों तथा कोच को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, सहयोग और टीम भावना जैसे गुण विकसित होते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत, लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की सराहना करते हुए कहा कि जोनल स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और तीन विद्यार्थियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होना विद्यालय के लिए गर्व एवं गौरव का विषय है। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस शानदार उपलब्धि पर प्रताप वर्ल्ड स्कूल के समस्त स्टाफ, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने वॉलीबॉल टीम, चयनित विद्यार्थियों और कोच को बधाई दी तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

लॉरेट इंस्टीट्यूट में 'फार्मा विस्टा' फ्रेशर पार्टी का किया आयोजन

वंश ठाकुर मिस्टर, दीपाली चुनी मिस फ्रेशर

भारतेन्दु संवाददाता, ज्वालामुखी। लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में प्रथम वर्ष के नवागंतुक विद्यार्थियों के स्वागत के लिए 'फार्मा विस्टा' फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव रहे, जबकि विशेष अतिथि डीएसपी ज्वालामुखी संजय कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत, सकारात्मक सोच तथा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर प्रबंधक एवं निदेशक डॉ. रण सिंह ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित किया। वहीं निदेशक एवं प्राचार्य डॉ. एमएस अशावत ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के साथ रचनात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. विनय पंडित एवं प्रोफेसर डॉ. सी. पी. एस. वर्मा भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर डॉ. अमरदीप, डॉ. प्रवीन, डॉ. अदिति कौशिक, डॉ. शिव कुमार खुशवा तथा संस्थान के अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम की सराहना की।

फ्रेशर पार्टी के दौरान विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, रैंप वॉक एवं विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न वर्गों में डिप्लोमा से मिस्टर फ्रेशर वंश ठाकुर, मिस फ्रेशर दीपाली, मिस्टर पर्सनैलिटी हर्षल ठाकुर तथा मिस पर्सनैलिटी तेजल भट्ट चुने गए।

एम. फार्म वर्ग में मिस्टर फ्रेशर अंशुल, मिस फ्रेशर शायना, मिस्टर पर्सनैलिटी अक्षत तथा मिस पर्सनैलिटी सपना रहे। फार्म. डी वर्ग में मिस्टर फ्रेशर अक्षय कुमार, मिस फ्रेशर सोम्या कुमार, मिस्टर पर्सनैलिटी जितेश शर्मा तथा मिस पर्सनैलिटी श्रेया राणा चुने गए। इसी प्रकार बी. फार्मेसी वर्ग में मिस्टर फ्रेशर गौरव मेहरा, मिस फ्रेशर आदाशिता, मिस्टर पर्सनैलिटी सूर्यांश ठाकुर तथा मिस पर्सनैलिटी प्रिया को चुना गया। कार्यक्रम उत्साह और उमंग से भरपूर रहा तथा नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए यह आयोजन यादगार बन गया।

◆ **नवागंतुक विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां**

बिलासपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय चिट्टा नेटवर्क किया ध्वस्त

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालने के बाद आईपीएस अधिकारी अभिषेक धीमान के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। पिछले 3-4 महीनों में पुलिस ने चिट्टा (हेरोइन) तस्करी से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर पंजाब और हरियाणा सहित बाहरी राज्यों से जुड़े तस्करों तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस की कार्रवाई से जिले में सक्रिय चिट्टा नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है तथा धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। नशा तस्करी के अलावा चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। रात्रि गश्त और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने से अपराधों में कमी आई है। स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अभियान से जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है।

अंबुजा फाउंडेशन ने तीन स्कूलों की एसएमसी को दिया प्रशिक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को पीएम श्री दारला स्कूल, बरायली स्कूल तथा ड्वारू स्कूल की स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एसएमसी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों, विद्यालय विकास में भूमिका और प्रभावी कार्यप्रणाली की जानकारी देना रहा।

प्रशिक्षण में पीएम श्री दारला स्कूल के एसएमसी चेयरमैन ओम प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य मुनीस कमल, प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक श्रीनिवास, तेजेंद्र सहित तीनों विद्यालयों की एसएमसी के सदस्य उपस्थित रहे। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से मसराम ने प्रशिक्षण दिया, जबकि आरती भी मौजूद रहीं।

प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों को विद्यालय विकास, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ समन्वय, विद्यार्थियों के हित में कार्य करने और विभिन्न गतिविधियों में एसएमसी की सक्रिय भागीदारी को लेकर जानकारी दी गई। सदस्यों ने प्रशिक्षण को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए फाउंडेशन का आभार जताया। एसएमसी चेयरमैन ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से विद्यालय विकास में समितियों की भूमिका और अधिक प्रभावी होगी।

साक्षरता की उड़ान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा हिमाचल

उल्लास मेले में प्रदेश की उपलब्धियों के साथ पहाड़ी नाटी ने भी मोहा मन

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने के अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में आयोजित उल्लास मेला 2026 में प्रदेश की साक्षरता यात्रा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया गया। 8 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया।

इस राष्ट्रीय उपलब्धि में शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, जिला नोडल अधिकारियों, स्वयंसेवी शिक्षकों और नवसाक्षरों के सामूहिक प्रयासों की अहम भूमिका रही। जिला बिलासपुर में असाक्षरों की पहचान से लेकर उन्हें साक्षर बनाने के लिए स्वयंसेवी शिक्षकों की तैयारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में जिला नोडल अधिकारी श्री राकेश कुमार का पिछले तीन वर्षों में विशेष योगदान रहा है। उनके समन्वित प्रयासों से जिले में साक्षरता अभियान को गति मिली और साक्षरता दर 99.5 प्रतिशत तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उल्लास मेले में हिमाचल की टीम ने उल्लास गीत के साथ प्रदेश की प्रसिद्ध पहाड़ी नाटी प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की लावणी, गुजरात के गरबा और झारखंड की लोक संस्कृति के कलाकारों ने भी सामूहिक प्रस्तुतियां दीं। विभिन्न राज्यों की लोक परंपराओं का यह संगम 'विविधता में एकता' का संदेश देता नजर आया। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी राकेश कुमार ने शिक्षा से वंचित लोगों के संघर्ष और शिक्षा पाने की आकांक्षा पर आधारित भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की। उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन की दिशा देने का माध्यम है। कार्यक्रम में वीरेंद्र चौहान, डॉ. देवेंद्र, रवि, शिक्षिका ममता कुमारी, स्वयंसेवी शिक्षक ज्योति, दीपिका सहित नवसाक्षरों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल की उपलब्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन प्रदेश के लिए गौरव का विषय रहा।

उद्घाटन सुनील शर्मा बिट्टू बोले—80 कनाल भूमि को मिलेगी सिंचाई सुविधा, किसानों की बढ़ेगी आय

हरनेड़ में 10.17 लाख की उठाऊ सिंचाई योजना का शुभारंभ

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेड़ में हिम कृषि योजना के तहत लगभग 10.17 लाख रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी गांववासियों को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि इस योजना से गांव की लगभग 80 कनाल भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विशेषकर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाली गेहूं, मक्की, हल्दी और जौ के लिए अलग से उच्च मूल्य घोषित किए हैं। हिमाचल प्रदेश इस तरह की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि इसी योजना के तहत गांव हरनेड़ को प्राकृतिक खेती के लिए आदर्श गांव घोषित किया गया है। इसके लिए सभी गांववासी बधाई के पात्र हैं। गत साढे तीन वर्षों के दौरान जिला हमीरपुर के लिए मंजूर की गई बड़ी परियोजनाओं की चर्चा करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोल सप्पड़ में बन रहे मेडिकल कालेज के नए परिसर में मेडिकल कालेज अस्पताल के अलावा एक अलग मातृ-शिशु अस्पताल, नर्सिंग कालेज, डेंटल कालेज, अलाइड हेल्थ सर्विसेज कालेज, कैंसर केयर संस्थान और अन्य संस्थानों का प्रावधान भी किया है। इससे यह संस्थान उत्तर भारत के बेहतरीन चिकित्सा एवं मेडिकल शिक्षण संस्थानों में शामिल होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा, हैलीपोर्ट और कई अन्य बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं।

सुनील शर्मा बिट्टू ने गांववासियों से मुख्यमंत्री के चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय योगदान देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि गांव के लिंक रोड एवं रास्तों की मरम्मत और पुराने कुएं के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि का प्रावधान करवाया जाएगा।

इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा और आतमा परियोजना हमीरपुर के परियोजना निदेशक राकेश धीमान ने सुनील शर्मा बिट्टू का स्वागत किया तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक खेती में गांव हरनेड़ की उपलब्धियों से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश आनंद, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, गांव के प्रगतिशील किसान ललित कालिया, कृषि विभाग और आतमा परियोजना के अधिकारी, स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधि और अन्य किसान भी उपस्थित थे।

◆ **लिंक रोड और पुराने कुएं के जीर्णोद्धार का भी दिया आश्वासन**

खूबसूरत अंदाज में ओलिविया डन

ओलिविया डन एक अमेरिकी कलात्मक जिम्नास्ट और सोशल मीडिया हस्ती हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। उन्होंने कम उम्र से जिम्नास्टिक में सफलता हासिल की और एलएसयू टीम का हिस्सा रहीं।

यूएस ओपन : ज्वेरेव और शेल्टन में खिताबी भिड़ंत

ज्वेरेव ने खाचानोव और शेल्टन ने हमवतन फ्रांसेस टियाफो को दी शिकस्त

एजेंसी, न्यूयॉर्क

यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के वर्ल्ड नंबर-1 एलेक्जेंडर ज्वेरेव और अमेरिका के बेन शेल्टन आमने-सामने होंगे। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल में ज्वेरेव ने रूस के करेन खाचानोव को 6-3, 7-6, 7-6 से हराया, जबकि शेल्टन ने हमवतन फ्रांसेस टियाफो को 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला जाएगा। खाचानोव ने दूसरे सेट में 0-2 से पिछड़ने के बाद ज्वेरेव ने वापसी की। इसके बाद सेट टाईब्रेकर तक पहुंचा। यहां खाचानोव ने ज्वेरेव के दो सेट पॉइंट बचाए, लेकिन ज्वेरेव ने दबाव बनाए रखा और सेट 7-6 से अपने नाम कर लिया। तीसरे सेट में भी खाचानोव ने टाईब्रेकर में 3-0 और फिर 5-2 की बढ़त बनाई। एक समय लगा कि मुकाबला चौथे सेट में जा सकता है, लेकिन ज्वेरेव ने लगातार पॉइंट्स जीतकर स्कोर बराबर किया और 7-6 से सेट जीत लिया।

ग्रैंड स्लैम मैचों में ज्वेरेव का रिकॉर्ड 24-2 का

इस जीत के साथ इस सीजन ग्रैंड स्लैम मैचों में ज्वेरेव का रिकॉर्ड 24-2 हो गया है। फ्रेंच ओपन में चैंपियन बनने के बाद उन्होंने विंबलडन का फाइनल खेला और अब स् ओपन के खिताबी मुकाबले में पहुंच गए हैं। यह पहली बार है जब ज्वेरेव ने लगातार तीन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है।

शेल्टन 23 साल बाद फाइनल में पहुंचने वाले अमेरिकी खिलाड़ी

बेन शेल्टन 26 साल बाद यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। रविवार को खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह ऑल-अमेरिकन सेमीफाइनल था और दोनों पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। शेल्टन ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उनके पास 2003 में एंडी रोडिक के यूएस ओपन जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष खिलाड़ी बनने का मौका है।

सिनियाकोवा और टाउनसेंड ने जीता यूएस ओपन का महिला युगल खिताब

एजेंसी, न्यूयार्क

शीर्ष वरीयता प्राप्त कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने शुक्रवार को अमेरिकी वाइल्ड कार्ड जोड़ी एशलिन क्रूगर और रॉबिन मोंटगोमरी को हराकर यूएस ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया। सिनियाकोवा और टाउनसेंड ने फाइनल में 5-7, 6-0, 6-2 से जीत दर्ज की और इसके साथ ही टीम के रूप में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इस जीत के साथ सिनियाकोवा के ग्रैंड स्लैम महिला युगल खिताबों की संख्या 12 हो गई। वह दो अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इससे पहले अपनी हमवतन बारबोरा क्रेजिकोवा के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं, टाउनसेंड महिला युगल में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली मौजूदा खिलाड़ियों में छठी खिलाड़ी बन गईं। सिनियाकोवा और टाउनसेंड ने 2024 में विंबलडन, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और इस साल फ्रेंच ओपन का महिला युगल खिताब भी जीता था। फाइनल में सिनियाकोवा और टाउनसेंड ने धीमी शुरुआत की और पहला सेट 5-7 से गंवा दिया। हालांकि दूसरे सेट में दोनों ने शानदार वापसी की। शुरुआती गेम में 40-30 से पिछड़ने के बाद उन्होंने अगले 27 में से 23 अंक जीतकर दूसरा सेट 6-0 से अपने नाम किया और मुकाबले को निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। निर्णायक सेट में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शुरुआती ब्रेक हासिल किया और सिनियाकोवा ने अपनी सर्विस बिना कोई अंक गंवाए बरकरार रखते हुए 3-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद टाउनसेंड ने भी चार अंकों वाला सर्विस गेम जीतकर बढ़त 4-2 कर दी। अंततः दोनों ने निर्णायक सेट 6-2 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।

अमेरिकी जोड़ी एशलिन क्रूगर और रॉबिन मोंटगोमरी को हराया

स्पोर्ट्स विंडो

निशानेबाज भक्ति शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक

एजेंसी, चांगवोन। भारत की भक्ति शर्मा ने डब्ल्यूएसपीएस विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 स्पर्धा के फाइनल में 213.1 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। ईरान की नासरीन शाही समाखौन ने भक्ति को पीछे छोड़कर रजत पदक हासिल किया, जबकि उनकी हमवतन फैजेह अहमदी ने 238.3 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारत की एक अन्य निशानेबाज सृष्टि अरोड़ा भी शामिल थीं, जिन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया। इससे पहले क्वालीफिकेशन में भक्ति छठे स्थान पर रही थीं और सृष्टि से एक स्थान पीछे थीं। हालांकि, 565 अंक के स्कोर के साथ उन्होंने नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सृष्टि ने क्वालीफिकेशन में 566 अंक हासिल किए। भारत की सुमेधा पाठक केवल एक अंक से शीर्ष आठ में जगह बनाने से चूक गईं। वहीं, 2024 पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता रुबीना फ्रांसिस 554 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहीं। भारत ने टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता। सृष्टि, भक्ति और सुमेधा के तीन सर्वश्रेष्ठ स्कोर के संयुक्त 1690 अंक भारत के खाते में रहे। ईरान ने 1707 अंक के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन ने कांस्य पदक हासिल किया।

डुप्लांटिस ने करालिस को पछाड़कर पोल वॉल्ट का खिताब कब्जाया

एजेंसी, बुडापेस्ट। विश्व और ओलंपिक चैंपियन आर्मंड 'मोंडो' डुप्लांटिस ने शुक्रवार को विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट का खिताब अपने नाम किया। डुप्लांटिस ने 6.20 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर ग्रीस के अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी इमैनुअल करालिस को पीछे छोड़ा। अमेरिका में जन्मे स्वीडिश खिलाड़ी डुप्लांटिस चोट की चिंता के बीच हंगरी पहुंचे थे। पैर में खिंचाव दोबारा उभरने के बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर ब्रसेल्स डायमंड लीग फाइनल से नाम वापस ले लिया था। उनकी अनुपस्थिति में करालिस ने वहां खिताब जीता था, लेकिन बुडापेस्ट में डुप्लांटिस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया। खिताबी जीत के बाद डुप्लांटिस ने कहा, 'यह शानदार था। मुझे बुडापेस्ट में प्रतिस्पर्धा करना बहुत पसंद है। पूरा शो शानदार था। आज रात मुकाबला बहुत मजेदार रहा। थोड़ी ठंड थी, लेकिन मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। आप सभी ने जो ऊर्जा दी, उसके लिए धन्यवाद। यह हम सभी के लिए लंबा सत्र रहा है।' बुडापेस्ट के 20 हजार दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में डुप्लांटिस ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। वह दो बार के ओलंपिक और तीन बार के विश्व चैंपियन हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भारत के सामने चयन की दुविधा

एजेंसी, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार को यहां तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत के सामने दुविधा होगी कि 'वंडर ब्वॉय' वैभव सूर्यवंशी को उतारा जाये या संजू सैमसन के अनुभव पर भरोसा किया जाए। सूर्यवंशी को इंग्लैंड में सैमसन की जगह अंतिम एकादश में जगह दी गई थी, लेकिन श्रृंखला के आखिरी मैच में 15 वर्ष के सूर्यवंशी की जगह सैमसन को उतारा गया।

महिला एशिया कप : भारत की नजरें आठवां खिताब जीतने पर

दुबई में आज श्रीलंका से होगा फाइनल मुकाबला

एजेंसी, दुबई

सात बार की चैंपियन भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका के खिलाफ रविवार को महिला टी20 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर आठवीं बार खिताब जीतने पर लगी होंगी ओर इसके लिये शेफाली वर्मा के साथ दीप्ति शर्मा पर काफी दारोमदार रहेगा। दो अर्धशतक समेत 168 रन बना चुकी शेफाली भारत की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुई हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाये हैं । धीमी और स्पिनरों की मददगार दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर भी उन्होंने सहज बल्लेबाजी की है।

स्मृति मंधाना (154) ने एक शानदार शतक लगाया लेकिन दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी । शेफाली के प्रदर्शन में निरंतरता रही है । शेफाली को अपने चिर परिचित स्ट्रोक्स खेलने में भी परेशानी नहीं आई जबकि दूसरे बल्लेबाज जूझते नजर आये हैं। श्रीलंका की कप्तान चामारी अटापट्टू के साथ सर्वाधिक 11 विकेट ले चुकी दीप्ति ने गेंदबाजी के अलावा बल्ले के जौहर भी दिखाये हैं । बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में छह गेंद में 13 रन बनाकर उन्होंने भारत को 150 रन के पास पहुंचाया। दीप्ति के साथ श्री चरणी और प्रेमा रावत ने भी उम्दा स्पिन गेंदबाजी की है और इन तीनों ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाये रखा है।

दोनों टीमें फाइनल तक के सफर में अपराजेय रही हैं और पिछली बार 2024 में भारत को श्रीलंका ने ही फाइनल में आठ विकेट से हराया था। अटापट्टू की टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ जुझारूपन दिखाते हुए सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है।

वेटलिफ्टर ऋषिकांत एशियन गेम्स से बाहर

एजेंसी, नई दिल्ली। एशियन गेम्स से पहले भारतीय दल में बदलाव हुआ है। चोट के कारण वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह बाहर हो गए हैं। वहीं,एथलेटिक्स के शाहनवाज खान और निथ्या गंधे को भी टीम से हटा दिया गया है। ऋषिकांत के हटने से वेटलिफ्टिंग में भारत की पुरुष चुनौती खत्म हो गई है, जबकि एथलेटिक्स टीम अब 74 खिलाड़ियों की रह गई है। ऋषिकांत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट ऋषिकांत सिंह घुटने की चोट के कारण एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे। 60 किग्रा वर्ग के 21 साल के ऋषिकांत को एक महीने के रिहैब की सलाह दी गई है। उन्हें जुलाई में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से एक हफ्ते पहले घुटने में चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल जीता था। उम्मीद थी कि वह एशियन गेम्स तक फिट हो जाएंगे, लेकिन मेडिकल असेसमेंट के बाद उन्हें रिहैब की सलाह दी गई।

द. कोरिया को हराकर जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत

भारतीय टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का करेगी प्रयास

एजेंसी, मोकी

ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ सुप्रिया की शानदार हैट्रिक के दम पर गत चैंपियन भारत ने शनिवार को एएचएफ जूनियर महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और खिताब बचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। भारत की ओर से मधु सिदार ने 13वें मिनट में गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद 17वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर सुप्रिया ने सटीक ड्रैग-फ्लिक के जरिए भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। भारत ने लगातार आक्रामक खेल जारी रखा और 21वें मिनट में सुखवीर कौर ने शानदार फिनिश के साथ टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। मध्यांतर तक भारतीय रक्षापंक्ति ने दक्षिण कोरिया के प्रयासों को नाकाम रखते हुए तीन गोल की बढ़त कायम रखी। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत ने एक बार फिर दबाव बनाया। 33वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर सुप्रिया ने एक और शानदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए अपना दूसरा गोल किया और भारत को 4-0 से आगे कर दिया। दक्षिण कोरिया ने 41वें मिनट में वापसी की कोशिश की। यूरी जियोंग ने सेट पीस पर गोल कर अंतर 4-1 किया और अपनी टीम की वापसी की उम्मीद जगाई। हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बाद रक्षापंक्ति को मजबूत करते हुए कोरियाई टीम को कोई स्पष्ट मौका नहीं दिया। भारत ने अंतिम क्वार्टर में भी आक्रामक रुख बनाए रखा और 56वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। सुप्रिया ने इस मौके को भी गोल में बदलते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत की 5-1 की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी।

जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा नकद भुगतान पर बढ़ा शुल्क

एजेंसी, नई दिल्ली

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना मंगवाने वाले ग्राहकों के लिए अब कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प थोड़ा महंगा हो गया है। खाना ऑर्डर करते समय यदि ग्राहक डिलीवरी के वक्त नकद भुगतान का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें सामान्य भुगतान के मुकाबले अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क बिल की अंतिम राशि में 'पे ऑन डिलीवरी फीस' के नाम से अलग से जोड़ा जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कई ग्राहकों के लिए यह शुल्क पांच रुपये है, जबकि कुछ उपयोगकर्ताओं के बिल में सात रुपये से लेकर 20 रुपये तक की अतिरिक्त राशि दिखाई दे रही है। हालांकि, शुल्क की राशि सभी ग्राहकों के लिए समान नहीं है और यह ऑर्डर या उपयोगकर्ता के अनुसार अलग-अलग दिखाई दे सकती है।

जो ग्राहक यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों से पहले ही ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, उन्हें इस अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। ऐसे में नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए खाने का कुल खर्च बढ़ जाएगा, जबकि ऑनलाइन भुगतान करने वालों पर इस नए शुल्क का असर नहीं पड़ेगा।

खास बात यह है कि जोमैटो का यह नया शुल्क प्लेटफॉर्म फीस, रेस्टोरेंट पैकेजिंग शुल्क, डिलीवरी शुल्क और जीएसटी से अलग है। यानी ग्राहकों को भोजन की कीमत के अलावा पहले से लागू विभिन्न शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है और अब कैश ऑन डिलीवरी चुनने पर अतिरिक्त राशि भी जुड़ सकती है।

एनएसई आईपीओ 17 सितंबर से खुलेगा 22,561 करोड़ रुपए का होगा इश्यू

एजेंसी, हैदराबाद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद एनएसई का मेगा आईपीओ 17 सितंबर से निवेशकों के लिए खुलेगा। निवेशक 21 सितंबर 2026 तक इसमें पैसा लगा सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 1,700 से 1,785 रुपये का मूल्य दायरा तय किया है। इस इश्यू का कुल आकार 22,561.57 करोड़ रुपये है। पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के रूप में है, इसलिए इससे मिलने वाली राशि सीधे मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी। आईपीओ में खुदरा निवेशकों के लिए एक लॉट में आठ शेयर रखे गए हैं। ऊपरी मूल्य दायरे के हिसाब से निवेशकों को एक लॉट के लिए न्यूनतम 14,280 रुपये लगाने होंगे। इश्यू में 35 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों, 50 प्रतिशत योग्य संस्थागत खरीदारों और 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। आईपीओ बंद होने के बाद 22 सितंबर को शेयरों का आवंटन तय किया जाएगा। सफल निवेशकों के डीमैट खातों में 23 सितंबर तक शेयर जमा होने की उम्मीद है। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को एनएसई के शेयरों की बाजार में ट्रेडिंग शुरू होगी। भारतीय कानूनों के तहत कोई स्टॉक एक्सचेंज अपने ही प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं हो सकता, इसलिए एनएसई के शेयरों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होगी।

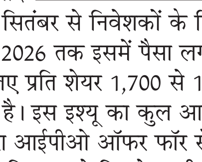

अदाणी पावर के गोड्डा प्लांट की यूनिट बंद, बांग्लादेश में गहराया बिजली संकट

एजेंसी, नई दिल्ली

बांग्लादेश पहले से ही गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है और अब झारखंड स्थित अदाणी पावर के गोड्डा पावर प्लांट की एक इकाई में तकनीकी खराबी आने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 1,600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा पावर प्लांट की दो इकाइयों में से 800 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई बंद हो गई है। इसका सीधा असर बांग्लादेश को होने वाली बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। बिजली उत्पादन में अचानक कमी आने के कारण वहां लोड शेडिंग की स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश बीते कुछ महीनों से बिजली की कमी से जूझ रहा है और राजधानी ढाका समेत आसपास के क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है।

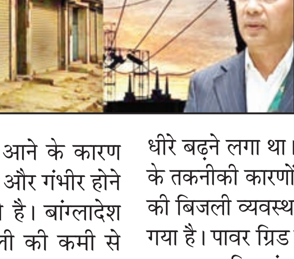

जानकारी के अनुसार गोड्डा प्लांट की 800 मेगावाट क्षमता वाली इकाई गुरुवार आधी रात के आसपास बॉयलर में तकनीकी खराबी आने के बाद बंद हुई। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब प्लांट में कुछ सप्ताह तक कम उत्पादन रहने के बाद बिजली उत्पादन में सुधार शुरू हुआ था। कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण गोड्डा प्लांट अगस्त के मध्य से कम क्षमता पर काम कर रहा था। बाद में परिस्थितियों में सुधार होने पर उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। ऐसे समय में एक इकाई के तकनीकी कारणों से बंद होने से बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया है। पावर ग्रिड बांग्लादेश के आंकड़ों के अनुसार, यूनिट बंद होने से पहले गुरुवार रात गोड्डा प्लांट से बिजली उत्पादन 1,400 मेगावाट से अधिक हो गया था।

कर्ज चुकाने के लिए टाटा संस में 7% हिस्सेदारी बेचेगा शापूरजी पलोनजी ग्रुप

एजेंसी, नई दिल्ली

कर्ज के भारी बोझ से जूझ रहे शापूरजी पलोनजी (एसपी) ग्रुप ने अपनी वित्तीय देनदारियां कम करने के लिए टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, समूह अगले दो वर्षों में टाटा संस की करीब सात प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। इस संबंध में एसपी ग्रुप के चेयरमैन शापूर मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर टाटा संस के स्तर पर चर्चा होने की संभावना है।

एसपी ग्रुप के पास टाटा संस में करीब 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी लंबे समय से समूह की वित्तीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अब कर्ज का दबाव बढ़ने के कारण समूह इसके एक हिस्से को बेचकर बड़ी रकम जुटाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बिक्री से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज चुकाने और वित्तीय दबाव कम करने में किया जा सकता है।

25 हजार करोड़ जुटाने की तैयारी, नोएल टाटा को शापूर का पत्र

एसपी ग्रुप के सामने तत्काल वित्तीय चुनौती भी है। रिपोर्ट के अनुसार, समूह को सितंबर 2026 में करीब 3500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण अदायगी करनी है। समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में इसे डिफॉल्ट माना जा सकता है। समूह पर कुल कर्ज 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। इसमें टाटा संस में उसकी हिस्सेदारी के बदले लिया गया कर्ज भी शामिल है। ऐसे में हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाना समूह के लिए वित्तीय दबाव कम करने का अहम विकल्प माना जा रहा है। शापूर मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को टाटा संस में हिस्सेदारी बेचने से संबंधित प्रस्ताव भेजा है।

तेलसंकट ड्रोन हमलों के बाद सऊदी ने रोकी तेल सप्लाई, वैश्विक बाजार में बढ़ी ईंधन संकट की चिंता

सऊदी अरब ने बंद की 50 लाख बैरल रोजाना वाली तेल पाइपलाइन

एजेंसी, नई दिल्ली

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता और बढ़ गई है। सऊदी अरब ने अपनी महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस पाइपलाइन के माध्यम से हाल के महीनों में रोजाना करीब 40 लाख से 50 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की जा रही थी। यह मात्रा वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग चार से पांच प्रतिशत बताई जा रही है। ऐसे में पहले से दबाव में चल रही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सऊदी के इस कदम का अतिरिक्त असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सऊदी अरब की करीब 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन देश के तेल परिवहन ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जरिये सऊदी अरब अपने तेल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर हुए बिना देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस पाइपलाइन को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध तथा बढ़ते तनाव के कारण गंभीर दबाव में है। इस रास्ते से तेल टैंकरों की आवाजाही में कमी आई है और वैश्विक बाजार में आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी हुई है।

ऐसे समय में सऊदी की एक प्रमुख वैकल्पिक तेल परिवहन व्यवस्था का अस्थायी रूप से बंद होना बाजार के लिए नई चिंता लेकर आया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, पाइपलाइन को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ड्रोन हमलों को देखते हुए लिया गया है।

आपूर्ति मार्गों पर बढ़ा जोखिम

वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के साथ तेल आपूर्ति के सामने कई स्तरों पर जोखिम पैदा हो रहे हैं। एक ओर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की पाइपलाइन को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। इससे तेल बाजार में उपलब्ध आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। बाजार में किसी भी प्रमुख आपूर्ति मार्ग के बाधित होने की स्थिति में कीमतों में तेजी आने की संभावना रहती है। मौजूदा हालात में निवेशक और तेल बाजार से जुड़े कारोबारी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।